हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक सोमवार, दिनांक 19 फरवरी, 2024 को माननीय अध्यक्ष, श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 02.00 बजे अपराह्न आरम्भ हुई।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

19-02-2024/1400/वाई.के.-एन.जी/1

अध्यक्ष : आज की कार्यवाही में आप सभी का स्वागत है। प्रश्न काल आरम्भ। Postponed Questions for the day.

प्रश्न संख्या - 1085 (स्थगित)

डॉ0 जनक राज : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न पिछले सत्र से स्थगित किया गया है और करूणामूलक नौकरी प्राप्त करने के लिए प्रदेश सरकार के पास आए आवेदनों से संबंधित है। इससे सरकार की गम्भीरता का पता चलता है कि एक साधारण से प्रश्न के जवाब में उत्तर दिया जा रहा है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार द्वारा इस प्रकार से एक हल्का सा जवाब देकर माननीय सदन को और प्रदेश की जनता को गुमराह किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि यह सूचना हमें कब तक प्राप्त हो जाएगी?

उद्योग मंत्री (प्राधिकृत) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न पिछले विंटर सेशन में पूछा गया था और उसे बीते हुए अभी केवल 2 माह का ही समय हुआ है। It involves every department. जैसे ही **सभी विभागों, बोर्डों, निगमों और अन्य सभी संस्थानों से सूचना प्राप्त होगी वैसे ही माननीय सदस्य को उपलब्ध करवा दी जाएगी। हम कोशिश करेंगे कि इस सत्र के समाप्त होने से पहले ही इस कार्य को पूर्ण कर लिया जाए।**

श्री राजेन्द्र राणा : अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि अभी इसका जवाब नहीं आया है। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह कोई बहुत बड़ी सूचना नहीं है। इसमें हमने पूछा है कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने करूणामूलक आधार पर नौकरी प्राप्त करने के लिए औपचारिकताओं को पूर्ण कर लिया है व कितने लोग नौकरी पाने के लिए पात्रता रखते हैं? इसके अलावा मैं बताना चाहता हूं कि मेरे पास सूचना आई है और उनके नाम-पते भी मेरे पास हैं कि इसमें से कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो अनाथ हैं तथा करूणामूलक आधार पर नौकरी पाना चाहते हैं।

19-02-2024/1400/वाई.के.-एन.जी/2

सरकार द्वारा सुख आश्रय योजना चलाई गई है तो क्या सरकार ऐसे बच्चों को प्रथामिकता के आधार पर नौकरी देने की इच्छाशक्ति रखती है? जब हम लोग विपक्ष में होते थे तब हम सरकार से इनके मामले को उठाते थे और ये लोग भी उस समय लगातार धरने पर बैठे हुए थे। प्रदेश में आज 5000 से भी अधिक ऐसे नौजवान हैं जिन्हें करूणामूलक आधार पर नौकरी मिलनी शेष है। मेरा केवल इतना कहना है कि विभिन्न विभागों में हज़ारों पद रिक्त पड़े हुए हैं तो इन नौजवानों को उन पदों के अगेंस्ट एडजस्ट किया जाना चाहिए। इनमें से ऐसे बहुत से नौजवान हैं जिनके माता-पिता इस दुनिया से चले गए हैं और उनकी आमदनी का कोई भी साधन नहीं बचा है। ऐसे लोगों को तो वैसे भी मानवता के आधार पर नौकरी मिलनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार इनके विषय में क्या प्लान कर रही है और इन्हें कब तक नौकरी मिलेगी?

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, it is a very important issue. The Government is very serious about it, क्योंकि बहुत सारे केसिज़ ऐसे हैं जोकि 8-10 सालों से लम्बित पड़े हुए हैं। यह विषय विभिन्न विभागों से संबंधित है और कुछ विभागों ने तो अपना जवाब दे दिया है लेकिन कुछ विभागों से अभी तक जवाब नहीं आया है। जैसा मैंने अभी कहा है कि the Government is very serious और हमने कहा है कि हम इसे करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि इसी सत्र के दौरान इसका जवाब तैयार कर दिया जाए। यदि इस सत्र में जवाब तैयार हो गया तो it will be listed again नहीं होगा तो अगले सत्र में आ जाएगा। We will do it. Now, this is for the Hon'ble Chief Minister to decide that what is the policy.

श्रीमती के.एस. द्वारा जारी.....

19.02.2024/1405/केएस/वाईके/1

प्रश्न संख्या : 1085 जारी...

पॉलिसी का तो आपको पता ही है मगर राणा जी ने जो अनाथ बच्चे हैं, जिनका कोई नहीं है, के बारे में पूछा तो **सरकार ऐसे केसिज़ को प्राथमिकता के आधार पर जल्दी ही प्रोसैस करेगी।**

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी की हमारी पिछली सरकार के द्वौरान करुणामूलक आधार पर बच्चों को रोज़गार मिलना चाहिए, इस दृष्टि से हमने अनेक कदम उठाए। 50 साल की उम्र को बढ़ाकर हमने कहा कि रिटायरमेंट के अंतिम दिन तक अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रित करुणामूलक आधार पर नौकरी पाने के लिए पात्र होंगे। हमने उसमें अन्य चीज़ों का भी प्रावधान किया था। बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश में हमने ऐसे पात्र लोगों को नौकरियां दीं। हिमाचल के इतिहास में करुणामूलक आधार पर सबसे ज्यादा नौकरियां हमारी सरकार ने दीं। इस प्रश्न का पिछले सत्र के दौरान भी यही जवाब आया था कि सूचना एकत्रित की जा रही है और अब भी सूचना एकत्रित करने की बात की जा रही है। जब आपसे सूचना ही एकत्रित नहीं हो रही है तो नौकरी देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता । ये ऐसे लोग हैं जिनको नौकरी की बहुत आवश्यकता है। आप ही लोग थे जब हमारी सरकार के दौरान वे लोग धरने पर बैठे थे, हम उनकी मदद कर रहे थे लेकिन इसके बावजूद भी वे कुछ इशूज़ को ले कर धरने पर बैठे रहे, आप भी उनके साथ धरने पर बैठ गए थे। आपकी संवेदनहीनता इस बात को दर्शाती है कि आज आप उस प्रश्न का उत्तर देने से ही कतरा रहे हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आप इस प्रश्न का उत्तर जो माननीय सदस्य डॉ0 जनक राज जी ने पूछा है, इसी सत्र में सुनिश्चित करेंगे? दूसरे, जो आपने वायदा किया था कि हम उन सभी को रोज़गार देंगे जो करुणामूलक आधार पर नौकरी के पात्र हैं तो उनको कब तक नौकरी दे देंगे? पहला प्रश्न मैंने किया कि आप उसका जवाब कब तक देंगे और दूसरा पूछा कि उनको नौकरी कब तक दे देंगे?

19.02.2024/1405/केएस/वाईके/2

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कहा कि हमारी कोशिश रहेगी कि इसका इसी सत्र के दौरान जवाब आ जाए। क्योंकि बहुत सारे विभागों ने उत्तर दे दिया है और बहुत से विभागों से उत्तर अभी नहीं आया है। बोड्र्ज़ और कॉर्पोरेशन्ज़ भी हैं,उनसे भी जवाब मांगा गया है और उनमें भी कुछ ने जवाब दे दिया है और कुछ ने नहीं दिया है। क्योंकि इसमें बहुत से विभाग इन्वॉल्व्ड हैं और कई केसिज़ तो 10-12 साल वाले भी पैंडिंग पड़े हैं। **कोशिश रहेगी कि इसी सत्र में जवाब आ जाए** और दूसरी बात जो माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कही, इसमें एक केबिनैट सब कमेटी बनाई गई है जिसमें जो मॉडलिटीज़ हैं, किसमें क्या चेंज करना है, इन्कम क्राइटेरिया जो अभी सवा दो लाख रुपये के लगभग एनुअल है,उसको बढ़ाया जाए या क्या किया जाए, कमेटी यह देखेगी। अध्यक्ष जी, पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में भी इस मामले को बहुत लटकाया गया था और जो आपने नौकरियां दी हैं वह बहुत सारी डेली पेड पर नौकरियां दी हैं। ...(व्यवधान) मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं कि वैसे तो करुणामूलक आधार पर रैगुलर नौकरी दी जाती थी मगर पूर्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डेली वेजिज़ पर आई.पी.एच. और पी.डब्ल्यू.डी. में ऑफर की हैं। कुछ लोगों ने ज्वाइन किया कुछ ने नहीं किया। ये सारे इशूज़ कि रैगुलर देनी हैं, कांट्रैक्ट पर देनी हैं या जो आपने डेली वेजिज़ दी हैं, उनको करना है, ये सारे के सारे इशूज़ सरकार के विधाराधीन हैं। उसी के अनुसार सरकार, मुख्य मंत्री जी और केबिनैट उसमें जल्दी ही डिसिज़न लेगी। धन्यवाद।

प्रश्न समाप्त

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी----

19.02.2024/1410/एवी/एजी/1

प्रश्न संख्या : 1336

श्री केवल सिंह पठानिया : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने पीछे ठेकों की नीलामी करके उस पर मिल्क सैस लगाया है। लिखित जानकारी में बताया गया है कि मिल्क सैस के रूप में

90,77,99,232.00 रुपये एकत्रित किए गए। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार एक्साइज के अंतर्गत लक्षित कुल 2350.81 करोड़ रुपये के राजस्व को कहां खर्च करेगी? सरकार ने जो पिछले साल शराब के ठेके नीलाम किए हैं क्या सरकार आगामी वित्तीय वर्ष में उनको दोबारा से नीलाम करेगी?

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मिल्क सैस 10 रुपये प्रति बोतल लगाया गया है। इसमें अभी तक 90,77,99,232.00 रुपये की राशि आ चुकी है और यह उम्मीद की जा सकती है कि इस वित्तीय वर्ष के अंत तक यह आंकड़ा लगभग 100 करोड़ रुपये को टच कर जाएगा। इस पैसे को मिल्क के विकास के लिए किसानों को दिया जाएगा यानी इसको गंगा योजना के तहत यूज़ किया जाएगा। इससे जो राजस्व प्राप्त होगा उससे चिलिंग प्लांट्स और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने में लगाया जाएगा। पहले शराब के ठेकों की ऑक्शन रिन्यू करके होती थी जिससे केवल 10-12 प्रतिशत ही राजस्व बढ़ता था। लेकिन हमारी सरकार ने मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में फैसला लिया और पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में चल रही प्रणाली को बदलकर ठेके ऑक्शन किए गए। प्रणाली में बदलाव करने से राजस्व में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसमें नीलामी के लिए रिज़र्व प्राइस 1446 करोड़ रुपये रखी थी जिसके अगेंस्ट सरकार को 1815 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई यानी इसमें 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसमें अधिकतर पैसा वापिस सरकार को आया है और अगले वित्तीय वर्ष में सरकार क्या करेगी it is for the Chief Minister and the Cabinet to decide, **उस समय के मुताबिक आगे का फैसला लिया जाएगा।**

समाप्त

19.02.2024/1410/एवी/एजी/2

प्रश्न संख्या : 1337

श्री बलबीर सिंह वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरे दो प्रश्नों को एक ही प्रश्न में डाल दिया गया है जबकि इसमें एक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और दूसरा होर्टिकल्चर मिशन के अंतर्गत आई सिंचाई योजनाओं के बारे में था। ये दोनों विभाग भी अलग-अलग है परंतु इन दोनों को इकट्ठा मिला दिया गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत मेरे चुनाव क्षेत्र में 79 योजनाएं स्वीकृति हुई हैं और स्वायल कंज़र्वेशन ने डेढ़-डेढ़ करोड़ रुपये के टेण्डर लगाए।

टी **सी द्वारा जारी**

19.02.2024/1415/टी0सी0वी0/ए0जी0-1
प्रश्न संख्या 1337 .... क्रमागत्
श्री बलबीर सिंह वर्मा..... जारी

और जो स्वॉयल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट हैं उन्होंने 1.50-1.50 करोड़ रुपये के टेंडर लगाए लेकिन ग्राउंड लैवल पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र में 9 करोड़ रुपया कंजर्वेशन डिपार्टमेंट ने खर्च किया है। मेरा सुझाव है कि प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना की जितनी भी बड़ी स्कीमें हैं वे सारी जल शक्ति विभाग को दे दी जाए। स्वॉयल कंजर्वेशन को जो स्कीमें दी गई हैं उनमें कोई स्कीम 80 लाख, एक करोड़ या डेढ़ करोड़ रुपये की है। इनके पास इतना स्टाफ नहीं है कि वे इन स्कीमों को प्रोपरली देख सके। मेरा आपसे आग्रह है कि स्वॉयल कंजर्वेशन में विशेष तौर पर जो बजट सिंचाई के लिए आ रहा है उसको जल शक्ति विभाग में डाला जाए ताकि वहां पर उसकी क्वालिटी प्रोपरली चैक की जाए और इन स्कीमों की प्रोपरली इम्प्लीमेंटेशन भी होगी क्योंकि स्वॉयल कंजर्वेशन में जितना बजट आता है उससे न वह टैंक मिलता है और न ही उस स्कीम का कोई पता होता है। यह मैं पिछले 8-10 सालों से देख रहा हूं।

कृषि मंत्री, प्राधिकृत : अध्यक्ष महोदय, राज्य में स्वॉयल कंजर्वेशन के जितने भी डिवीजन है उनके पास कोई ज्यादा पैसा नहीं होता है। जल शक्ति विभाग के पास मिडियम और

बड़ी स्कीमें होती है। लेकिन स्वॉयल कंजर्वेशन डिर्पाटमेंट के पास छोटी-छोटी स्कीमें होती है, जैसे कई लोग टैंकों में पानी स्टोर करके उससे इरिगेशन करते हैं। आपका सुझाव है कि इन स्कीमों को जल शक्ति विभाग में ट्रांसफर कर दिया जाए लेकिन जल शक्ति विभाग के पास बड़ी स्कीमें होती है और इन छोटी स्कीमों की ओर उनका कोई ध्यान नहीं होता है। इरिगेशन के लिए एग्रीकल्चर में जो पैसा आता है वह लघु स्कीमों के लिए आता है जिस तरह से उसका नाम प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना लेकिन यदि इसके पैसे का एलोकेशन देखें तो किसी सब-डिवीजन मे 15 लाख रुपया, किसी में 10 लाख रुपया और किसी में 5-6 विधान सभा क्षेत्रों का एक करोड़ रुपया होगा। इसलिए यह जल शक्ति विभाग के लिए फिजिबल नहीं है। जहां

तक आपके क्षेत्र की योजनाओं का सवाल है। आपने कहा कि प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना और बागवानी में अलग-अलग योजनाएं है। आपके विधान सभा क्षेत्र में 8 स्कीमें बागवानी विभाग के पास हैं, 2 कम्युनिटी सिंचाई योजनाएं हैं और लगभग 69 योजनाएं लोगों की निजी योजनाएं हैं। मेरे पास भी जल शक्ति विभाग रहा है। आपको दो मध्यम सिंचाई स्कीमें 90:10 के अनुपात में दी गई थी, वे रिकॉर्ड समय में नहीं बनी। उनका डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम आज तक नहीं मिला है। मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र की स्कीम का डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम भी नहीं चला। फिना सिंह और शाहनहर स्कीमें पूरी नहीं हुई जबकि उनके लिए भारत सरकार से 60:40 के अनुपात में पैसा मिलता था। जल शक्ति विभाग की अपनी स्कीमों के रिजल्ट भी अच्छे नहीं आ रहे हैं। मैं स्वयं इस विभाग में रहा हूं और उस समय हमने बहुत-सारी लघु स्कीमें नार्बाड और भारत सरकार से ली। भारत सरकार उस समय 90 प्रतिशत अनुदान और 10 प्रतिशत लोन पर स्कीमें देती थी लेकिन वह भी हमने नहीं भरा। फिर भी वे स्कीमें रिकॉर्ड टाइम में पूरी नहीं हुई । वे सारी डिफंक्ट स्कीमें बनी हुई है। अभी भी खेतों तक पानी नहीं पहुंचा है। यह मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। अब जाकर जायका के माध्यम से पानी को खेतों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।

एन0एस0 द्वारा जारी ।

19-02-2024/1420/एन0एस-ए0एस0/1

प्रश्न संख्या : 1337 ------ क्रमागत

कृषि मंत्री ------जारी

यह मेरा प्रेक्टिकल अनुभव है। इसलिए ये बड़ी-बड़ी माइनिंग वाली इंडिविज्युअल स्कीम्ज हैं। इसमें तो पैसा ही बहुत कम है। आज भी सॉयल कंजरवेशन के जितने भी डिवीजन्ज हैं उनमें एवरेज पैसा बहुत कम है। कहीं पर 5 लाख रुपये कहीं पर 3 लाख रुपये हैं। वे खुद जिलाधीश से पैसा मांगते हैं। ये इक्नोमिकल ही नहीं है कि हम जल शक्ति विभाग को पैसा दे दें। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यही है।

अध्यक्ष : मंत्री जी ने बड़ा एग्जॉस्टिव रिप्लाई दिया है। आप जो बोल रहे थे तो दोनों विभाग अलग हैं। एग्रीकल्चर विभाग अलग है और होर्टिकल्चर विभाग अलग है। इसके मंत्रालय अलग हैं और जवाब भी अलग-अलग आता है। इसलिए सेग्रीगेट किया गया है और आगे इसका जवाब आया है तथा आपके नाम से प्रश्न लगा है। Anyway, what do want to ask now?

श्री बलबीर सिंह वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं। इसमें बड़ी स्कीमें 1.50 करोड़ रुपये, 86 लाख रुपये, 1 करोड़ रुपये, 1.37 करोड़ रुपये, 90 लाख रुपये और 1.10 करोड़ रुपये की भी हैं। इसमें आगे दिखाया गया है। मेरा आपसे निवेदन है कि जिस भी विभाग से करवाएं लेकिन इसको प्रोपरली चैक करने वाला विंग हो कि ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। मेरी विनती है कि चौपाल में जितनी भी स्कीमें हैं क्या आप इनको चैक करवाने के लिए किसी की ड्यूटी लगाएंगे? ये स्कीमें इंप्लीमेंट नहीं हो रही हैं।

कृषि मंत्री : सॉयल कंजरवेशन और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग भी हैं और उनके पास जे0ई0 भी लगे हुए हैं। इसका सर्वे जे0ई0 करते हैं। फिर भी उसमें आपको संदेह है कि क्वालिटी ऑफ वर्क ठीक नहीं हो रहा है तो इसकी पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे कि इनके किस प्रकार के रिजल्ट हैं। आपके सुझाव के ऊपर पूरी गौर करेंगे।

19-02-2024/1420/एन0एस-ए0एस0/2

प्रश्न संख्या : 1338

श्री सतपाल सिंह सत्ती : अध्यक्ष महोदय, जो मैंने प्रश्न पूछा है उसके अनुसार अगर आयुर्वैद विभाग में नीट के माध्यम से डॉक्टरों की सलैक्शन होती है और किसी कारणवश सरकारी मेडिकल कॉलेजिज में उनका नम्बर नहीं आता है लेकिन प्राइवेट कॉलेजिज में उनका नम्बर सरकारी कोटे में आता है। सरकार के माध्यम से जो नीट का टैस्ट लिया गया है तो उसके माध्यम से जब वे आयुर्वैद की पढ़ाई करने के लिए सरकारी क्षेत्र में जाते हैं तो उसमें यह देखा गया है कि जब प्रशिक्षु इटर्नशिप में जाते हैं और सरकारी अस्पतालों में जिनको एडमिशन मिलता है तो उनको वजीफा मिलता है। जब वही व्यक्ति मेरिट में आकर प्राइवेट होस्पिटल में जाते हैं तो उनको वजीफा नहीं मिलता है। मेरा मंत्री महोदय से प्रश्न है कि एक ही टैस्ट के माध्यम से जो सलैक्शन होती लेकिन प्राइवेट कॉलेजिज में जाते हैं और सरकारी क्षेत्र में यानी आयुर्वैद अस्पताल, सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों या उप-स्वास्थ्य केंद्रों में इटर्नशिप करते हैं तो उस समय उनको वजीफा नहीं दिया जाता है। इनके साथ भेदभाव हो रहा है। क्या सरकार आने वाले समय में इस भेदभाव को समाप्त करके एक तरह का पैटर्न करने का विचार रखती है? मेरा निवेदन रहेगा कि इस क्षेत्र के जो प्रशिक्षु हैं उन लोगों को भी सरकारी प्रशिक्षुओं की तरह वजीफा दिया जाना चाहिए।

आयुष मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना माननीय सदस्य ने मांगी है मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा कि भारतीय चिकित्सा पद्धति के जो नियम हैं वे राष्ट्रीय आयोग एन0सी0आई0एस0एम0 आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जो मापदंड हैं उनके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। प्रदेश में एक इकलौता सरकारी आयुर्वैदिक संस्थान, पपरोला में है।

आर0के0एस0 द्वारा ------जारी

19.02.2024/1425/RKS/AS-1

प्रश्न संख्या:1338... जारी

आयुष मंत्री...जारी

जिसमें 75 पोस्टें बी.एम.एस. और 56 पोस्टें पोस्ट ग्रेजुएशन की हैं। राष्ट्रीय आयोग द्वारा जो मापदंड निर्धारित किए गए हैं उनके अनुसार यह आवश्यक है कि जो गवर्नमेंट कॉलेज के माध्यम से इंटर्नशिप करेंगे उनको वजीफे के तौर पर 10,000 रुपये देने बाध्य हैं लेकिन प्राइवेट संस्थानों में ये मापदंड लागू नहीं होते। अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन्ज अपने स्तर पर वजीफा देना चाहें तो वे दे सकते हैं। इसके नियमों में जो बदलाव की आवश्यकता है उसके लिए हम राष्ट्रीय आयोग से बात करेंगे। हम आने वाले समय में यह गुजारिश करेंगे कि जो मापदंड सरकारी संस्थानों में हैं उन्हें प्राइवेट इंस्टीट्यूशन्ज में भी लागू किया जाए।

श्री विपिन सिंह परमार : अध्यक्ष महोदय, आयुष मंत्री जी पहली बार इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। यह विषय वजीफे को लेकर ही नहीं है। आप आयुष मंत्री है लेकिन यह प्रस्तावना हमारी सरकार द्वारा शुरू की गई थी। हमने पपरोला के आयुर्वेदिक संस्थान को अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान का दर्जा दिए जाने तथा जोगिन्द्रननगर एवं बैजनाथ फार्मेसिज को क्लब करने की सारी औपचारिकताएं पूरी की थीं। अगर आपके पास इनकी जानकारी है तो आप कृपया करके हमें इसके बारे में बताएं। मैं जानना चाहूंगा कि वर्तमान सरकार इस विषय को लेकर कहां तक सफल हो पाई है? दूसरा, हिमाचल प्रदेश के बहुत से ए.एस.सीज., पैरा-मेडिकल स्टाफ के कारण खाली पड़े हैं। मैं जानना चाहूंगा कि इन पदों को भरने के लिए विभाग द्वारा क्या योजना बनाई जा रही है? ये दो महत्वपूर्ण सामयकि विषय हैं इसलिए मैं इनका उतर जानना चाहूंगा।

19.02.2024/1425/RKS/AS-2

आयुष मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न इस प्रश्न से कोई तालमेल नहीं खाते हैं लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि पूर्व सरकार के समय इसका प्रपोजल केंद्र सरकार को प्रेषित किया गया था। हमारी सरकार के समय मुझसे पूर्व श्री हर्षवर्धन चौहान जी इस विभाग को देख रहे थे। इन्होंने इस विषय को टेक-अप किया है। जो पूर्व में ऑब्जैक्शन्ज लगे थे उन्हें हमारी सरकार के समय पूरा किया गया है लेकिन केंद्र सरकार की ओर से अभी तक कोई सार्थक

उत्तर नहीं आया है। हम समय-समय पर इस विषय को टेक-अप कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि केंद्र सरकार से इसके लिए स्वीकृति मिल जाएगी। हिमाचल प्रदेश में कई आयुर्वेदिक संस्थान स्टाफ की वजह से खाली पड़े हैं। पूर्व सरकार के समय यह नोटिफिकेशन की गई थी कि कुछ ही जिलों में रिक्त पदों को भरा जाएगा। मैंने मुख्य मंत्री जी के साथ इस विषय में वार्तालाप की और उन्होंने इस एजेंडे को फिर से कैबिनेट में लाने की बात कही। हम पिछले फैसले को रूल ओवर करके नया फैसला लेंगे। ऐसा नहीं है कि दूर-दराज क्षेत्रों में ही स्टाफ की कमी है। अगर हम जिला कांगड़ा, हमीरपुर और इसमें इंक्लूडिड अन्य जिलों की बात करें तो वहां भी काफी पद रिक्त पड़े हैं। हम इस विषय को कैबिनेट में लाकर हर जिले में नियुक्तियां करने की कोशिश करेंगे। पूर्व सरकार ने कुछ कारणों से जो स्पैसिफाइड नियुक्तियों की बात की थी हम उसको रेशनलाइज करके जल्द ही पूरे प्रदेश में स्वीकृत पदों को भरने का प्रयत्न करेंगे।

प्रश्न संख्याः 1339

श्री रवि ठाकुर : अनुपस्थित

प्रश्न संख्याः 1340

डॉ0 हंस राज : अनुपस्थित।

अध्यक्षः प्रश्न संख्याः 1340 के साथ माननीय सदस्य श्री डी.एस. ठाकुर जी भी टैग्ड हैं। अतः आप इस प्रश्न का उत्तर पूछ सकते हैं।

श्री बी.एस.द्वारा... जारी

19.02.2024/1430/बी.एस./डी सी/-1

प्रश्न संख्याः 1340

श्री डी.एस. ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना हमने मांगी थी वह तो इसमें मैंशन नहीं की गई है। परंतु जो डलहौजी विधान सभा चुनाव क्षेत्र के अंन्तर्गत सलुनी, मंजीरी और सुराला

की 56 करोड़ रुपये की स्कीम है वह पूर्ण हो चुकी है और जिसका कार्य एक वर्ष पहले पूरा हो चुका था और जनता को भी यह समर्पित भी हो गई है। परंतु आज भी इन पंचायतों को पानी के आबंटन में बहुत समस्या आ रही है। कई स्थानों पर पाइपें नहीं हैं और विभाग के पास जो स्टाफ है उसमें भी कमी है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह जो काम यूनिप्रो कंपनी ने करवाया था, क्या इस कंपनी द्वारा कार्य पूर्ण करने के बाद इस स्कीम के रख-रखाव के लिए अपने कर्मचारियों और पाइपों का प्रावधान है।

उद्योग मंत्री, प्राधिकृत : अध्ययक्ष महोदय, जैसा माननीय विधायक जी ने कहा कि इनके चुनाव क्षेत्र में जल संकट वाले क्षेत्र सलुनी, मंजीरी और सुराला में पानी उपलब्ध करवाने के लिए नाबार्ड के तहत 34 करोड़ रुपये और जल जीवन मीशन के तहत 56.24 करोड़ रुपये की पेयजल योजना स्वीकृत की गई थी जिसका कार्य पूर्ण हो चुका है। इस पेयजल योजना को दिनांक 10.5 2023 को पूर्ण कर जनता को उप-मुख्य मंत्री द्वारा समर्पित कर दिया गया था और इससे 6,455 घरों को कनेक्शन दिए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय, जब यह प्रश्न आया तो मैंने विभाग से यह पूछा कि माननीय विधायक ने यह प्रश्न किया है तो उसका कोई कारण अवश्य होगा। जैसा कहा गया कि उस स्कीम का उद्घाटन तो हो गया परंतु प्रश्न का मतलब तो यह है कि पानी का आबंटन सही से नहीं हुआ **होगा। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दूंगा कि मैंने विभाग को निर्देश दे दिए हैं कि जो भी गांव या घर इस स्कीम की डी.पी.आर. में होंगे और यदि उससे वंचित रहे होंगे उन्हें इस स्कीम से कनेक्शन दे दिए जाएंगे।** यह बात ठीक है कि आपके चम्बा जिले में स्टाफ की भी कमी है परंतु अभी हाल ही में 4500 पंप आपरेटर, पैरा फिटर और मल्टीटास्क वर्कर्ज लगाए जा रहे हैं। जिसमें आपके चम्बा जिला में 49 पंप ऑपरेटर्ज, 21 पैरा फिटर्ज और 96 मल्टी टास्क वर्कर्ज लगाए जा रहे हैं। जल्द ही इनकी नियुक्तियां कर दी जाएगी।

19.02.2024/1430/बी.एस./डी सी/-2

श्री डी.एस. ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से मेरा प्रश्न रहेगा कि क्या यूनिप्रो कंपी को जो काम आबंटित किया गया था और यह काम भी पूर्ण हो चुका है उसके बावजूद भी हमारी 21 पंचायतों में पानी की बहुत कमी है। मैंरा यह प्रश्न था कि क्या कंपनी द्वारा इसके रख-रखाव का प्रावधान है या विभाग द्वारा ही इस स्कीम को चलाया जाएगा?

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभी इस स्कीम में ठेकेदार की 2.50 करोड़ रुपये की पेमेंट रोकी गई है। वह इसलिए रोगी गई है कि यह जो स्कीम है, वह जब तक सुचारु रूप से नहीं चलेगी या पंपिंग सुचारु रूप से नहीं होगी उसकी पेमेंट नहीं होगी और पांच वर्ष तक वही ठेकेदार इस स्कीम को **चलाएगा। यदि माननी विधायक को ऐसा लगता है कि कोई गांव छूट गया है तो आप मुझे या विभाग को आ करके जो भी कमी रही होगी उसके बारे में बताने की कृपा कर दें उसे ठीक कर दिया जाएगा।**

19.02.2024/1430/बी.एस./डी सी/-3

प्रश्न सख्यां 1341

श्री लोकेन्दर कुमार : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना मुझे मिली है इसमें जो हमार लुहरी जल विद्युत परियोजना है उसमें जवाब दिया है कि जो हमने प्रश्न किया था कि कितना पैसा स्थानीय पंचायतें के लिए इस वर्ष दिया गया है? उत्तर में बताया बताया है कि 331 लाख रुपया इस वर्ष दिया गया है। मैं आदरणीय मंत्री जी से प्रश्न करना चाहता हूं कि

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

19.02.2024/1435/डीटी/डी0सी0/1

प्रश्न संख्या 1341 जारी

श्री लोकेन्दर कुमार जारी...

ये जो 331 लाख रूपए इन्होंने दिया है क्या ये राशि विशेष विचाराधारा वाले लोगों को ही मिल रही है, क्योंकि साथ में हमारी 12 पंचायतें ऐसी हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के

विचाराधार वाले प्रधान जीते हैं लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार की राशि उपलब्ध नहीं करवाई जा रहीद्य वो प्रधान जब कुल्लू पैसा मांगने के लिए जाते हैं तो संबंधित प्रोजैक्ट के चेयरमैन इन प्रधानों को पैसे नहीं देते। साथ-ही-साथ प्रश्न के उत्तर में ये भी दर्शाया गया है मेरे विधान सभा क्षेत्र की बहना पंचायत, लूरी जल विद्युत परियोजना-1 व सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना प्रभावित क्षेत्र में नहीं आते। इसमें भी मैं यह बताना चाहता हूं कि लूरी जल परियोजना 210 किलो वॉट की है इसका काम नीरथ व सुन्नी में भी चल रहा है। परंतु जितना भी मक आता है वो रात के समय लूरी के आस-पास फैंका जाता है और वहां से वह हमारे क्षेत्र के अंदर आता है। इसके अतिरिक्त जो बजरी आदी सामग्री को भी अवैध रूप से गांव क अंदर लाया जाता है। इसके अतिरिक्त इन्होंने उत्तर दिया है कि बहना पंचायत इसके अंदर नहीं है। लेकिन बहना पंचायत के अंदर 63 लाख रूपए खर्च भी किए गए है और तीन लड़कियों को वहां पर नौकरी पर भी रखा गया है। मैं माननीय मंत्री जी पूछना चाहता हूं कि जो पैसा प्रदेश सरकार को मिला है क्या वो आने वाले समय में उसका वितरण सामान्य रूप से बिना किसी भेदभाव के किया जाएगा? क्योंकि काफी संख्या में लोग इस बरसात के कारण प्रभावित हुए हैं और प्रभावित लोागों ने जितने भी प्रस्ताव कुल्लू के लिए भेजे थे उस पर एक भी पैसा इन 12 पंचायतों के अंदर नहीं आया। इसके अतिरिक्त जो बहना पंचायत है को भी वर्तमान में किसी भी प्रकार की राशि आबंछित नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त मैं यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि जो रेत, बजरी, मक जो वहां फैंका जाता है, उसकी रोकथाम के लिए भी कोई कदम सरकार की ओर से नहीं उठाया जा रहा है। इसलिए मैं चाहूंगा की माननीय मंत्री महोदय जी आश्वस्त करें कि इस परियोजना में बहना पंचायत को भी जोड़ा जाएगा।

19.02.2024/1435/डीटी/डी0सी0/2

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विधायक को यह बताना चाहूंगा कि जिला कुल्लू में project effected area के जो directly effected areas हैं उसमें इनके चुनाव क्षेत्र की तीन पंचायतें देहरा, गडेल और नीरथ आती हैं। Project effected zone में वो

एरिया आते हैं जिनपर उस प्रोजेक्ट का अपरोक्ष प्रभाव पड़ता है। उसमें इनकी चार पंचायते आती हैं क्रमशः दुराज, कीही, पलैही व भावा।

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो पंचायतों को दी गई धनराशि के संबंध में प्रश्न किया है मैं उसके बारे में इन्हें अवगत करवाना चाहूंगा कि इनके निर्वाचन क्षेत्र की पंचायतों के लिए 3 करोड़ 31 लाख रूपये पैसा इसमें दिया गया है जिसकी पंचायत वाईज़ डिटेल मैं माननीय विधायक को दे दूंगा। लेकिन बहाना पंचायत का उल्लेख इनके द्वारा किया गया है, मैं इन्हें बताना चाहता हूं ये पंचायत इसमें नहीं आती।

श्री दीप राज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में यह दोनों प्रोजेक्टस आते हैं जिनका उल्लेख यहां किया गया है। तत्तापानी में कोल डेम का जो प्रोजेक्ट है इसमें जो लैंड इफक्टिड लोग हैं, जब भारी बरसात हुई तो उनके घरों के रास्ते बह गये। आप चाहें तो मैं नाम के साथ भी कोट कर सकता हूं। श्रीमती लीली देवी जी उनके घर का रास्ता चला गया है। आप हमें आश्वस्त करें कि कब तक उनको रास्ता दे दिया जायेगा; और कब तक उनके घरों के रास्ते बनाये जायेंगें?

दूसरा, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि अभी जो नया प्रोजेक्ट स्टेज-III लग रहा है उसमें अभी तक Land Effected Zone चिन्हित नहीं किया गया है लेकिन जो land looser हैं उनकी पहचान करली गई है। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि आने वाले समय जो land effected zone होगा वहां के लोगों को भी भारी क्षति का समाना करना पड़ेगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस संबंध में भी माननीय मंत्री जी आश्वस्त करें कि इसके लिए कितनी विशिष्ट समयावधि तय की जाएगी?

19.02.2024/1435/डीटी/डी0सी0/3

उद्योग मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जो उत्तर उपलब्ध करवाया गया है उसमें प्रभावित लोगों का जिक्र किया गया है लेकिन जो अभी आइडेंटिफाड नहीं किए गए होंगे उन्हें आइडेंटिफाइ कर लिया जाएगा और माननीय सदस्य के चुनाव क्षेत्र में सुन्नी वाला क्षेत्र आता है और

करसोग वाला क्षेत्र आता है, आपके यहां जहां भी डेमेज हुआ होगा उस डेमेज के संबंध में आप सरकार को या उपायुक्त को लिखित तौर पर भेजें। उसको रिस्टोर करने के लिए सरकार द्वारा कंपनी के मेनेजमेंट को पत्र लिख दिया जाएगा **and it will be done.** मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इसमें जो 1.5 % प्रोजैक्ट की कॉस्ट है उसे सी0एस0आर0 या लाडा में खर्च करना पड़ता है। उसमें भी पहले फेज में 25 प्रतिशत, दूसरे फेज में फिर 25 प्रतिशत है और

श्री एन0जी0द्वारा जारी...

19-02-2024/1440/एच.के.-एन.जी/1

प्रश्न संख्या -1341.....जारी

उद्योग मंत्री.....जारी

तीसरे फेज में 50 प्रतिशत है। अभी तक यह प्रोजैक्ट 60 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। **इसमें directly or indirectly affected areas होंगे और उनमें जहां पर भी नुकसान हुआ होगा तो उसकी डी.पी.आर. बना कर इन कम्पनियों से पैसा दिलवाएंगे।** It will be done very shortly.

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री नंद लाल, आप कहिए। I will give you time. Why are you in a hurry? You (towards Shri Deep Raj) are being assisted by Shri Nand Lalji.

श्री नन्द लाल : अध्यक्ष महोदय, यह जो आनी में बन रहे प्रोजैक्ट की बात चल रही है तो this is in our area और रामपुर की नीथर जगह में यह सब लोकेटिड है। माननीय सदस्य श्री लोकेन्द्र कुमार ने जो बात कही है, मैं उससे सहमत हूं। वहां पर जो Project affected area और पंचायतें शामिल हैं there is a difference. वहां पर 900 मीटर का एक मापदण्ड रखा हुआ है उसमें पूरी पंचायत कवर नहीं हो रही है। उसके कारण सी.एस.आर. के

अंतर्गत जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थीं वह लोगों को नहीं मिल रही हैं। लोगों में बहुत रोष है कि आधी पंचायत बाहर कर दी और to cover the entire Panchayat. लेकिन वे तो डिस्टेंस के हिसाब से चल रहे हैं और लोगों का नुकसान तो हर जगह हो रहा है। इसी प्रकार प्रदूषण भी पूरी पंचायत में बराबर हो रहा है। माननीय सदस्य ने जो रोज़गार की बात कही है वह भी सही है। जिसका मन चाहा वह वहां पर रोज़गार दे रहा है। मेरा कहना है कि it is through the contractor only. वहां पर कम्पनी की ओर से कोई रोज़गार नहीं दिया जा रहा है। मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि यह सुनिश्चित किया जाए और यह जो डिस्टेंस वाला इश्यू है it should be taken up with the authorities.

19-02-2024/1440/एच.के.-एन.जी/2

उन लोगों के पास पूरी पंचायत को ले जाकर उनसे बात की जाए। इसके अलावा रोज़गार के विषय पर उनके साथ एक बड़ी बैठक की जाए जिसमें सभी संबंधित माननीय विधायकों को भी बुलाया जाए और इसका समाधान किया जाए। धन्यवाद।

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत हूं। प्रोजैक्ट के लिए जो पैरामीट्र्स बनाए गए हैं वे पूरे देश के सभी प्रोजैक्ट्स के लिए एक समान हैं। इसमें project affected zone or project affected area को लिया जाता है। Project affected area में directly affected areas आएंगे और project affected zone में indirectly affected areas आएंगे। माननीय सदस्य श्री नन्द लाल जी की पंचायतें project affected area में आ रही हैं। जिसमें ग्राम पंचायत नीथर, ग्राम पंचायत दत्तनगर, जेथल और ग्राम पंचायत कमाथला शामिल हैं। Project affected zone में देथल, बढ़ात, हुट्टी, आनाधार, किरथल और करगाला पंचायतें आती हैं। वहां पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष डैमेज तो हो ही रहा है। लेकिन पानी के ज्यादा छोड़ देने के कारण भी डैमेज हो रहा हैं। **मैं माननीय सदस्य श्री नन्द लाल जी को कहना चाहता हूं कि हम मैनेजमेंट से इन मामलों को टेकअप करेंगे।**

अभी यह प्रोजैक्ट कम्पलीट नहीं हुआ है और **लाडा का पैसा affected areas के लिए ही है और उस पैसे को वहां पर खर्च करवाएंगे।** माननीय सदस्य की बात से मैं सहमत हूं कि हाइड्रल प्रोजैक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोजैक्ट और अन्य प्रोजैक्ट्स में अपने स्टाफ के तहत हमारे लोगों को रोज़गार नहीं देते हैं। हिमाचल प्रदेश के लोगों को तो ठेकेदार के माध्यम से ही नौकरी देते हैं। ठेकेदार का काम जब समाप्त हो जाता है तब कर्मचारियों व हिमाचली लोगों को काम से निकाल दिया जाता है। Sir, this is a serious problem in the State. इस पर मुख्य मंत्री जी ने कम्पनियों के साथ चर्चा की है और इस समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हिमाचल प्रदेश के लोगों को प्रोजैक्ट्स में डायरेक्ट रोज़गार प्राप्त हो क्योंकि प्रोजैक्ट तो लगातार चलते रहेंगे।

Speaker : Shri Lokender Kumarji this will be the last supplementary.

19-02-2024/1440/एच.के.-एन.जी/3

श्री लोकेन्दर कुमारः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अभी मंत्री जी ने कहा कि लुहरी प्रोजैक्ट के तहत बहना पंचायत प्रभावित पंचायत नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि जहां से प्रोजैक्ट के डम्पर चलते हैं या जहां पर मिट्टी को डम्प किया जाता है क्या वह प्रभावित क्षेत्र की श्रेणी में नहीं आता? बहना पंचायत में रात-दिन सैंकड़ों डम्पर चलते हैं और मिट्टी डम्प की जाती है। इसके अलावा मंत्री जी ने बहुत प्यार से टाल दिया और माननीय विधायक श्री नन्द लाल जी ने भी कहा है कि हमारे प्रभावित लोगों को कम्पनी द्वारा एक कागज़ देकर कहा है कि आपको नौकरी मिलेगी और जिन्होंने नौकरी नहीं लेनी होगी उन्हें कम्पनी पांच लाख रुपये देगी।

श्रीमती के.एस. द्वारा जारी.....

19.02.2024/1445/केएस/एचके/1

प्रश्न संख्या : 1341 जारी---

श्री लोकेन्दर कुमार जारी---

परन्तु अभी तक ना ही उनको नाकरी मिली है, और ना ही 5 लाख रुपये मिले हैं और आप देखें कि आए दिन चाहे रामपुर का क्षेत्र हो, आनी का क्षेत्र हो या करसोग का क्षेत्र हो, वहां पर सड़कों पर लोग आ रहे हैं। बाहर के लोगों को लगातार नौकरी मिल रही है। लोग हमें फोन करते हैं कि हमें वहां पर लगना है। किसी ने इंजीनियरिंग की है या कोई आई.टी.आई. करके आया है, उनको वहां पर लिया ही नहीं जा रहा है। मंत्री महोदय हमें आश्वस्त करें कि हमारी वहां जल्दी बैठक हो। सभी सम्बन्धित विधायक वहां आएं और बैठक का अच्छा नतीजा निकले क्योंकि एस.जे.वी.एन.एल. वालों को हम कहते हैं तो वे पटले कम्पनी को बोलते हैं और वहां पर आदमी बार-बार शोषित होता रहता है। वे कभी उसको पटेल कम्पनी में भेजते हैं और पटेल कम्पनी वाले उसको एस.जे.वी.एन.एल. में भेज देते हैं। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी हमें इस सम्बन्ध में आश्वासन दें।

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की बात से बिल्कुल सहमत हूं। ये जो कह रहे हैं यह इन्हीं के चुनाव क्षेत्र की बात नहीं है। जहां-जहां भी हाईडल प्रोजैक्ट्स हैं, चम्बा या किन्नौर में बहुत सारे प्रोजैक्ट्स रहे हैं । क्योंकि बड़ी कम्पनीज़ सबलैटिंग करके आगे कॉंट्रैक्टर्ज़ को काम दे रही हैं। वे सीधे तौर पर कर्मचारियों की जिम्मेवारी नहीं लेते। बहुत सारे ऐसे केसिज़ भी हैं जिनमें बड़ी कम्पनियां हैं, जिसको एस.जे.वी.एन.एल. कॉंट्रैक्ट देगी वे आगे सबलैट करके वर्क देंगे और हिमाचल प्रदेश के लोगों की पेमेंट्स लटकाई जाती है। इस तरह के बहुत सारे केसिज़ समय-समय पर आते रहते हैं। मैं माननीय विधायक की बात से बिल्कुल सहमत हूं। आपने जो एरिया की बात की, we are trying to solve this problem.

अध्यक्ष : मंत्री जी, माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि आप सभी विधायकों को बुलाकर इस सम्बन्ध में मीटिंग कर लें।

Industries Minister: Sir, we ensure, we will do it. जहां-जहां प्रोजैक्ट्स हैं, वहां पर स्थानीय विधायकों, मैनेजमैंट और डिप्टी कमिशनर के थ्रू मीटिंग बुलाकर we will solve these issues.

19.02.2024/1445/केएस/एचके/2

प्रश्न संख्या : 1342

श्री चैतन्य शर्मा : अनुपस्थित।

प्रश्न संख्या : 1343

श्री दलीप ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र में बरसात में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। विभाग और जिलाधीश महोदय द्वारा जो धनराशि जारी की गई है, उसकी मैंने सूचना भी मांगी थी। जिन व्यक्तियों की जमीन ही चली गई, मकान बनाने के लिए जिनके पास जमीन ही नहीं है। लोगों की गऊशाला चली गई या मकान चला गया है और ऐसे बहुत ज्यादा अनुसूचित जाति परिवार के लोग हैं जिनके पास मकान बनाने के लिए जमीन नहीं है। माननीय मंत्री जी ने मुझे जो जवाब दिया है, उसमें कहा गया है कि 3 बिस्वा गांव के लिए और 2 बिस्वा शहर के लिए सरकार भूमि आबंटित कर रही है परन्तु आपने टाइम बाउंड नहीं किया है कि आप कब तक उनको यह जमीन देने वाले हैं। बस यही कहा है कि हम इनको जमीन देंगे। लोग कब तक इंतज़ार करेंगे कि हमें मकान के लिए जगह मिलेगी और हम उसमें मकान बनाएंगे? पैसा सरकार दे रही है लेकिन अगर पैसा देने के बावजूद जिस व्यक्ति के पास जमीन ही नहीं है तो वह मकान बनाएगा कहां? मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि कृपया आप आप अप्रैल, मार्च से, जब से भी आप चाहें सुनिश्चित करें कि उन को जमीन उपलब्ध करवाएं ताकि आप अगर पैसा दे रहे हैं तो वे मकान बना सके।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सरकाघाट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में अभी तक कुल 12,38,25,000/- रुपये राहत राशि जारी कर दी गई है। 99 प्रतिशत पैसा जारी भी कर दिया है। माननीय सदस्य ने ठीक कहा कि जो लोग भूमिहीन हुए हैं या जिनको मकान बनाने के लिए भी जगह नहीं है, सरकार की स्कीम तो है कि 3 बिस्वा ग्रामीण और 2

बिस्वा शहरी क्षेत्र में देंगे परन्तु यह उसी जगह पर सम्भव है जहां पर हमारे पास एफ.सी.ए. से बाहर की जमीन है। सरकाघाट में अभी तक इस किस्म की एफ.सी.ए. से बाहर की कोई जमीन उपलब्ध नहीं है इसलिए 3 और 2 बिस्वा वाली स्कीम को इम्पलीमेंट करना वहां सम्भव नहीं है

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी----

19.02.2024/1450/एवी/वाईके/1

प्रश्न संख्या : 1343---------- क्रमागत

राजस्व मंत्री------ जारी

अगर **ये एफ0आर0ए0 में भूमि प्राप्त कर सकते हैं तो हम उससे लोगों को तेजी से फायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे।** आप जानते हैं कि एफ0सी0ए0 के लिए केंद्र सरकार की अनुमति प्राप्त करनी पड़ती है तथा मुझे लगता है कि 2-2, 3-3 बिस्वे के लिए तो वहां से भी स्वीकृति नहीं मिलेगी। फिर भी डिजास्टर मेनेजमेंट एक्ट के तहत हम यह देखने जा रहे हैं कि इसके अंदर प्रावधानों को किसी तरह से लागू करके ऐसी स्थिति में जहां पर कोई जमीन नहीं है और **उसको कहीं पर रीहेबिलिटेट करना है तो हम क्या इस एक्ट का फायदा उठाकर एफ0सी0ए0 से ऊपर करें, हम इसकी कोशिश कर रहे हैं।**

श्री दलीप ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि 12 करोड़ रुपये के करीब राशि दी गई है जबकि लिखित सूचना के अनुसार 9 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। अभी बहुत सारे ऐसे विभाग हैं उसमें चाहे लोक निर्माण विभाग है या जल शक्ति विभाग है, मेरे विधान सक्षा क्षेत्र की बहुत सारी सड़कें जो डिजास्टर के समय बंद थीं उन पर अभी तक बसें नहीं चल पाई हैं और न ही वह पैसा लग पा रहा है। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि आप जमीन को जल्दी-से-जल्दी उपलब्ध करवाने के प्रयास कीजिए। आप इसके लिए जितने ज्यादा जल्दी प्रयास करेंगे लोग उतनी शीघ्रता से अपने मकान बना सकेंगे।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, लिखित सूचना में कुछ कमी रह गई थी इसलिए हमने संशोधित रूप से सूचना अपलोड भी करवा दी थी परंतु हो सकता है माननीय सदस्य को वह उपलब्ध न हुई हो। इसलिए मैं दोबारा से कहना चाहता हूं कि यह राशि 12 करोड़ रुपये

ही है और सभी विभागों को पैसे दिए हैं। लोक निर्माण विभाग को 2 करोड़ रुपये की राशि दी गई है और कुछ खर्चा अभी रहता भी है। **विभाग को उन सड़कों को जल्दी से ठीक करना चाहिए। हम इस मामले को लोक निर्माण विभाग से उठाएंगे कि इस राशि का सदुपयोग करके आपकी सड़कों को जल्दी-से-जल्दी ठीक करें।**

प्रश्न समाप्त

19.02.2024/1450/एवी/वाईके/2

प्रश्न संख्या : 1345

श्री राजेन्द्र राणा : अध्यक्ष महोदय, सूचना मिल गई है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने राजकीय महाविद्यालय सुजानपुर में एम0ए0 की क्लासिज की घोषणा दिनांक 5 मार्च, 2023 को की थी। आपने लिखित सूचना में दर्शाया है कि इसका एन0ओ0सी0 दिनांक 31 मई, 2023 को दिया गया था। मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि क्या आप वहां पर जुलाई माह में नये सैशन के दौरान क्लासिज शुरू कर देंगे या नहीं?

शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र राणा जी इस सदन के एक वरिष्ठ सदस्य हैं और हमारे बड़े भाई भी हैं। इन्होंने जैसे अभी कहा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने इनके विधान सभा क्षेत्र में जाकर राजकीय महाविद्यालय सुजानपुर-टीहरा में दो पी0जी0 कोर्सिज शुरू करने की घोषणा की थी। इसकी स्वीकृति विभाग ने दे दी है परंतु इसमें अभी यूनिवर्सिटी स्तर पर कुछ औपचारिकताएं शेष रहती हैं। मैंने उसके लिए **विभाग को आदेश दे दिए हैं कि शीघ्रातिशीघ्र उन सारी औपचारिकताओं को पूर्ण किया जाए और आने वाले एकेडेमिक सेशन यानी माह जुलाई से राजकीय महाविद्यालय सुजानपुर-टीहरा में दोनों पी0जी0 कोर्सिज प्रारम्भ कर दिए जाएंगे।**

टी सी द्वारा जारी

19.02.2024/1455/टी0सी0वी0/वाई0के0-1

प्रश्न संख्याः 1344

श्री सतपाल सिंह सत्ती : अध्यक्ष महोदय, श्री राकेश जम्वाल जी ने प्रश्न किया था और जो इसका उत्तर आया है उसमें यह बताया गया है कि कौलडैम से तत्तापानी की ओर जाते हुए लैफ्ट बैंक पर दो विधान सभा क्षेत्र सुन्दर नगर और करसोग का एरिया एक साथ लगता है लेकिन जो सी0एस0आर0 का फंड है उससे शिमला ग्रामीण और अर्की के कुछ एरिया को ज्यादातर पैसा दिया गया है। सुन्दर नगर इससे सबसे ज्यादा इफैक्ट हुआ है या अन्य जो विधान सभा क्षेत्र है उनको सी0एस0आर0 से कोई फंड नहीं दिया गया है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या आपने वाले समय में एन0टी0सी0पी0 को निर्देश दिए जाएंगे कि इन क्षेत्रों में भी जनता के हित में सी0एस0आर0 का पैसा खर्च करें?

उद्योग मंत्री (प्राधिकृत) : अध्यक्ष महोदय, जैसे सतपाल सिंह सत्ती ने कहा है कि सुन्दर नगर विधान सभा क्षेत्र में सी0एस0आर0 का पैसा खर्च नहीं किया गया लेकिन इन कम्पनीज को कुल प्रोफिट का 2 प्रतिशत पैसा सी0एस0आर0 के तहत खर्च करना पड़ता है। इस कम्पनी ने इस वित्तीय वर्ष में 168.94 लाख रुपये खर्च कर दिए हैं। इसकी डिटेल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसमें बहुत-सारे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के नाम है। अगर सुन्दर नगर का नहीं होगा तो हम स्थानीय विधायक श्री राकेश जम्वाल जी से आग्रह करेंगे कि सी0एस0आर0 के तहत वहां पर पैसा खर्च किया जाए।

श्री दीप राज : अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि करसोग विधान सभा क्षेत्र का एक बहुत लम्बा क्षेत्र इसमें आता है जिसकी वजह से पुल भी 3 महीने तक टूटा रहा। इसको देखने के लिए कौलडैम प्रोजैक्ट वाले भी नहीं आए और जितने रास्ते हैं वे अभी भी टूटे हैं। चाहे वह इफैक्टिड जोन हो या लैंड लूजर का जोन हो। उनसे एक स्पैसिफिक टाइम लिया जाए कि वे कब तक इन रास्तों को ठीक करेंगे? वहां

पर लोगों के घरों को भी नुकसान हुआ है और कौलडैम की ओर से कोई भी चैकिंग इत्यादि के लिए नहीं आया। मैं चाहूंगा कि इसके लिए उनको निर्देश दिए जाएं।

19.02.2024/1455/टी0सी0वी0/वाई0के0-2

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने इनके पहले प्रश्न में भी कहा है कि we will direct the Deputy Commissioner जो भी ग्रिवेंसिज है चाहे वे करसोग विधान सभा क्षेत्र के हैं या इनके क्षेत्र के हैं। We will direct the Deputy Commissioner कि वे इस मैटर को कम्पनी से टेकअप करें और सी0एस0आर0 में जो पैसा है उससे जहां-जहां नुकसान हुआ है उससे आपके चुनाव क्षेत्र में इसके तहत नुकसान की भरपाई हो सके।

19.02.2024/1455/टी0सी0वी0/वाई0के0-2

प्रश्न संख्याः 1346

श्री सुख राम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के (ख) भाग के संदर्भ में जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है उसके अनुसार 220/33 के0वी सब-स्टेशन गोंदपुर में बनाना प्रस्तावित है क्योंकि मेरे विधान सभा क्षेत्र, शिलाई और चौपाल के विधान सभा क्षेत्र तथा साथ में नाहन व रेणुका की कुछ पंचायतें ऐसी हैं जिनको 132 के0वी0 सब-स्टेशन गोंदपुर से सप्लाई दी जाती है। जब यह 132 के0वी0 से सप्लाई फेल हो जाती है तो यह सारा क्षेत्र अंधेरे में हो जाता है। 132 के0वी0 वहीं से 220 के0वी0 लाइन होदरी-मादरी की गई है। उसी में सब-स्टेशन बनना है। इसलिए इन्होंने कहा है कि डॉक्युमेंटेशन पूरा होने के बाद निविदाएं आमंत्रित की जाएगी। इस डॉक्युमेंट को कब तक पूरा करके निविदाएं आमंत्रित की जाएगी ताकि इस 220/132 के0वी0 सब-स्टेशन का कार्य पूरा किया जा जाए और तीन विधान सभा क्षेत्र को डबल सप्लाई मिल सके?

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह स्कीम हि0 प्र0 पॉवर सैक्टर डवलपमेंट प्रोग्राम के तहत तैयार की जानी थी और इसकी सैंक्शन हो चुकी है। इससे मेरा विधान सभा चुनाव क्षेत्र भी प्रभावित होता है। **इसको आपने पॉवर मिनिस्टर रहते हुए प्रपोज किया था और इसको नाबार्ड ने सैंक्शन कर दिया है। इन दोनों स्कीमों के टेंडर शीघ्र ही** लग जाएंगे और जमीन भी शीघ्र ही ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसके लिए संबंधित उपायुक्त को निर्देश दे दिए गए हैं।

प्रश्न काल समाप्त

एन0एस0 द्वारा जारी ।

19-02-2024/1500/एन0एस-ए0जी0/1

साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य

अध्यक्ष : अब मुख्य मंत्री जी द्वारा प्राधिकृत उद्योग मंत्री सदन को इस सप्ताह की शासकीय कार्यसूची से अवगत करवाएंगे।

उद्योग मंत्री (प्राधिकृत) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से इस माननीय सदन को इस सप्ताह की शासकीय कार्यसूची से अवगत करवाता हूं जोकि इस प्रकार हैः-

सोमवार, 19 फरवरी, 2024	1. शासकीय/विधायी कार्य ।
	2. बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2024-25 पर सामान्य चर्चा
मंगलवार, 20 फरवरी, 2024	1. शासकीय/विधायी कार्य ।
	2. बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2024-25 पर सामान्य चर्चा।
बुधवार, 21 फरवरी, 2024	1. शासकीय/विधायी कार्य ।
	2. बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2024-25 पर

सामान्य चर्चा।

वीरवार , 22 फरवरी, 2024 1. शासकीय/विधायी कार्य ।

2. बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2024-25 पर सामान्य चर्चा का समापन।

शुक्रवार , 23 फरवरी, 2024 1. शासकीय/विधायी कार्य ।

2. गैर-सरकारी सदस्य कार्य दिवस।

19-02-2024/1500/एन0एस-ए0जी0/2

कागज़ात सभा पटल पर

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री द्वारा प्राधिकृत उद्योग मंत्री जी कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

उद्योग मंत्री (प्राधिकृत) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जोकि इस प्रकार से हैं:-

(i) प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (38/2016) की धारा-29 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्रधिकरण (कैम्पा) का 9वाँ तथा 10वाँ वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2017-2018 तथा वर्ष 2018-2019 (विलम्ब के कारणों सहित);

(ii) विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 104(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग के वार्षिक लेखे तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2022-23;

(iii) संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत हिमऊर्जा (हिमाचल प्रदेश ऊर्जा विकास अभिकरण) हिमाचल प्रदेश का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2022-23;

(iv) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 395 के अन्तर्गत सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2022-2023;

अध्यक्ष : अब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम अधिनियम, 1979 की धारा 23(6) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम, हमीरपुर की 42वीं वार्षिक प्रशासनिक विवरणिका, वर्ष 2022-23 की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष : अब कृषि मंत्री कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

19-02-2024/1500/एन0एस-ए0जी0/3

कृषि मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति , बीज अधिनियम, 1966 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य बीज एवं जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण अभिकरण, शिमला का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2022-23 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष : अब उद्योग मंत्री कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, अतिरिक्त निदेशक, ग्रुप-ए (राजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2024 जोकि अधिसूचना संख्याःइन्ड-ए (ए) 3-5/2023, दिनांक 24.01.2024 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 31.01.2024 को प्रकाशित, की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष : अब लोक निर्माण मंत्री कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (b) के अन्तर्गत शिमला जल प्रबन्धन निगम लिमिटेड का चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2021-22 (विलम्ब के कारणों सहित), की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

19-02-2024/1500/एन0एस-ए0जी0/4

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट अनुमान पर सामान्य चर्चा

अध्यक्ष : अब वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट अनुमानों/वार्षिक वित्तीय विवरण पर सामान्य चर्चा प्रारम्भ हो रही है तथा इसका समापन दिनांक 22 फरवरी, 2024 को मुख्य मंत्री जी के उत्तर के साथ होगा। समय की उपलब्धता को देखते हुए विपक्ष के नेता को 45 मिनट तथा अन्य सदस्यों को 10 से 15 मिनट का समय सुनिश्चित किया गया है। मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन रहेगा कि वे अपना-अपना भाषण बजट तक ही सीमिति रखकर निर्धारित अवधि में समाप्त करें। विषयों को रिपीट न करें, नए विषय लाएं, सुझाव भी दें और क्रिटीसाइज भी करें। अब मैं विपक्ष के नेता श्री जय राम ठाकुर जी को चर्चा आरम्भ करने के लिए आमन्त्रित करता हूं।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान जो दिनांक 17 फरवरी, 2024 को मुख्य मंत्री जी ने इस माननीय सदन में प्रस्तुत किए हैं, मैं उसमें चर्चा करने के लिए माननीय सदन में खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, पिछला बजट दिनांक 17 मार्च, 2023 को प्रस्तुत किया गया था और इस बार का बजट दिनांक 17 फरवरी, 2024 को प्रस्तुत किया यानी ठीक 11 महीने बाद दूसरा बजट प्रस्तुत किया। मुझे इस बात का मलाल है कि उस दिन मैं इस सदन में व्यक्तिगत रूप से मौजूद नहीं था.

आर0के0एस0 द्वारा ------जारी

19.02.2024/1505/RKS/AS-1

श्री जय राम ठाकुर...जारी

क्योंकि मुझे पार्टी की बहुत महत्वपूर्ण नेशनल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए दिल्ली जाना पड़ा था। लेकिन फिर भी मैं बीच-बीच में इस बजट को सुन रहा था। जब मैं आज सुबह दिल्ली से शिमला आ रहा था तो मैंने रास्ते में थोड़ी-सी नजर इस बजट में डाली। मैंने जब सरसरी नजर इसमें डाली तो मुझे लगा कि अब इस बजट में दूसरी नजर मारने की आवश्यकता नहीं है। इसका कारण यह है कि जो 11 महीने पहले आपने बजट पेश किया गया था उसी बजट की बहुत सारी चीजें आपने इस बजट में भी दोहराई है। इस एक साल के लिए निर्धारित योजनाओं की कोई भी चीज जमीन में नहीं उतरी है। बेहतर होता आप वर्ष 2023-24 के बजट की प्रति यहां पर रख देते और कह देते कि इसी को ही वर्ष 2024-25 का बजट मान लिया जाए। आप कह देते कि हम एक साल में कुछ भी करने में कामयाब नहीं हो पाए इसलिए इसी को ही बजट की प्रस्तुती मान लिया जाए। हम उम्मीद कर रहे थे कि आपने एक साल के कार्यकाल में कुछ सीखा होगा। हमने सोचा कि एक साल के कार्यकाल में जो परिस्थितियां थी उनके अनुरूप इस बजट में कुछ नये इनिशिएटिव आएंगे लेकिन यह एक साल पूर्ण रूप से शून्य में बह कर चला गया। यह इस बजट की हकीकत है। मुख्य मंत्री जी आत्म-निर्भर हिमाचल बनाने की बात करते हैं लेकिन इनकी बातों में विरोधाभास है। एक तरफ आप कहते हैं कि हम आने वाले चार वर्षों में हिमाचल को आत्म-निर्भर बना देंगे और हिमाचल प्रदेश पूरे भारतवर्ष में आर्थिक रूप से सबसे समृद्ध राज्य बनकर उभरेगा। लेकिन कई जगह आप भाषण देते हैं कि हिमाचल की परिस्थिति शीघ्र ही श्रीलंका जैसी हो जाएगी। यह बात भी सत्य है। आप कभी कुछ कहते हैं और कभी कुछ। आपको काम के प्रति भी ऐसी ही कन्फयूज्न है। आप कभी कुछ करते हैं और कभी कुछ। आपकी बात और काम में कोई तार-तम्य नहीं बैठ पा रहा है। अगर हम आत्म-निर्भर हिमाचल की बात करें तो कुछ मित्र लोग तो आत्म-निर्भर हो पा रहे हैं लेकिन इस परिस्थिति में यह प्रदेश आत्म-निर्भर नहीं हो सकेगा जोकि बहुत बड़ी चिंता का विषय है। आपने इस बार 58,444 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया है।

श्री बी.एस.द्वारा... जारी

19.02.2024/1510/बी.एस./ए एस/-1

श्री जय राम ठाकुर जारी...

और उसमें बड़ी दिलचस्प बात है कि जो आर्थिक वृद्धि दर का जिक्र किया है वह 7.1 प्रतिशत का किया है। मैं जानना चाहता हूं कि यह आंकड़ा आपने कहां से उठाया है और इसे इस प्रकार से प्रस्तुत करने का आधार क्या है इसकी हमें समझ नहीं आ रही है। आपने पैरा 72 में जो संशोधित अनुमानों का जिक्र किया है उसमें कहा है कि वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमानों के अनुसार कुल राज्य प्राप्तियां 40,446 करोड़ रुपये हैं और वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व व्यय 45,926 करोड़ रुपये है। इस तरह से वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमानों के अनुसार 5,480 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा अनुमानित है। मैं समझता हूं कि यह भी आंकड़ा घुमा-फिरा करके दिया गया है। जबकि मेरा मानना इससे हट करके है। उसके बाद आपने अगले पैरा में लिखा है कि वर्ष 2023-24 के लिए जो जिक्र किया है कि राजस्व प्रप्तियों में 42,153 करोड़ रुपये का अनुमान बताया गया है और इसी तरह से राजस्व व्यय 46,667 करोड़ रुपये अनुमानित है।

(उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

इस प्रकार कुल राजस्व घाटा 4,514 करोड़ रुपये अनुमानित है। यदि हम इन आंकड़ों पर जाएं तो मैं इस बात को कह सकता हूं कि यह आंकड़े तथ्य पर नहीं है। मैं इस बात से सहमत हूं कि इन सारी चीजों के लिए हमें अधिकारियों पर निर्भर रहना पड़ता है और अधिकारी इन्हें बहुत बेहतर ढंग से घुमाते हैं और अब की बार भी वही घुमाने का प्रयत्न हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को कह सकता हूं कि विकास के जो मुख्य निर्माण कार्य निवेश एवं सहायता अनुदान कैपिटल असैस की बात करें उसके अन्तर्गत यदि हम जाते हैं तो मुझे इस बात को ले करके सचमुच दुःख है कि मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत फर्क वर्ष 2022-23 के अंतर्गत 5,310 करोड़ रुपये से कम हो करके वर्ष 2023-24 में 4,725 करोड़ रुपया ही रह गया है और इस प्रकार निवेश में खर्च 423 करोड़ रुपये से घट करके 228 करोड़ रुपया ही रह गया है। यदि हम आगे बढ़ करके बात करें तो ग्रांट इन एड पर केपिटल असैस के अन्तर्गत व्यय 1376 करोड़ रुपये से घट कर 779 करोड़ रुपया ही रह गया है, अब क्या करेंगे? इसी प्रकार में आगे बढ़ करके बात कही है कि

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

19.02.2024/1515/डीटी/ए0एस0/1

श्री जय राम ठाकुर जारी....

मटेरियल एंड सप्लाई में खर्च 466 करोड़ रूपए में से कम होकर 428 करोड़, मशीरनरी एवं इक्विपमेंट में 216 करोड़ रूपए से कम होकर केवल 90 करोड़ ही रह गया। इसमें कितनी डिक्रीज हुई की आंकड़ा 216 से घटर 90 करोड़ रूपए रह गया। इसलिए मैं यह कह सकता हूं कि ये जो आंकड़ें हैं ये तथ्य पर आधारित हो ही नहीं सकते। इसके अतिरिक्त अगर हम देखे की केन्द्रीय परियोजनाओं के अंतर्गत जो भारत सरकार से धनराशि प्राप्त की जाती है, उसमें भी वर्ष 2022-2023 वे भी 880 करोड़ रूपए से कम होकर 2023-2024 में 481 करोंड़ ही रह गई। इस बात को लेकर मैं यहां ये उल्लेख करना चाहूंगा कि सरकार द्वारा घाटे कम दर्शाने के लिए राजस्व प्राप्तियों को जो बढ़ा-चढ़ा कर प्रस्तुत किया गया है, मुझे लगता है कि वह उचित्त नहीं है। कम से कम सही तस्वरी आने दीजिए। जो हकीकत है उसे तो सही ढंग से आने प्रस्तुत कीजिए। मैं यह भी देख रहा हूं कि राज्य की वर्ष 2023-2024 में अपनी राजस्व प्राप्तियां 16472 करोड़ रूपए की हैं और जिन्हें वर्ष 2024-2025 में 18739 करोड़ रूपए दिखाया गया है। इसी प्रकार से अगर हम share in Central taxes की बात करें 2023-24 8478 करोड़ की तुलना में वर्ष 2024-2025 में 10124 करोड़ दर्शाइ गई है। ये आंकड़ें हैं जिन आंकड़ों को हम झुठला नहीं सकते। ये वास्तिवकता है। केन्द्रीय प्रायोजित योजना के राजस्व प्राप्ति की अगर हम बात करें वे 3338 करोड़ रूपए की तुलना में 2024-2025 में 5272 करोड़ दर्शाए गए हैं और वर्ष् 2023-2024 की केंद्रींय पूंजिगत प्राप्तियां है 481 करोड़ रूपए की तुलना में 14200 करोड़ रूपए दर्शाई गई हैं। इसलिए इस बात को मैं कह सकता हूं कि सारे विकास कार्य पिछले एक साल से ठप पड़े हुए हैं और कहीं थोड़े-बहुत चल भी रहे हैं तो वो भी ठप होने की कगार में हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की जो देनदारियां है चाहे वह लोन की रिपेंट का मामला है, चाहे वह उसके ब्याज का है, कर्मचारियों का एरियर है, चाहे वे पैंशनरों के एरियर हैं, चाहे वह महिलाओं के साथ किए गए वायदे हैं, ये देनदारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। अगर हम पहली जनवरी से एरियर देने की बात करें तो वह एरियार लगभग 10000 करोड़ रूपए

बैठता है। लेकिन इस बजट में उन सारी चीजों का जिक्र ही नहीं किया है। इन सारी चीजों को छिपा दिया गया है। छिपाने की वजह यही है कि हम विपक्ष के लोग उसका जिक्र न कर सकें। इसलिए इस बात को लकर मैं कहता हूं कि चीजों को

19.02.2024/1515/डीटी/ए0एस0/2

छिपा करके प्रदेश का भला नहीं हो सकता, प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता। जो वास्तविकताएं हैं उनका सामना करना पड़ेगा, उनको जनता के सामने रखना पड़ेगा। उन चुनौतियों का सामना आने वाले समय में हम कैसे करें सरकार को उस दिशा मे काम करने की आवश्यकता है। इसके अलावा अगर हम इस बात को देखें की हमारी सरकार ने वर्ष 2022-2023 में लोन की रिपेंट के लिए 10246 करोड़ रूपए की धनराशि रखी गई थी। लेकिन वर्तमान सरकार ने आते-आते लोन की स्पीड को ऐसे बढ़ाया

श्री एन0जी0द्वारा जारी...

19-02-2024/1520/डी.सी.-एन.जी/1

श्री जय राम ठाकुर .....जारी

जैसे गाड़ी फोर-लेन पर चल रही हो। इस स्पीड से गाड़ी चल रही है। आपने 14 माह में 14000 करोड़ रुपये लोन ले लिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान सुक्खू सरकार ने वर्ष 2023-24 में 5506 करोड़ रुपये और वित्तीय वर्ष 2024-25 में 5507 करोड़ रुपये ही लोन की रिपेमेंट के लिए रखे हैं। एक तरफ सरकार कह रही है कि हम लोन व उसके ब्याज के लिए लगभग 16 प्रतिशत अदायगी करेंगे। यदि हम 16 प्रतिशत का हिसाब लगाएं तो वह 8000 करोड़ रुपये से ज्यादा बनता है। लेकिन इसके लिए बजट प्रावधान लगभग 5500 करोड़ रुपये ही रखा गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि शेष धनराशि कहां से लाई जाएगी? इस प्रकार से सरकार

के ये आंकड़े आपस में ही कंफ्लिक्ट कर रहे हैं। इस प्रकार सरकार की हकीकत पर से पर्दा उठ रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, बजट में सरकार ने लगातार झूठ बोला है। झूठ बोलने की यह कला आपकी बहुत गजब की है। आपने सत्ता में आने से पहले जनता को 10 गारंटियां देकर झूठ बोला। सत्ता में आने के बाद आपने अपना पहला बजट प्रस्तुत किया और उसमें बहुत सारी झूठी घोषणाएं कीं। मैं मानता हूं कि चुनाव से पहले जो आपकी पार्टी का घोषणा पत्र था वह एक राजनीतिक दस्तावेज़ था। लेकिन बजट तो सरकार का एक आधिकारिक दस्तावेज़ होता है। आपने तो अपने चुनावी घोषणा पत्र को भी नीतिगत दस्तावेज़ बनाया है। आपने जो पिछले बजट में कहा था, आप तो उसे भी नकार चुके हैं और उसमें कुछ नहीं किया है। यह हकीकत आपके सामने है। यहां पर मैं कहना चाहता हूं कि :-

यह सोचना गलत है कि तुम पर नज़र नहीं,

हम मशरूफ़ बहुत हैं लेकिन बेख़बर नहीं।

19-02-2024/1520/डी.सी.-एन.जी/2

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार में बैठे लोग जो भी काम करते हैं वह बहुत चालाकी से करते हैं लेकिन पकड़े जाते हैं और इसीलिए मैंने यह शेर कहा है। मेरा मन कर रहा है कि मैं यहां पर सरकार के पिछले बजट का भी जिक्र करूं क्योंकि आप अक्सर वायदे करके भूल जाते हैं। आपने पिछले बजट में ग्रीन हिमाचल, ग्रीन कॉरिडोर आदि के बारे में बहुत कुछ कहा था। आज हम इन्हें दूरबीन के माध्यम से ढूंढ़ रहे हैं। आपने कहा था कि प्राइवेट बस ऑप्रेटर को ई-बस खरीदने के लिए 50 प्रतिशत या 50 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि अभी तक कितनी बसें खरीदी गई हैं? एक साल बीत चुका है।

श्रीमती के.एस. द्वारा जारी.....

19.02.2024/1525/केएस/डीसी/1

श्री जय राम ठाकुर जारी---

आपने प्राइवेट ट्रक ऑप्रेटर्ज़ को कहा कि ई-ट्रक को खरीदने के लिए आपको 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी, आपको 50 लाख रुपये का उपदान दिया जाएगा। हम भी हिमाचल में ही रहते हैं परन्तु अभी तक मुझे खबर नहीं मिल पाई कि हिमाचल प्रदेश में किसी ने ई-ट्रक खरीदा हो और वह चला हो। प्राइवेट ऑप्रेटर्ज़ के लिए आपने कहा कि चार्जिंग स्टेशन के लिए 50 प्रतिशत उपदान दिया जाएगा। हमारे पत्रकार बंधुओं ने भी उसको अच्छी तरह से कवरेज दी, अच्छी बात है कि नया इनिशिएटिव लिया। कहा गया कि आज से पहले किसी ने इस बारे में नहीं सोचा, ग्रीन हिमाचल, ग्रीन कोरिडोर, ई-बसें, हम तब भी कहते रहे कि जब आएंगी तब बात करेंगे। दूसरे, इसमें नया भी कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हो रहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी इस बारे में केंद्र सरकार की ओर से एक नहीं-अनेक प्रयत्न कर चुके हैं और मुझे लगता है कि बेहतर होता आप जा कर उनसे मिलते और इस कन्सैप्ट को उनके सामने रखते तो निश्चित रूप से वे आपको सलाह भी देते और सहयोग भी देते। लेकिन आपने तो एक ही बात करनी है क्योंकि लम्बे समय तक आप पार्टी के पदाधिकारी रहे हैं, पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, मुख्य मंत्री जी, आपको तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी काम अच्छा नहीं लगता । हमें आज इस बात की प्रसन्नता है कि आज पूरे देश में इस तरह का एक वातावरण है, केवल भारतीय जनता पार्टी ही नहीं चाहती कि नरेन्द्र मोदी जी दोबारा प्रधान मंत्री बने, पूरा देश चाहता है, पूरी दुनिया चाहती है कि नरेन्द्र मोदी जी फिर से देश के प्रधान मंत्री बने।

उपाध्यक्ष महोदय, ग्रीन हाईड्रोजन की बातें हुईं थीं। ये पुरानी बातें हो गईं। पिछली बार आपने कहा था। अगर आपने उसमें इनिशियेटिव्ज़ लिए होते तो भी हम आपको मानते। हमारी सरकार ने जो हैलीपोर्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू की थी। कुल मिलाकर आपके अब के बजट में भी वही ज़िक्र है, उसमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है। उसमें आपने कुछ एडिशन

नही किया है, आपने नाम का ज़िक्र किया है रामपुर, बद्दी, कांगणीधार, और मनाली का जो हेलीपोर्ट है, उसमें आपने कहा था कि हेली टैक्सी चलाएंगे। एक साल बीत गया, जो हमारा पवन हंस का हेलीकॉप्टर चलता था, जो चण्डीगढ़ से शिमला, शिमला से कुल्लू, शिमला से मण्डी और मण्डी से धर्मशाला, शिमला से धर्मशाला जाया करता था, वह बीते जमाने की बात हो गई। वह बंद हो गया

19.02.2024/1525/केएस/डीसी/2

है। आप पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। आपने पिछले बजट में भी कहा कि धर्मशाला को आप टूरिज्म कैपिटल बनाएंगे। एक साल बीत गया लेकिन कोई एक भी काम ऐसा नहीं हुआ जिससे आभास हो कि धर्मशाला के लिए पर्यटन की दृष्टि से आपने कोई काम किया हो। आपने वहां पर ज़ू खोलनेकी बात की है। चिड़िया तो मालूम नहीं कहां उड़ गई है। ना चिड़िया मिल रही है, ना घर मिल रहा है। यह परिस्थिति आपकी वहां की है। पर्यटन के लिए आपने पिछली बार के बजट में पैसे के प्रावधान का ज़िक्र किया था। 2000 करोड़ रुपये के प्रस्ताव का ज़िक्र था लेकिन पर्यटन के नाम पर बजट के प्रावधान का इस बजट बुक में ज़िक्र ही नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछली बार भी अगर ज़िक्र किया गया था तो वह ए.डी.बी. का प्राजैक्ट हमारा जो 2100 करोड़ रुपये का था, उसका ही ज़िक्र था। मैं आपको याद करवा रहा हूं, आपने एक बात कही कि हम आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खोलेंगे लेकिन खोले हुए संस्थान तो बंद हो गए। हिमाचल प्रदेश में गवर्नमैंट सैक्टर में हमारे 6 मैडिकल कॉलेज हैं। 6 मैडिकल कॉलेजों के अलावा एक प्राइवेट सैक्टर में है। कितने डॉक्टर्ज़ एक साल में वहां से निकलते हैं?

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी----

19.02.2024/1530/एवी/एचके/1

श्री जय राम ठाकुर------ **जारी**

हर साल हमारे 700-800 बच्चे डॉक्टर बनकर निकलते हैं। हमारी सरकार ने अपने कार्यकाल में 500 डॉक्टर्ज की पोस्ट्स क्रिएट की थीं और उसमें से 300 पोस्टें भर भी दी थीं। उसके बाद बाकी 200 पोस्ट्स को भरने के लिए हमने प्लान बनाया हुआ था। आपकी सरकार को बने एक साल का समय हो गया है परंतु अभी तक एक डॉक्टर की पोस्ट नहीं भरी गई। पोस्ट्स को तो क्या भरना आपने तो उनका एन0पी0ए0 भी बंद कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में ऐसी स्थिति थी कि फाइनल ईयर का परिणाम आते ही वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से उसकी नौकरी लग जाती थी। परंतु एक साल से एक डॉक्टर की भर्ती नहीं की गई उलटे हिमाचल प्रदेश के उन बच्चों को जिन्होंने एजुकेशन लोन लेकर के पढ़ाई की है। ऐसे बच्चे जो पढ़ने को अच्छे थे परंतु पढ़ाई करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, वे बच्चे लोन लेकर पढ़े हैं मगर उसके बावजूद आज वे दर-दर की ठोकरे खा रहे हैं। उन बच्चों का तो भविष्य ही बर्बाद हो रहा है और ऊपर से आप उनके लिए नौकरी नहीं दे रहे हैं। एक पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर 7 साल पढ़ाई करने के बाद मिलता है और एन0पी0ए0 बंद करने के बाद उसको 35,000 रुपये सैलरी मिलेगी। इस प्रकार से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। माननीय मुख्य मंत्री जी, आप अपने उत्तर के दौरान इन आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों के बारे में भी बताएं। आपने चम्बा, नाहन और हमीरपुर मेडिकल कॉलेजिज में नर्सिंग कॉलेज खोलने की घोषणा की थी हालांकि उसका केंद्र सरकार की योजना तहत प्रावधान था। आपने फिर सभी मेडिकल कॉलेजिज में पैट स्कैन मशीन लगाने की बात कही। अभी तक केवल आई0जी0एम0सी0 में ही इस मशीन को लगाने की प्रक्रिया पूरी हुई है हालांकि वह प्रक्रिया हमारी सरकार के कार्यकाल में ही शुरू हो गई थी। लेकिन अभी तक भी वह फंक्शनल नहीं हुई है और मरीजों को अभी भी चण्डीगढ़ जाना पड़ता है। आपकी सरकार का एक साल का कार्यकाल बीत गया है तो कृपया करके यह बताएं कि बाकी मेडिकल कॉलेजिज में आप पैट स्कैन मशीन कब लगाएंगे। हमारी सरकार ने प्रदेश में अटल जी के नाम से अटल आदर्श विद्यालय खोले थे। ठीक है, मैं मानता हूं कि शुरुआत करने के लिए थोड़ा समय लगता है। परंतु आपको नाम अच्छा नहीं लगा और आपने नाम बदलकर उसका नाम राजीव गांधी मोडल डे बोर्डिंग स्कूल

19.02.2024/1530/एवी/एचके/2

कर दिया। आपने पिछले बजट में बहुत सारी घोषणाएं की हैं और आपका पिछला बजट भाषण मेरे बहुत काम आया है। मैं वर्तमान बजट भाषण से ज्यादा इसको (हाथ में पिछले साल की बजट बुक दिखाते हुए कहा।) पढ़ रहा हूं। आपने बजट भाषण में कहा कि मैं राजीव गांधी मोडल डे बोर्डिंग स्कूल खोलने की घोषणा करता हूं। लेकिन अभी तक हिमाचल प्रदेश के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में यह प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है और आपका पूरा एक साल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आपको अपने नाम से योजना का नाम रखने में कुछ आन्नद आ रहा है और आना भी चाहिए क्योंकि उसके साथ आपका नाम हमेशा के लिए जुड़ रहा है। आपने पिछले बजट के दौरान मुख्य मंत्री सुख आश्रय योजना शुरू की थी और इस बार मुख्य मंत्री सुख-शिक्षा योजना तथा मुख्य मंत्री सुख आरोग्य योजना शुरू की है। आप योजनाएं शुरू जरूर कीजिए मगर उससे कम-से-कम सुख की अनुभूति तो होनी चाहिए। वह सुख की अनुभूति न इधर हो रही है, न उधर हो रही है और न ही बाहर हो रही है।

टी सी द्वारा जारी

19.02.2024/1535/टी0सी0वी0/एच0के0-1

श्री जय राम ठाकुर ..... जारी ।

यह सबसे बड़ी परेशानी है। जब सुख की अनुभूति ही न हो तो जिन्दगी किस काम की ? आखिर किस चीज के लिए हम काम कर रहे हैं? सरकार किस काम के लिए है? इस सुख की अनुभूति को मित्रों तक ही सीमित मत रखो। इसको थोड़ा आगे बढ़ने दीजिए। पिछली बार आपने कहा कि हम हिमाचल प्रदेश में 30000 नौकरी देने का ऐलान करते है। अच्छा है, हमसे बहुत सारे ऐसे काम छूट गए थे और नौकरी तो ऐसा विषय है जो हर बेरोजगार

को आकर्षित करता है लेकिन एक साल बीत गया। उन 30 हजार नौकरियों का क्या हुआ? आज बेरोजगार सड़कों पर है। करुणमूलक आधार पर जो नौकरी की मांग कर रहे हैं वे भी सड़कों पर हैं। जिनको नौकरी दी हुई है, जो आउटसोर्स पर है वह भी सड़कों पर है। जिनकी पक्की नौकरी लगी है वह भी सड़कों पर है क्योंकि उनको अपना वेतन समय पर नहीं मिल पा रहा है। उनको अपनी सैलरी लेने के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। एक साल बीत गया, ना एरियर, न डी0ए0 और आपने वादा किया था कि कैबिनेट की पहली बैठक में हम ओ0पी0एस0 लागू करेंगे। लेकिन यह भी तो हकीकत है कि बहुत सारे लोगों को आपने चाहे वे बोर्ड या कारपोरेशन के कर्मचारी हैं जिनको आपने कह रखा था कि हम सत्ता में आएंगे तो आपको भी ओ0पी0एस0 लागू करेंगे परंतु अब उनकी गिनती ही नहीं कर रहे हैं। उन इलैक्टिसिटी बोर्ड और एच0आर0टी0सी0 के कर्मचारियों का क्या होगा? हालांकि उनकी पेंशन पॉलिसी अलग है लेकिन उसके बावजूद वे भी मांग कर रहे हैं। आप लोग कहते हैं कि हम कर्मचारी हितैषी हैं । हमने कहा बहुत अच्छी बात है लेकिन कर्मचारी विरोधी तो हम भी नहीं । हम हकीकत के साथ खुद भी जी रहे थे और हकीकत के साथ उन लोगों को भी जीने के लिए कह रहे थे जो वर्तमान में हमारे सामने परिस्थिति है। लेकिन आपने कहा नहीं, हम यह करेंगे। ओ0पी0एस0 लागू करने का ऐलान तो आपने कर दिया और उसके बाद आप कह रहे हैं कि 9000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार आपको दें लेकिन उसके बारे में केन्द्र सरकार ने आपको स्पष्ट कर दिया है कि वह पैसा आप नहीं मांग सकते। वह पैसा स्टेट गवर्नमेंट के खाते में थोड़े ही देंगे। जो कर्मचारी रिटायर होगा वह उसके अकाउंट में जाएगा क्योंकि अभी तक उसके अकाउंट से पैसा जाता था, वह पैसा उसकी सैलरी से जाता था। वह उसके लिए पात्र होगा लेकिन आप क्या चाह रहे कि वह पैसा सीधा आपके खाते में जमा कर दिया

जाए। कुछ तो समझ हमारे मित्रों को आ जानी चाहिए । अब उनको लग रहा कि गलत हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर से कह रहा हूं कि यह बजट है, यह निकल जाएगा। इसके बाद लोकसभा का चुनाव है उसके बाद यह जो ओ0पी0एस0 वाला मसाला है इसके बारे में

मेरी पूरी जानकारी है, पुख्ता जानकारी है कि ओ0पी0एस0 आने वाले समय में जब लागू करने की बात आएगी तो लास्ट पे ड्रोन का 50% नहीं देंगे। यह उसका 40, 30 या हो सकता उससे भी नीचे 20-25 प्रतिशत पर चले जाएं। इसलिए मेरा प्रदेश के कर्मचारी भाइयों से निवेदन है कि जब ये हमसे झूठ बोल सकते हैं, प्रदेश की जनता से बोल सकते हैं तो यह झूठ आपके साथ भी बोल सकते हैं। आपने जो ठग शब्द कहा है, हम तो ठग है लेकिन आप तो महा ठग है। मझे मालूम नहीं कि यह शब्द उचित है या नहीं आप देख लें लेकिन झे लग रहा है कि इसे आपने उपयोग किया है, आपका एक्सपंज नहीं हुआ तो मेरा भी एक्सपंज नहीं होगा।

एन0एस0 द्वारा जारी ।

19-02-2024/1540/एन0एस-वाई0के0/1

श्री जय राम ठाकुर ------जारी

मैं गारंटियों पर बात करूंगा। ये गारंटी गले की घंटी और गले की फांस बन गई है। ये गले से बाहर नहीं आएगी और ये लटकी रहेगी। आपने जो गारंटियां दी हैं शायद अब आपको इस बात का आभास हो गया कि यह संभव नहीं है और हम इनको पूरा नहीं कर सकते हैं। मैंने आपको कहा था कि आप इनको 10 जन्मों तक भी पूरा नहीं कर पाएंगे। पिछले बजट में आपने कहा था कि हमारी सरकार आई है और हमारी गारंटी है कि प्रदेश में 18 से 60 साल की महिलाओं को 1500 रुपये देंगे। उसके बाद फिर झूठ बोला। मुझे लगता है कि फिर ठगने का काम किया। 2,37,000 महिलाओं को आंकड़ा निकाला गया। पिछले बजट में कहा गया कि इन महिलाओं को हमारी सरकार 1500 रुपये देगी जिनको पहले ही सरकार 1000 रुपये और 1150 रुपये पेंशन दे रही थी। आपने उस आंकड़े को निकाल कर कहा कि कुछ में 500 रुपये और कुछ में 350 रुपये डालेंगे तथा हमारी गारंटी पूरी हो जाएगी। यहां पर लाहौल स्पिति के विधायक नहीं हैं। आपका इनके साथ कुछ विवाद हुआ और बाद में आपने उनको हाथ पकड़ कर मनाया क्योंकि उन्होंने कोई चिट्ठी लिख दी थी तथा अखबार में कोई खबर भी आई थी। आप स्पिति घाटी में गए औरआपने वहां भी पूरी ठगी की व झूठ बोला। वहां बहुत ही पिछड़े लोग हैं जो ट्राइबल में रहते हैं । आपने 15 अप्रैल को घोषणा की

कि जितनी भी महिलायें स्पिति में है मैं उनको 1500 रुपये देने की घोषणा करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इनको मालूम है कि सबसे कम महिलाएं स्पिति में हैं। इन्होंने वहां से घोषणा की। इन महिलाओं को मिला कर यह आंकड़ा लगभग 2,37,000 पहुंचा है। अभी कहा कि अब हम देना शुरू करेंगे। एक साल पहले की घोषणा थी। दिनांक 15 अप्रैल, 2023 की घोषणा थी और अगला अप्रैल आने वाला है लेकिन अभी तक यह पैसा उनको नहीं मिला।

उपाध्यक्ष महोदय, जो यह बजट पेश किया गया है इसमें हम देख रहे हैं कि आपकी सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि जो विषय हमने शामिल करने के लिए कहा था और बजट का हिस्सा होना चाहिए था, वे मिसिंग हैं। यह किस स्तर पर हुआ? यह मुख्य मंत्री जी के स्तर पर हुआ या अधिकारियों के स्तर पर हुआ या सरकार के स्तर पर हुआ? इस पर मुख्य मंत्री जी ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। मुख्य मंत्री जी की एक खासियत है कि ये कम बोलते हैं लेकिन इन सारे विषयों पर बोलना पड़ेगा। यह आपके

19-02-2024/1540/एन0एस-वाई0के0/2

सामने बहुत बड़ा प्रश्न है। आपकी ही सरकार के दौरान अगर आपके मंत्री बजट से संतुष्ट नहीं हैं तो कौन संतुष्ट है? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। उपाध्यक्ष महोदय, गारंटियों में बेरोजगारों के लिए भी कहा गया था। पिछली बार 30,000 नौकरियों की बात की गई थी लेकिन इस बार नौकरियों की कोई बात नहीं की गई। इस बार एक नौकरी का भी जिक्र नहीं किया गया। आप कितनी नौकरियों देंगे, इसका कोई टारगेट या लक्ष्य होगा? ये सब मिसिंग है। आपने शायद अनुभव से सीखा होगा कि पिछली बार हमसे गलती हो गई और हमने गलत कह दिया तथा हमसे नहीं हुआ। इसलिए इस बार हम नहीं कहेंगे। जो किया नहीं जा सकता उसको कहना ही नहीं हैं।

आर0के0एस0 द्वारा ------जारी

19.02.2024/1545/RKS/AS-1

श्री जय राम ठाकुर...जारी

इसलिए आपने यह तय कर दिया। मैं कहता हूं कि गलती से कुछ बातें सीखने को मिलती और शायद आपने एक बात यह सीखी होगी। आपने झूठ बोलकर यह कहा था कि जब हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी तो 5 लाख बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। आपने कहा था कि हम कैबिनेट की पहली बैठक में एक लाख नौकरियां निकालेंगे। आप मुझे बताएं कि एक साल बीत जाने के बाद आपने कितनी नौकरियां निकाली हैं? आपने जो कहा है वह तथ्य पर आधारित नहीं है। आपने 'हरित, स्वच्छ, बिजली राज्य हिमाचल, पर्यटन राज्य हिमाचल, स्वस्थ, शिक्षित, कुशल एवम दक्ष, हिमाचल' और कई अन्य बातों का जिक्र किया है। आपने इन चीजों को पूरा करने के लिए क्या विजन रखा है? आप 'हरित, स्वच्छ, बिजली राज्य हिमाचल, पर्यटन राज्य हिमाचल, स्वस्थ, शिक्षित और कुशल एवम दक्ष, हिमाचल' के लिए क्या करेंगे? हिमाचल के बारे में एक ऐसी धारणा थी कि यहां बहुत सारी चीजें की जा सकती थीं लेकिन आज यह करने के लिए कोई आदमी भरोसे के साथ नहीं कह सकता। हम हिमाचल प्रदेश में उद्योग लाए। आपने बल्क ड्रग्स फार्मा पार्क की बात कही। इसके संदर्भ में यह कहा जा रहा है कि हमने हिमाचल प्रदेश की जमीन दे दी। मैं आपको कहना चाहूंगा कि इसके लिए competitive bid हुई है। स्वाभाविक रूप से बड़ी चीज को हासिल करने के लिए प्रदेश की सभी सरकारों ने ऑफर दी थी। इस बल्क ड्रग्स फार्म पार्क के स्थापित होने से हिमाचल प्रदेश के कितने बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा इस बात को आप नहीं देख रहे हैं। आप इस बात को नहीं देख रहे हैं कि इस बल्क ड्रग्स फार्म पार्क में जब काम शुरू होगा तो हिमाचल प्रदेश में कितनी इंडस्ट्रीज आएंगी? जो प्राइवेट सैक्टर का इंवेस्टमेंट हिमाचल प्रदेश में आएगा उससे हिमाचल प्रदेश की ग्रोथ में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूट होगा। जो आपकी विरोधाभासी बातें हैं वे बहुत हैरानी पैदा करती है। आप इंडस्ट्री लाने के लिए दुबई जाकर आए। उद्योग मंत्री जी भी इंडस्ट्री लाने के लिए दुबई गए थे लेकिन मुझे मालूम नहीं कि आप वहां से क्या लेकर आए? अगर हिमाचल प्रदेश में प्राइवेट सैक्टर का इंवैस्टमेंट लाना है तो हमें अपने प्रतिस्पर्धी पड़ोसी राज्यों से अच्छी सुविधा यहां देनी होगी। लेकिन हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए

हमें यहां से वहां इंडस्ट्री जाती दिख रही है। पहले यहां एक माहौल था जो उद्योपतियों को हिमाचल में आने के लिए आकर्षित करता था लेकिन

19.02.2024/1545/RKS/AS-2

आज वह वातावरण नहीं है। आज यहां गुंडागर्दी और लूट-खसूट हो रही है इसलिए उद्योगपति हाथ जोड़कर हिमाचल प्रदेश से बाहर जा रहे हैं। ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ था। यहां का हवा-पानी बहुत अच्छा है इसलिए उद्योगपति यहां आना चाहते हैं। यहां पर एश्योर्ड पावर सप्लाई मिलती है लेकिन आप पावर टैरिफ में लगातार इंक्रीज कर रहे हैं और जहां पड़ोसी राज्यों में बिजली पैदा नहीं होती वे हमसे सस्ते रेट में उद्योगपतियों को बिजली दे रहे हैं। इसलिए उद्योगपति उन्हीं राज्यों में अपने उद्योग स्थापित करेंगे।

श्री बी.एस.द्वारा... जारी

19.02.2024/1550/बी.एस./ए जी/-1

श्री जय राम ठाकुर जारी...

आखिरकार यह परिस्थिति कहने से नहीं बदलेगी इसे आपको व्यावहारिक रूप से देना होगा। थाड़ी बहुत चीजों को ले करकें बातें आएंगी। (...घंटी) उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो मैं पुराने बजट पर ही नजर डाल रहा था, अभी तो नया गजट बाकी है।

उपाध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष, कृपया समय का ध्यान रखें, क्योंकि आपको बोलने के लिए 45 मिनट दिए गए थे वह पूरे हो चुके हैं।

श्री जय राम ठाकुर : पिछली बारह आपने जो बातें कहीं थीं मेने कहने का अभिप्राय है कि आप उसमें खरे नहीं उतर पाये हैं। उसी तरह से अगर आज हम आगे बढ़ करके बात करें तो मैं देख रहा हूं कि आपके छोटे-छोटे इंक्रीजिज की हैं जैसे आंगनबाड़ी वर्कर्ज और आंगनबाड़ी सहायिका के मान देय में आंशिक रूप से बढ़ोतरी की है परंतु ये तो सब रूटीन की चीजें हैं और आपने थोड़ा प्रयत्न किया है कि आने वाले वक्त में हमारे पास

परिस्थितियां है कि लोक सभा चुनाव आ गया। इस लोक सभा के चुनाव में हमें किस प्रकार से सामना करना है। वह भी अपने आप में आपके लिए परेशानी का सबब है।

अगर मैं लोक निर्माण विभाग की बात करूं, मैं इस बात से सहमत हूं कि इस बार त्रासदी के कारण बारिश के मौसम में लोक निर्माण विभाग को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और जिस प्रकार से बजट में भी जिक्र किया गया है। लेकिन यह भी सही है कि हमारे लिए हिमाचल प्रदेश में सड़क एक मात्र माध्यम है जिससे लोगों की पीठ का बोझ कम किया जा सकता है। इसके अलावा प्रर्यटन को उनके डैस्टिनेशन तक पहुंचाने का यही माध्यम है। परंतु आज सड़कों की हालत आप देख रहे हैं कि इनकी क्या हालत है? आज 40,703 किलामीटर सड़कें हिमाचल प्रदेश में है और मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का हम कभी भी अहसान चुकता नहीं कर सकते हैं। क्योंकि 40,703 किलोमीटर सड़कों में से 20,000 किलोमीटर सड़कें प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत बनी हैं। यह श्रेय सचमुच उनकों जाता है। अगर हम स्टेट के बजट में से नार्बाड द्वारा या वर्ल्ड बैंके के माध्यम से सड़कें बनीं होती तो आज भी मेरे हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे गांव सड़कों के बिना होते। गांव के लोगों की पीठ का बोझ यदि उतरा है तो उसका श्रेय हमारे पूर्व प्रधान मंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाता है जिन्होंने इस योजना की

19.02.2024/1550/बी.एस./ए जी/-2

शुरूआत 60,000 करोड़ रुपये से पूरे देश भर में की थी। यह बहुत बड़ा उनका योगदान है। अब उसके बाद यदि हम आगे बढ़ करके बात कहें, आपने फिर वही बातें कहीं है हरित हिमाचल के बारे में भी बात कही गई है कि हम उस दिशा में काम करेंगे। परंतु उसमें आज तक कुछ नहीं हुआ है। इसके साथ-साथ उपाध्यक्ष महोदय, हम यह कहना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में विशेष तौर से जिसका जिक्र में करना चाहूंगा कि आपने जो गारंटियां दी हैं उन गारंटियों पर आप कब काम शुरू करेंगे। क्या वह आपके बजट का हिस्सा होगीं या नहीं? इस प्रकार के हालात लग रहे हैं कि आपने जो गारंटियां दी है वे गारंटियां पूरा करने के लिए इस डाकुमेंट में कोई जिक्र नहीं है। कहीं भी उन बातों का जिक्र नहीं है। आपकी गोबर की गारंटी का कुछ नहीं हुआ आपने कहा था 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। लेकिन उसके बावजूद उसका कुछ नहीं हुआ। एक चीज को आपने थोड़ सा छूने की कोशिश है।

परंतु आपने गारंटी तो दी थी कि गाय का दूध 80 रुपये किलो और भैंस का दूध 100 रुपये किलो लिया जाएगा। लेकिन उसमें थोड़ी सी इंक्रीज करके गाय का दूध 45 रुपये और भैंस का दूध 55 रुपये किलो ले करके आपने अपनी घोषणा को छूने की कोशिश की है। परंतु अब छूने से बात नहीं बनेगी यह तो आपने गारंटी दी है यदि इन्हें अब पूरा नहीं करेंगे तो कब पूरा करेंगे? उसी तरह से उपाध्यक्ष महोदय, आगे बढ़ करके अब यहां पर देखें।

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

19.02.2024/1555/डी0टी0/ए0जी0/1

श्री जय राम ठाकुर जारी...

उपाध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं। उनके बारे में आपने अपने बजट भाषण में घोषणा कि लेकिन वह एक छोटी सी घोषणा है उससे उनका कुछ नहीं बनने वाला क्योंकि वह लोग पोलिसी की मांग कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय मैं यहा पंर हिमाचल प्रदेश स्टाफ स्लैक्शन कमीशन, हमीरपुर का उल्लेख एक बार फिर से करना चाहूंगा। इस संस्थान में जो अलग-अलग पोस्ट कोडस के परिणाम रूके हुए हैं और जिसके कारण भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हो रही हैं, आप कृप्या उन परिणामों को घोषित करवाईये और साथ में अब नया कमीशन को भी खोल दीजिए। जो नौजवान आज धरने पर बैठे हैं उनका परिणाम निकलना चाहिए। कई तो ऐसे मामले भी हैं जिसमें बच्चों ने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद टाईपिंग टैस्ट भी क्लीयर कर लिया है। लेकिन उसके बाद भी उनके रिजल्ट नहीं निकाले जा रहे। उनके बारे में तो कम-से-कम आपको सोचना चाहिए। एक प्रश्न आज इस माननीय सदन में भी लगा था जिसको देखकर मुझे बहुत विचित्र लगा, उत्तर में कहा गया कि सूचना एकत्रित की जा रही है। करूणालमुलक आधार पर नौकरी पाने वाले अभ्यर्थी लंबे समय तक हमारी सरकार के के दौरान भी धरने में बैठे थे, लेकिन आपने तो उनकी बात सुनना ही बंद कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, अब सरकार ने बागवानों से कहा था कि हिमाचल प्रदेश में सेब की कीमत बागवान ही तय करेंगे। आपकी इस कही हुई बात का क्या हुआ? हम तो बार-बार यही कह रहे है कि

जो आपने जनता को गांरटी दीं हैं उन्हें पूरा करो। मैं यह भी कहना चाह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में खासतौर से इस सरकार के पिछले एक साल के कार्यकाल में जो हालात बने हुए हैं वे ठीक नहीं है। वर्तमान सरकार द्वारा जो संस्थान बंद कर दिये गये हैं उनका कोई भी जिक्र इस बजट बुक में नहीं है। मुख्य मंत्री जी अपने हिसाब से जाकर कहीं भी घोषणा कर देते हैं। लेकिन आपके बजट में भी नए संस्थान खोलने का कहीं जिक्र कहीं नहीं है और आप हमसे कहते रहते थे कि आप कि बजट में ऐसा कोई जिक्र नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर कहना चाहता हूं किः

19.02.2024/1555/डी0टी0/ए0जी0/2

टूटने लगे हैं कांच तेरी खिड़कियों के,

ये याद रखना कि जनता जाग रही है॥

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग में बहुत से ऐसे काम है जिनका टैंडर का प्रौसेस कम्प्लीट होने के बाद टैंडर अवार्ड भी हुआ, अवार्ड होने के बाद काम पूरा भी कर दिया गया, लेकिन उन ठेकेदारों को पिछले 14 महीने से पेमेंट नहीं दी गई, उनकी पेमेंट रूकी हुई है। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा की पेमेंट तो की जा रही है पर पेमेंट चुन-चुन कर दी जा रही है। उन लोगों के लिए कहा जा रहा है कि तुम लोग कांग्रेस पार्टी ज्वाईन कर लो तब तुम्हारी पेमेंट रिलीज हो जाएगी। हद तो तब हो गई जब कांग्रेस पार्टी के ही कुछ नेता यह कहने लग पड़े कि कितनी की पेमैंट है, उसमें से इतना हिस्सा अगर हमें दोगे

श्री एन0जी0 द्वारा जारी....

19-02-2024/1600/ए.एस.-एन.जी/1

श्री जय राम ठाकुर .....जारी

उसके बाद आपकी पेमेंट जारी करेंगे। यह हालात हिमाचल प्रदेश में बन चुके हैं। यह आख़िर हो क्या रहा है? हिमाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार की सभी सीमाएं टूट गई हैं। आज मैं इस बात को जरूर कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार की योजनाएं के बलबुते पर ही हिमाचल प्रदेश थोड़ा-थोड़ा आगे सरक रहा है अन्यथा यदि हिमाचल प्रदेश केवल आपके भरोसे होता तो मालूम नहीं हिमाचल प्रदेश किस कदर ठहर जाता या पीछे की ओर चला जाता। आज केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में जो 90:10 का शेयर मिल रहा है वह इसलिए मिल रहा है क्योंकि देश के यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने वर्ष 2014 में प्रधान मंत्री बनने के बाद हिमाचल प्रदेश को उस कैटेगरी में डाला जिसमें नॉर्थ-इस्ट के राज्य व उत्तराखण्ड शामिल हैं। हम इस बात से सहमत हैं कि प्रदेश में आर्थिक तंगी है। ...(घण्टी)... मैं आपको कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार और पूर्व सरकार को कोसना छोड़ दीजिए। अब अपने काम की बात कीजिए।

उपाध्यक्ष : माननीय श्री जय राम ठाकुर जी, कृपया वाइंडअप कीजिए।

श्री जय राम ठाकुर : उपाध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के हमारे मित्रों में अपने काम का जिक्र करने की हिम्मत नहीं है। प्रदेश सरकार ने सत्ता में आने के बाद डीज़ल की कीमतें दो बार बढ़ाई हैं। डीज़ल की कीमतें बढ़ने से गरीब आदमी पर महंगाई का बोझ सीधा पड़ता है। आज हिमाचल प्रदेश का बेरोज़गार युवा सड़कों पर है। नौकरी पर लगा हुआ कर्मचारी सड़कों पर है। मास्टर और बच्चे भी सड़कों पर हैं। एक साल में ही इस प्रकार की परिस्थिति क्यों बन गई है? इसकी एक ही वजह है कि हिमाचल प्रदेश सरकार अपने किए हुए वायदों को पूरा न करने की परिस्थिति में पहुंच गई है और पूर्ण रूप से असफल सरकार साबित हुई है।

(अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

19-02-2024/1600/ए.एस.-एन.जी/2

अध्यक्ष महोदय, सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले बजट पेश करके कुछ झूठे वायदे करने की कोशिश की है ताकि लोकसभा चुनाव में लोगों के सामने जाकर वोट लिए जा सकें। सरकार ने पिछले वर्ष बहुत शोर डाला कि एक्साइज़ के राजस्व में हमने 40 प्रतिशत की बढ़ौतरी की है। वर्तमान वित्तीय वर्ष समाप्त होने की दिशा में बढ़ रहा है। आज एक प्रश्न के उत्तर में सरकार ने कहा है कि एक्साइज़ का राजस्व 1855 करोड़ रुपये प्राप्त हुआ है। इस राजस्व का आंकलन करने पर हम पाएंगे कि यह बढ़ौतरी केवल 16-17 प्रतिशत ही बनती है। सरकार के 40 प्रतिशत आंकड़ों के अनुसार अभी तक लगभग 2500 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्त होना चाहिए था। इस माह तक लगभग 400 करोड़ रुपये राजस्व घाटे में चल रहा है और इसे कैसे पूरा किया जाएगा? सरकार ने शोर तो बहुत डाला कि हमने ओपन बीडिंग की और उसके बहुत बड़े-बड़े कलस्टर बना दिए। मैं कहना चाहता हूं कि इसकी वजह से आपने बड़े ठेकेदारों को लाभ दिलवाने की कोशिश की है। आपने जो पॉलिसी लाई है, उसी प्रकार की पॉलिसी दिल्ली में केजरीवाल ने लागू की थी। आज उनके तीन मंत्री जेल की सलाखों की पीछे चले गए हैं और आने वाले समय में यही परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में भी बनेगी। आपने जो कोटा तय किया है उसकी लिफटिंग ही नहीं हो पा रही है। मेरे पास जो जानकारी है उन आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष केवल लगभग 8 प्रतिशत की लिफटिंग इंक्रीज़ हुई है। अंग्रेजी शराब में पीछले वर्ष की तुलना में 11.60 प्रतिशत लिफटिंग कम हुई है और बियर की लिफटिंग में भी 12.5 प्रतिशत की कमी आई है।

श्रीमती के.एस. द्वारा जारी.....

19.02.2024/1605/केएस/एएस/1

श्री जय राम ठाकुर जारी----

जब लिफ्टिंग ही कम हुई है तो आप किस बात का ज़िक्र किए जा रहे हैं? आप ज़िक्र कर रहे हैं कि हम 40 परसेंट इन्क्रीज़ के साथ बहुत सारा रेवन्यू कलैक्ट कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हकीकत यह है कि एक्साइज़ में जितना रेवन्यू आता था उससे ज्यादा नहीं बल्कि कम रेवन्यू अब की बार आ रहा है और यह हकीकत है। जब आपके पास रिसोर्सिज़ हैं, जो आप रिसोर्स जनरेट करने की झूठी बातें कह रहे हैं तो सैलरी क्यों रुकी हुई है, डी.ए. क्यों रुका है, एरियर्ज़ क्यों रुके हैं, विकास के कार्य क्यों रुके हैं? आप सभा में जाते हैं और हर जगह यही कहते हैं कि हम आर्थिक बदहाली के दौर से गुज़र रहे हैं। ये जो 1000 संस्थान आपने बंद किए हैं ये क्यों नहीं खुल पा रहे हैं? उसकी वजह हमें बताएं। झूठे आंकड़ों के आधार पर आपने इस बजट को प्रस्तुत तो किया है लेकिन मैं समझता हूं कि यह बजट पूर्ण रूप से दिशाहीन है। इसमें ना प्रदेश के बेरोज़गारों को राहत है, ना कर्मचारियों के लिए राहत की कोई उम्मीद है, ना बागवानों को राहत की उम्मीद है, ना किसानों को राहत की उम्मीद है और ना ही समाज के गरीब मज़दूरों को इससे राहत की उम्मीद है। यह पूर्ण रूप से दिशाहीन है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए इस बजट का समर्थन करने में मैं पूरी तरह से असमर्थ हूं। मुझे मालूम नहीं कि आने वाले समय की परिस्थितियां क्या होंगी लेकिन यह हकीकत है कि हिमाचल प्रदेश में एक साल के कार्यकाल में सरकार प्रदेश का बहुत बड़ा नुकसान कर चुकी है क्योंकि विज़न नहीं, दिशा नहीं, काम करने की नीयत नहीं, काम करने की नीति नहीं और इस कारण से हमारा हिमाचल पिछड़ता नज़र आता है जिसका हमें बहुत ज्यादा अफसोस है। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष : ठाकुर साहब, हमने आपको खुला समय दिया। 1 घंटा 2 मिनट आप बोले।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय आपकी सीट पर विराजमान थे और आप समय के अनुसार देख भी लेना, जय राम जी एक घंटा दो मिनट बोले लेकिन हमने इनकी स्पीच में कोई व्यवधान नहीं डाला। इसलिए जब हम बोलेंगे तो आपने भी नहीं डलवाना। दूसरा, मैं माननीय विपक्ष के माननीय नेता से यह जानना चाहूंगा कि कहां पर, किस ठेकेदार की पेमेंट नहीं हो रही है? जिस समय मैं इस चर्चा का उत्तर

दूंगा, उस दौरान आप मुझे बता देना या लिखकर दे देना ताकि हमारी जानकारी में हो कि किस डिविजन में किस ठेकेदार की पेमेंट नहीं हुई है। **अगर नहीं हुई होगी तो उस बारे में हम देखेंगे और पेमेंट कर देंगे।** ...(व्यवधान) बिक्रम सिंह जी, अभी आपने चर्चा में भाग लेना हैं। आप फैक्ट्स के साथ आएं। ऐसे ही सरेआम बोल देना कि पैसे ले रहे हैं, यह कोई बात नहीं होती। आप कोई रिकॉर्डिंग लाएं, कोई प्रूफ लाएं तो हम देखेंगे। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष : बिक्रम सिंह जी, मैंने आपको अलाउ नहीं किया है। आप बैठिए। मुख्य मंत्री जी अभी जवाब दे रहे हैं। अभी आप बैठिए। उसके बाद आपने हाथ खड़ा कर लेना, मैं आपको समय दूंगा।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष जी, पूर्व मुख्य मंत्रीजी ने जो अभी बोला था, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। धन्यवाद।

श्री बिक्रम सिंह : अध्यक्ष जी, अख़बारों के माध्यम से खुद हमने प्रैस कॉंफ्रेंस करके विधान सभा के अंदर यह कहा है, अपनी स्पीच में भी कहा है कि आपके एक पदाधिकारी की पिटाई की गई। जिस समय वह पी.डब्ल्यू.डी. का ठेका लेने गया उससे 10 परसेंट पैसे मांगे गए कि पहले 10 परसेंट दो तब हम आपको ठेका देंगे। फिर वह आपसे मिला और आपने स्टेज पर बुलाकर उससे बात की और कहा कि एस.पी. साहब से बात करवाते हैं। उसके बारे में मैंने कहा। आप कहते हैं कि सारी बातें मुझे बताया करो। अब हम आपको बात बताते हैं तो आप कहते हैं कि मुझे दोबारा बताओ तो दोबारा कितनी बार बताएं? इसकी इन्क्वायरी करिए।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी----

19.02.2024/1610/एवी/डीसी/1

श्री बिक्रम सिंह ------ जारी

यह लोक निर्माण विभाग के सब-डिवीजन डाडा-सीबा की बात है। उस लड़के का नाम श्री जीवन धीमान है जिसकी पिटाई हुई है।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सरकारें जुबानी नहीं चलतीं, लिखित रूप से चलती हैं। माननीय पूर्व मंत्री **श्री बिक्रम सिंह जी अगर मुझे लिखित रूप में देंगे तो मैं इस पर कार्रवाई करूंगा।**

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्री भवानी सिंह पठानिया जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री भवानी सिंह पठानिया : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा पेश किए गए बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

हमने अभी नेता प्रतिपक्ष जी का 1.02 घंटे का भाषण सूना। अभी हमारी सरकार के कार्यकाल के लगभग 4 साल और बचे हैं, तो मैं एक छोटे से शेर के साथ अपनी बात शुरू करना चाहूंगा कि :-

चिरागों को आंखों में महफूज़ रखना,
बड़ी दूर तक रात-ही-रात होगी।

(उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

अभी हमारी सरकार को एक ही साल का समय हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने बोलने के लिए पहली बार खड़ा हुआ हूं और जैसे कि यहां पर आशीष बुटेल जी ने कहा तो मुझे भी आपके सामने बोलते हुए खुशी की अनुभूति हो रही है।

मैं सबसे पहले आपका ध्यान एक आंकड़े की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। वर्ष 2014 से जो हमारी अर्थव्यवस्था रही है उसमें एक छोटी-सी अनॉमली देखने को मिली है। हम थ्री, फोर और फाइव ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं। लेकिन यदि आप इन बड़े-बड़े आंकड़ों के नीचे की भयावह स्थिति को देखेंगे तो पता चलेगा कि आज की डेट में किस प्रकार की बदहाली का दौर चल रहा है। हमारे देश की लगभग 160 करोड़ जनसंख्या है और मैं यहां पर एक उदाहरण देना चाहूंगा कि टॉप एक प्रतिशत हिन्दुस्तानी हमारी लगभग 22 प्रतिशत नेशनल इन्कम पर बैठा हुआ है। 10 प्रतिशत

हिन्दुस्तानियों के पास लगभग 60 प्रतिशत नेशनल इन्कम है। 10 प्रतिशत हिन्दुस्तानी यानी 16 करोड़ के पास 60 प्रतिशत नेशनल इन्कम है। अगर इसको वैल्थ के हिसाब से देखा जाए यानी जिसमें इन्कम के साथ-साथ धन-दौलत, जमीन इत्यादि सब कुछ आता है तो टोप 10 प्रतिशत हिन्दुस्तानियों के पास इस नेशन की लगभग 70 प्रतिशत वैल्थ है। यह डिस्पेरिटी पिछले दस वर्षों से न केवल बढ़ती जा रही है बल्कि सुरसा की तरह यह एक बहुत ही विकराल रूप धारण कर चुकी है। इसके बाद आपको यह सुनने को मिलेगा कि देश की खुशहाली बढ़ रही है। अपने मुंह से हरेक नेशनल नेता ने यह चीज बोली हुई है कि आज 80 करोड़ हिन्दुस्तानी मुफ्त का राशन ले रहा है। आप यह बताइए कि क्या धना सेठ मुफ्त का राशन लेगा? 160 करोड़ की जनसंख्या में अगर 80 करोड़ जनसंख्या मुफ्त का राशन ले रही है तो इसका मतलब यह हुआ कि आज की डेट में हिन्दुस्तान की 50 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे है। अगर आप आंकड़ों को चैक करेंगे तो मुझे लगता है कि आजाद हिन्दुस्तान में यह आंकड़ा पहली बार देखने को मिला है। मैं इस इन्कम डिस्पेरिटी की भयावह स्थिति पर कुछ बोलना चाहूंगा क्योंकि यदि आप इस बजट को देखें तो हिमाचल प्रदेश एक कांग्रेस शासित राज्य है। इस कांग्रेस शासित राज्य में साधारण परिवार से उठा हुआ एक व्यक्ति जिसने संगठन से जुड़ते हुए प्रदेश के मुख्य मंत्री की कुर्सी संभाली और इस बजट में जो इन्होंने प्रस्तुत किया है, उसमें मुझे दो चीजें प्रमुखता से दिखी हैं। महात्मा गांधी जी ने दो चीजें बोली थीं कि जब भी किसी सरकारी पॉलिसी या धन को उपयोग करना चाहो तो सबसे पहले आप यह देखिए कि पंक्ति में खड़े या बैठे हुए आखिरी इंसान तक वह पहुंच रहा है या नहीं। मेरे हिसाब से यह बजट इन्कम डिस्पेरिटी को कम करने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। आप यह भी देखें कि इस बजट में सारी-की-सारी चीजें पंक्ति में बैठे हुए आखिरी इंसान तक पहुंच रही है या नहीं। इस बजट के कुछ पहलू हैं। इस बजट में गरीब, मजदूर, किसान, उपेक्षित वर्ग यानी सबके ऊपर समान दृष्टि से फोकस किया हुआ है। मैं अब तीन-चार चीजों पर बात करूंगा और उसके बाद मुझे फिर से यही प्रश्न पूछना पड़ेगा कि अगर ये सामाजिक उधार की चीजें नहीं है तो फिर ऐसा क्या किया जाए जिससे कि सामाजिक उधार हो। मैं अपने भाजपा के मित्रों से पूछना चाहूंगा।

टी सी द्वारा जारी

19.02.2024/1615/टी0सी0वी0/डी0सी0-1

श्री भवानी सिंह पठानिया..... जारी ।

सबसे पहले मनरेगा की दिहाड़ी 25 प्रतिशत बढ़ी है। इसका मतलब है कि 240 से बढ़कर 300 रुपये हुई है। क्या मुख्य मंत्री जी का यह कदम अनुचित था? दूसरा, जो हमारे दिहाड़ीदार भाई हैं उनकी दिहाड़ी 400 रुपये कर दी गई है। क्या यह कदम गलत था और क्या आप इसका समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं? तीसरा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका, मिड-डे मील वर्कर, वॉटर कैरियर, मल्टीपरप्ज वर्क और एम0एम0सी0 अध्यापक इन सबका मानदेय बढ़ाया गया है। क्या यह फैसला गलत है और क्या इस फैसले को नहीं लेना चाहिए था? अगर पिछड़ा वर्ग और समाज के उपेक्षित लोगों के लिए कोई स्कीम लांच करते हैं तो हमें तहेदिल से उसका समर्थन करना चाहिए। वाल्मीकि समाज के भाइयों के लिए 'महाऋषि वाल्मीकि कामगार आवास योजना' शुरू की गई है क्या यह गलत कार्य है? 'मुख्य मंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना' का अनुदान जोकि 1.50 लाख रुपये हुआ करता था उसको बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया है। 'मुख्य मंत्री सुख शिक्षा योजना' के तहत सभी विधवा नारियों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। यह एक ऐसा कदम है जो उन लोगों के लिए नील का पत्थर साबित होगा जिन लोगों के बच्चे पढ़ना-लिखना चाहते हैं लेकिन उनके ऊपर पिता का साया न होने की वजह से वे आर्थिक सरोकार को पूरा नहीं कर पाते और इस कारण से पढ़ाई छोड़ देते हैं। विधवा एवं एकल नारी के पात्र बच्चों के अकाउंट में 1000 रुपया हर महीने जमा होगा। क्या यह भी एक गलत स्टैप लिया गया है। इन्होंने कहा है कि यह जो बजट है यह निराशाजनक है और इसका समर्थन नहीं किया जा सकता तो इसका मतलब यह है कि मैंने जो स्कीमें अभी गिनाई हैं, भारतीय जनता पार्टी इनका समर्थन नहीं करना चाहती और इनके विरोध में है। अगला कदम आय और वैल्थ की डिसपेरिटी को कम करने में काम आएगा। यह पैसा सीधे तौर पर उन लोगों के पास जा रहा है जो हमारी 80 करोड़ की जनसंख्या, सस्ते राशन के ऊपर जी रही है। यह उनको आत्मनिर्भर बनाने की

कोशिश करेगा और उनको समाज में सिर ऊंचा करके जीने में सहायता करेगा। इसके अलावा इस बजट का एक दूसरा पहलू भी है कि हिमाचल प्रदेश एक

19.02.2024/1615/टी0सी0वी0/डी0सी0-2

ग्रामीण राज्य है। हमारी 90 प्रतिशत आबादी गांव के अंदर बस्ती है। मेरी फतेहपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में 52 पंचायतें हैं और कोई भी शहरी क्षेत्र नहीं है। इस बजट के अंदर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जो कदम उठाए गए है वे सराहनीय है। जैविक खेती की पॉलिसी निर्धारित करने के लिए एक किसान गेहूं, मक्की और धान को छोड़कर इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि उसको यह गारंटी नहीं होती है कि यदि मंडी में फसल नहीं बिकी तो मैं उसको कहां बेचूंगा। इससे हमारी जो हाईवैल्यू क्राप्स हैं जैसे सब्जी, हल्दी या सफेद मूसली इत्यादि का प्रोडेक्शन नहीं बढ़ पाता क्योंकि किसान को यह गारंटी नहीं होती कि उसका माल बिक जाएगा या नहीं। जैविक खेती भी उसी प्रकार का एक रिस्क है। इसमें प्रोडेक्शन नॉर्मल खेती से कम है क्योंकि इसमें जहरीले पदार्थ नहीं मिलाए जाते। इसमें नेचुरल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल होता है। इसमें पैस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं होता है जिसके कारण इसकी प्रोडेक्शन कम है। अगर प्रोडेक्शन कम है तो इसका अच्छा रेट निर्धारण करने के लिए सरकार की पॉलिसी होना बहुत जरूरी है। 'राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना' की जो शुरूआत हुई है इसके अंदर 40 रुपये एम0एस0पी0 गेहूं के लिए और 30 रुपये एम0एस0पी0 मक्की के लिए निर्धारित किए गए हैं। लोगों को जैविक खेती करने के लिए यह बहुत ही बढ़ा कदम है।

एन0एस0 द्वारा जारी ।

19-02-2024/1620/एन0एस-एच0के0/1

श्री भवानी सिंह पठानिया ------जारी

हिमाचल प्रदेश मेरे हिसाब से इस देश का पहला राज्य बना है जिसमें इस प्रकार का कदम जैविक खेती के लिए उठाया गया है। मैं इसके लिए मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और वे सराहना के पात्र हैं। इसके अतिरिक्त पशुपालक के लिए दूध के दाम बढ़ाए गए हैं। गाय का दूध 45 रुपये प्रति लीटर और भैंस का दूध 55 रुपये प्रति लीटर किया गया है। ये सारे-का-सारा पैसा डायरेक्टली किसान, बागवान, पशुपालक व फिशरीज वाले बंधुओं के पास जा रहा है। इस पैसे से और कुछ हो न हो लेकिन स्वरोजगार मिल रहा है और व्यापार के अंदर स्वावलंबन की बढ़ौतरी हो रही है। सरकार अगर किसानों व बागवानों को प्रोत्साहित करती रहती है तो इससे हमारी रूरल इकोनोमी या ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है। उसकी सुदृढ़ता से इनकम डिस्पेरिटी कम हो रही है। दूसरा, लोगों को शहर की तरफ पलायन नहीं करने पड़ता है। 8,000 से 10,000 रुपये की नौकरी करने के लिए बद्दी, बरोटीवाला और बाकी इंडिस्ट्रियल एरियाज में नहीं जाने पड़ता है। ये अच्छे कदम उठाए गए हैं। इसमें मुझे एक आपत्ति यह सुनाई दी कि आपने गारंटी में 100 रुपये बोला था। अब 100 रुपये वाली गारंटी में वही होता है कि at the end of the day जब तक डिस्ट्रिब्यूशन क्रिएट नहीं करते तब तक आप लास्ट माइल कनैक्टिविटी नहीं दे सकते। जिस प्रकार से इस समय सहकारी सभाओं के गठन का काम स्टार्ट हो चुका है। ढंगवार और अन्य स्थानों पर मिल्क चिलिंग प्लांट व मिल्क प्रोसैसिंग प्लांट स्टार्ट हो चुके हैं। ये और कुछ नहीं बल्कि हमारी डिस्ट्रिब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर का गठन हो रहा है और यह उसी दिशा में एक कदम है। थोड़े ही दिनों के बाद आप देखेंगे कि जो हमारी 'हिम गंगा योजना' है उस स्कीम में हमारी जो भी गारंटी थी, उस गारंटी को पूरा करने के लिए सरकार वचनबद्ध है। तीसरा, बजट के अंदर बागवानों के लिए यूनिवर्सल कार्टन शुरू करने की बात हो रही है। यह बहुत ही सराहनीय कदम है।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछली 14-15 महीनों के अंदर मैं जब भी मुख्य मंत्री जी के साथ किसी मीटिंग में गया हूं तो मैंने उनको बात करते देखा है। इनका फोकस हमेशा 2-3 विषयों के ऊपर रहता है। पहला फोकस यह है कि किस प्रकार से हमारा रेवेन्यू बढ़ सकता है? दूसरा

फोकस यह है कि किस प्रकार से हम अपने खर्चों को कम कर सकते हैं? इसमें देखिए कि एक्साइज में चाहे 18 प्रतिशत आया है या 40 प्रतिशत आया

19-02-2024/1620/एन0एस-एच0के0/2

है उसका पता तभी चलेगा जब 31 मार्च को क्लोजिंग होगी। इतने सालों के बाद पहली बार एक्साइज पॉलिसी के अंदर बदलाव लाकर ठेकों को ऑक्शन किया गया और 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई। उसके बाद वाटर सैस को इंप्लीमेंट किया गया। यह रेवेन्यू एनहांसमेंट की दिशा में ही एक कदम था। उपाध्यक्ष महोदय, अपने पेट पर कोई लात नहीं मारता। माननीय सदस्यों को हिमाचल भवन और अन्य विश्राम गृहों में जो सब्सिडी मिलती थी उसको रिमूव किया गया। खाना सस्ते रेट पर मिलता था उसको नॉर्म्ल रेट पर ले जाया गया। इस सबके पीछे यही मंशा थी कि सरकार का रेवेन्यू बढ़े और रेवेन्यू बढ़ने के साथ-साथ सरकार का खर्च भी कम हो।

यहां पर विपक्ष के नेता ने कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर बात की है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कम हो गया। मेरा मानना है कि माननीय जय राम ठाकुर जी ने 5 बजट प्रस्तुत किए हैं और इनको इतना पता होगा कि कमिटिड एक्सपेंडिचर वह एक्सपेंडिचर है जो खर्च करना ही होता है और उससे बच नहीं सकते हैं। पहले एक्सपेंडिचर हिमाचल प्रदेश का अगर आज आप देखें तो 79 per cent of my revenue receipt जो मैं कमा रहा हूं, उसका 79 प्रतिशत खर्च पहले से बंधा हुआ है। इसमें 41 प्रतिशत सैलरी पर, 24 प्रतिशत पेंशन पर और 14 प्रतिशत लोन के इंटरेस्ट की रीपेमेंट में जाता है। अब आप बताइए कि कमिटिड एक्सपेंडिचर ओवर नाइट तो कम नहीं होगा, रेवेन्यू ओवर नाइट नहीं बढ़ेगा। हर व्यक्ति को पता है कि यह प्राकृतिक आपदा का वर्ष था और इस प्रकार की त्रासदी आज तक हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं आई। उसके बावजूद यह बोलना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में कमी आई है जबकि आपके कमिटिड एक्सपेंडिचर 80 प्रतिशत के आसपास है। मेरे 2-3 प्रश्न रहेंगे। प्रश्न नम्बर-। कि केंद्र सरकार ने हमारी लोन की लिमिट कम क्यों की? यह बहुत बड़ा प्रश्न है।

आर0के0एस0 द्वारा ------जारी

19.02.2024/1625/RKS/एचके-1

श्री भवानी सिंह पठानिया ....जारी

केंद्र सरकार ने लोन की लिमिट क्यों कम की? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। लोन की लिमिट कम करने से जो 21 प्रतिशत कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाना था अगर वह 21 प्रतिशत कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाता तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कम होने की बजाय बढ़ जाता। इसका मतलब यह है कि हिमाचल के युवा, किसान-बागवान और हिमाचल के सभी निवासियों के पेट में लात पड़ रही है, उनके भविष्य के साथ कुठाराघात हो रहा है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण हिमाचल प्रदेश की लोन लिमिट को कम करना है। मैं यह बात कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश जितना हमारा है उतना ही आपका भी है। अगर आप यह मानते हैं कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के वोट शेयर में एक प्रतिशत का गैप है और जब केंद्र सरकार लोन लिमिट को कम करती है तो उसका खामियाजा जितना कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा उतना ही भारतीय जनता पार्टी को भी भुगतना होगा। दूसरा, ए.डी.बी., वर्ल्ड बैंक, जाइका और जितनी भी अन्य ऑर्गेनाइजेशन्स हैं ये सभी पहले प्रोजैक्ट की सेंटिटी व वायबिलिटी के बेस पर जितनी मर्जी फंडिंग कर सकती थी। लेकिन जब से हिमाचल प्रदेश में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को हटाया है तब से हमारी लिमिट तीन वर्ष के लिए 2700 करोड़ रुपये या एक साल के लिए 900 करोड़ रुपये फिक्स की दी गई। मेरा सवाल यह है कि ऐसा क्यों किया गया? क्या आप हिमाचल प्रदेश की जनता को इसलिए सजा दे रहे हैं कि आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ कर बाहर फैंक दिया? मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि as a part of the percentage, जो शहीदों का अनुपात है, कितनी आबादी के ऊपर कितने शहीद हैं, उस अनुपात में हिमाचल प्रदेश देश में सबसे अग्रणी राज्य है। इसलिए तीन या चार महीने बाद जब लोक सभा का चुनाव होगा तो आपको इसका परिणाम पता चल जाएगा। आप इस तरह प्रदेश के लोगों को मत डराइए। आप हमारी लिमिट को रिस्टोर कीजिए। लिमिट रिस्टोर होने के बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर भी रिस्टोर हो जाएगा जिससे अगले वर्ष रेवेन्यू

के अंदर साढ़े आठ से 10 प्रतिशत की ग्रोथ दिखेगी। मेरे तीन-चार और सुझाव हैं। ये सुझाव रेवेन्यू को एनहांस करने में काम आएंगे। पहली माइनिंग पोलिसी है। आज माइनिंग पोलिसी धनासेठों के हाथ में कंस्ट्रेटिड है। मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में बेरोजगार युवाओं के पास 700-800 ट्रैक्टर्ज हैं। जब खेती का सीजन खत्म हो जाता है तो ये

19.02.2024/1625/RKS/एचके-2

ट्रैक्टर्ज खड़े हो जाते हैं या अवैध माइनिंग करते हैं। हमारी खड्डें रेत से भर चुकी हैं और 30-40 सालों से उनकी ड्रेजिंग नहीं हुई है जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। मेरा मानना है कि हमें 20, 25 या 30 हजार के लाइसेंसिज के ऊपर इन ट्रैक्टर्ज वालों को वैध माइनिंग अलाउ करनी चाहिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। फतेहपुर की खड्ड में जब 30 साल पहले एक पुल बना था तो पुल के नीचे से पूरा ट्रैक्टर निकल जाता था। लेकिन आज वहां कुत्ता भी निकलने की कोशिश करे तो उसका सिर टकरा जाता है। हमारी पूरी-की-पूरी खड्डें रेत से भरी हुई हैं। अगर हम छोटी खड्डों में बेलचे से माइनिंग अलाउ करते हैं तो इससे स्वरोजगार, स्वावलम्बन और ग्रामीण आर्थिकी सुदृढ़ होगी तथा सरकार को भी काफी रेवेन्यू मिलेगा। हमारी 52 पंचायतें हैं , 242 रेवेन्यू विलेजिज हैं, कोई 7 या 8 ठेके हैं। अगर कोई मिल्क सैस देता है लेकिन उसने पीना हो तो वह कहां जाएगा? वह एक ऐसे आहते में जाता है जिसे हम अवैध कहते हैं। हमारे पास ऐसी पोलिसी नहीं है कि हम छोटे रेस्टारेंट या एंटरप्रिन्योर को वह लाइसेंस दे सके। इन छोटे एंटरप्रिन्योर वालों की अढ़ाई लाख, पांच लाख या बारह लाख का लाइसेंस लेने की क्षमता नहीं होती। अगर हम प्रति पंचायत छोटे केंद्रों में दो या तीन कंडिशन्ज के साथ एक्साइज का लाइसेंस दे दें तो इससे काफी रेवेन्यू प्राप्त होगा। जब उन्हें शराब खरीदनी हो तो वे अपने नजदीकी ठेके से शराब खरीदें। जो दो नम्बर की शराब बेच रहे हैं अगर इसे वैध कर दिया जाए तो इससे रेवेन्यू बढ़ेगा और आर्थिकी के ऊपर भी काफी बूस्ट आएगा। राजीव गांधी स्टार्ट अप योजना के अंदर आप टूरिज्म और रिलिजियस टूरिज्म को इंक्लूड कीजिए। अगर मेरा घर किसी लेक के पास है और मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं उस घर को होम स्टे में कंवर्ट कर सकूं तो इसे आप राजीव गांधी स्टार्ट-अप योजना के अंदर शामिल करें।

श्री बी.एस.द्वारा... जारी

19.02.2024/1630/बी.एस./वाई के/-1

श्री भवानी सिंह पठानिया जारी...

ये वहां पर एक अच्छा वाथरूम भी बना सकता है, ये पैडल बोट भी खरीद लेगा और अन्य फिशिंग के इक्यूपमेंट भी ले सकता है और पर्यन में यह पूरी तरह आत्मनिर्भर हो करके अपना काम कर सकता है। तीसरा धार्मिक पर्यटन है, ज्वालाजी, चामुण्डाजी और जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं यहां पर भी यदि स्टार्ट-अप के माध्य से बेराजगार युवाओं को जोड़ा जाए तो प्रशाद के सैंटर और जो हमारी धर्मशालाएं हैं तथा जंज घर हैं इस तरह से खोलने के लिए हम स्टार्ट-अप फंड के अंदर लोन देना आरंभ करेंगे तो यह भी स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए काम आएंगे।

इसके अलावा मेरा आखिरी प्वाइंट यह है कि रूरल वाटर हमारी जो स्कीम हैं जिसमें हमने कहा है कि ग्रामीण इलाकों में हम कोई भी पानी का बिल नहीं लेंगे। इससे यह हो रहा है कि उसी नलके से जिससे सिर्फ मैं पानी पीता था या शौचालय में इस्तेमाल करता था आज उसी नलके से गाय और भैंसे भी पानी पी रही हैं। उसी नलके से प्याज और अन्य खेतों में भी पानी का इस्तेमाल हो रहा है। इस तरह से पानी की बहुत बरबादी हो रही है। हमें 70 लीटर पानी प्रति व्यक्ति पर कैपिटा के हिसाब से चलना चाहिए कि हमें इतना ही पानी देना है। मैं यह बोल रहा हूं कि आप इसे थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं यदि चार लोगों का परिवार है तो आप उन्हें कह सकते हैं कि आप 800 लीटर पानी फ्री मिलेगा लेकिन इसके ऊपर आप पानी खर्च कर रहे हैं तो उस पानी का आपको बिल देना पड़ेगा। मेरा हिसाब से जो ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के कनेक्शन्ज हैं वहां पर रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए और पानी की फिजूलखर्ची को रोकने के लिए एक सैस लगाना बहुत जरूरी है। इसी के साथ मैं यह बोलना चाहूंगा कि युवाओं के लिए, बागवानों के लिए, किसानों के लिए और महिलाओं के लिए, सभी के लिए यह एक सर्वहितकारी बजट है। हमारे खिलाड़ियों के लिए जिस हिसाब से धनराशि को बढ़ाया गया है इस तरह से महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में धनराशि को दिया जाता था परंतु आज हम फक्र के साथ बोल सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश

भी एक ऐसा ही राज्य है जिसमें अन्य राज्यों के बाराबर धनराशि प्रदान की जा रही है। इसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, मैं इस बजट का तहेदिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, बहुत-बहुत धन्यवाद।

19.02.2024/1630/बी.एस./वाई के/-2

उपध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्री सुख राम चौधरी जी इस चर्चा में भाग लेंगे।

श्री सुख राम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, 17 फरवरी, 2024 को मुख्य मंत्री जी ने अपना दूसरा बजट पेश किया है और हम यह सोच रहे थे कि मुख्य मंत्री जी का यह दूसरा बजट है और इस बजट में मुख्य मंत्री जी ने कहा कि जो हमारी 10 गारंटियां हैं वह हमारा सरकारी दस्तावेज है। उनको हम लागू करेंगे परंतु हम 14 महीनों से देख रहे हैं कि जिन गारंटियों को देकर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई और तरह-तरह के नारों से देहात के दुर्गम क्षेत्रों में एक नहीं चार-चार आदमी एक पंचायत में लोगों को अकर्षित करने के लिए, युवाओं और महिलाओं को आकर्षित करने के लिए लगाए गए और कांगेस पार्टी ने नारे दीवारों पर लिखे गए। उसके कारण हिमाचल प्रदेश की महिलाओं ने हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों ने हिमाचल प्रदेश के किसानों ने उन पर विश्वास प्रकट करके कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाया क्योंकि वे गारंटियां ही ऐसी थीं। उन गारंटियों से हर व्यक्ति प्रभावित हो सकता था। किसानों को कहा प्रति किसान हम भैंस का दूध 100 रुपये लीटर खरीदेंगे और गाय का दूध 80 रुपये लीटर खरीदेंगे। इसके अलावा दो रुपये गोबर लेंगे। किसानों ने सोचा कि अच्छी सरकार आएगी। गोबर भी बिक जाएगा दूध भी बिक जाएगा और लोगों की आमदनी भी बढ़ जाएगी। बेरोजगारों के लिए क्या कहा कि

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

19.02.2024/1635/डीटी/वाई0के0/1

सुख राम चौधरी ...जारी...

680 करोड़ रुपये हर विधान क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए बेरोजगारों को सस्ते ऋण पर उपदान के रूप में देंगे। हिमाचल प्रदेश की हजारों दिवारों पर लिखा कि एक लाख युवाओं को

प्रतिवर्ष सरकारी क्षेत्र में रोजगार देंगे। 18 से 60 साल की महिलाओं को, आमदनी का उसमें कोई जिक्र नहीं, प्रति महिला 1500 रुपए देने का वायदा किया और हिमाचल प्रदेश के लोगों ने इन वायदों में आकर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बना दी। सरकार ने प्रदेश के बेरोजगारों, महिलाओं को और अन्य वर्गों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए। चौदह महीने सरकार को बने हुए हो गए हैं लेकिन आज अपने द्वारा प्रस्तुत दूसरे बजट में मुख्य मंत्री जी क्या कहते हैं कि 2,37,000 महिलाओं को जिनको पहले 1050 रुपए मिलता था उनको हम 1500 रूपए देंगे। पूर्व में जब भाजपा की सरकार थी हमनें कोई वायदा जनता से नहीं किया था लेकिन हमनें प्रदेश के बुजुर्गों को पैंशन देने की आयु को 80 से घटाकर 60 वर्ष किया। हमनें बीस साल का अंतर घटाकर इस आयु को 60 वर्ष करके प्रदेश में इस आयु वर्ग के पांच लाख लोगों को ये पैंशन दी और पैंशन की राशि को 7.50 सौ रुपए से बढ़ाकर 1150 रुपए किया। 65 वर्ष के उपरांत मिलने वाली पैंशन को 1050 रुपए से बढ़ाकर 1250 किया गाया। 70 साल की आयु से ऊपर के लोगों को हमनें 1700 रुपए की पैंशन दी। लेकिन हमने ऐसा कोई भी वायदा नहीं किया था। ऐसे तथ्यों को छुपाने के लिए तरह-तरह की बातें आदरणीय मुख्य मंत्री जी कर रहें हैं। अब कह रहें हैं कि 2 लाख 37 हजार महिलाओं को ही हम 1500 रुपए मासिक देंगे। वो तो 60 साल से ऊपर की महिलाएं हैं। लेकिन आपने तो वायदा 18 साल से 60 साल आयु वर्ग की महिलाओं के साथ किया है। हिमाचल प्रदेश में 24 लाख महिलाएं बिना किसी आय वाली हैं। मुख्य मंत्री जी 15 अप्रैल को लाहौल-स्पिति गए आपने सोचा की जहां महिलाओं की संख्या कम है वह जिला चुना जाए। लाहौल-स्पिति में महिलाओं की संख्या कितनी है, 2000, 3000 या ज्यादा से ज्यादा 4000 होगी। उनको सरकार 1500 रुपए प्रतिमाह पैंशन देगी। लेकिन आपने इसमें उम्र का जिक्र नहीं किया था। आप ने ऐसा कहा था कि 18 से 60 वर्ष की सभी महिलाओं 1500 रुपए देंगे और उसमें कोई मानदंड सुनिश्चत करेंगे ऐससा नहीं कहा था। हिमाचल प्रदेश में कुल 12 जिले हैं और 14 महीने सरकार के बीत गए, चुनाव के समय तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा फार्म भरवाए गए थे। हर विधान सभा क्षेत्र में आपके कार्यकर्ताओं ने महिलाओं से फार्म

भरवाए और ये भी कहा कि हम आपको एक नंबर दे रहें हैं इस नंबर में मिस-कॉल करें आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और दिसंबर माह में जब हमारी सरकार बनेगी उस समय आपके खाते में 1500 रुपए आने शुरू हो जाएंगे। ये आपने हिमाचल प्रदेश की महिलाओं से कहा था। लेकिन अब सरकार इस गांरटी से मुकर गई। अब आप इस गांरटी में इधर-उधर की बात कर रहें हैं। अब आप कह रहें हैं कि हम लाहौल-स्पिति से लागू करेंगे। क्या हिमाचल प्रदेश की अन्य महिलाओं ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया? आप इस गारंटी को केवल लाहौल-स्पिति से ही क्यों शुरू कर रहें हैं पूरे हिमाचल प्रदेश में इस गारंटी को क्यों नहीं शुरू कर रहे? वर्तमान में हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति क्या है? मुख्य मंत्री जी आप इस विधान सभा के नए सदस्य नहीं हैं। हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति क्या है, प्रदेश ने कितना लोन चुकाना है, इसके बारे में आप भलीभांती जानते हैं। अगर आप इस घोषणा को पूरा नहीं कर सकते तो आपने वायदा क्यों किया? आपको आने वाले समय में पता चल जाएगा क्योंकि जनता दूध का दूध और पानी का पानी खुद कर देगी। आपने हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों से कहा कि 10 करोड़ रूपए प्रति विधान सभा क्षेत्र में उपदान में ऋण देंगे। अब आप कह रहें हैं कि उपदान में ई-टैक्सी के परमिट देंगे। वो नौजवान जिसने इंजीनियरिंग की है, एक दुकानदार एक आई0टी0आई0 करने वाला युवा, मान लीजिए वो कोई छोटा मोटा बिजनेस लगाना चाहता है, दुकान करना चाहता है, इसमें आप उसको क्यों नहीं कवर करते? क्या प्रदेश सरकार ने सारे नौजवान टैक्सी ड्राईवर ही बनाने है।

श्री एन0जी0द्वारा जारी...

19-02-2024/1640/ए.जी.-एन.जी/1

श्री सुख राम चौधरी.....जारी

आप कितने लोगों को टैक्सी ड्राइवर बनाएंगे? इसमें भी आप हिमाचल प्रदेश के बेरोज़गारों के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। एक बेरोज़गार जिसने इंजिनियरिंग डिपलोमा किया, आई.टी.आई. की और वह अपना कारोबार करना चाहता है। आप उस युवा को राजीव

गांधी स्टार्टअप योजना के तहत कम ब्याज पर ऋण क्यों नहीं दे रहे हैं? आपकी गारंटी कहां गायब हो गई? आपकी मंशा ठीक नहीं है। आपने कहा कुछ और है और आप करना कुछ और चाहते हैं। अपने बजट भाषण के माध्यम से आप अपनी गारंटी की केवल औपचारिकता पूरी करना चाहते हैं। आपके बजट भाषण में कोई भी गम्भीरता नहीं है। आपकी गम्भीरता न बेरोज़गारों के लिए है और न महिलाओं के लिए है। कर्मचारी चयन बोर्ड 12-13 माह से बंद पड़ा है। जांच चलती रहती लेकिन आप रिजल्ट तो निकालते। उनके इंटरव्यू ही शुरू कर देते तो बेरोज़गारों को लगता कि सरकार हमारे प्रति गम्भीर है। लेकिन आप तो डीले प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि जितनी ज्यादा देर की जाए या पूर्व सरकार पर दोष डाला जाए तो बेहतर होगा। आपको लगता है कि वहां पर भ्रष्टाचार हो रहा था तो दोषियों को जेल में डालते लेकिन बेरोज़गारों ने आपका क्या बिगाड़ा था और उनका कसूर क्या है? आपने 14 माह में उन बच्चों के इंटरव्यू क्यों नहीं लिए? आपने 14 माह में तो कर्मचारी चयन बोर्ड का पुर्नगठन तक नहीं किया। आपने जो गारंटियां दी हैं उन्हें पूरा करने में आप पूर्ण रूप से असमर्थ साबित हो रहे हैं।

आपने गाय के दूध के दाम 38 रुपये से बढ़ाकर 45 रुपये और भैंस के दूध के दाम 47 रुपये से 55 रुपये करने की बात कही है। आपने तो चुनाव से पहले गाय के दूध के दाम 80 रुपये और भैंस के दूध के दाम 100 रुपये करने की बात कही थी। आपने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहीं पर भी यह वर्णन नहीं किया था कि आप इसे चरणबद्ध तरीके से बढ़ाएंगे।

आपके बड़े-बड़े नेता चुनाव से पहले मंदिरों में जा कर कसमें खा रहे थे कि मैं माता की कसम खाता हूं, आपने उन वीडियोज़ को वायरल भी किया, कि सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट में गारंटियों को पूरा करेंगे। अब आप कह रहे हैं कि चरणबद्ध तरीके से बढ़ाएंगे। आपने किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में जैविक खेती की बात कही है। आप गेहूं पर समर्थन मूल्य 40 रुपये प्रति किलो देने की बात

कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि 80 रुपये प्रति किलो तो ओपन मार्किट में ही बिक रहा है। जो किसान जैविक खेती कर रहे हैं उन्हें लोग 80 रुपये के हिसाब से एडवांस में पैसा देकर जा रहे हैं। जैविक गेहूं का आटा बाजार में 100 रुपये किलो बिक रहा है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 125 से 150 किसान ऐसे हैं जो जैविक खेती करते हैं। उन किसानों को मार्किट में जाने की जरूरत नहीं है और लोग उनके घरों में आकर उनका अनाज ले जाते हैं। अनेक बार तो उनके घरों में भी सभी लोगों को अनाज नहीं मिल पाता। क्या आप हिमाचल प्रदेश के किसानों को मूर्ख समझ रहे हैं? आप कह रहे हैं कि जैविक खेती की गेहूं को हम 40 रुपये प्रति किलो खरीदेंगे लेकिन वे 80 रुपये प्रति किलो तो पहले से ही बेच रहे हैं। आप 30 रुपये प्रति किलो मक्की खरीदने की बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आप हिमाचल प्रदेश के किसानों और आम जनता को कितना मूर्ख बनाओगे? आपने इस बजट भाषण को झूठ का पुलिंदा बना दिया है। इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। इस प्रकार से आप किसानों की आय कैसे बढ़ा सकते हैं? आप दूध 55 रुपये प्रति लीटर की बात कर रहे हो लेकिन 55 रुपये तो उसके घर से बिक रहा है। इस प्रकार से आपने दूध का समर्थन मूल्य कैसे बढ़ा दिया? आपकी सरकार ने जो वायदे किए हैं वे सभी झूठे हैं। आप कहते थे कि जय राम ठाकुर सरकार ने तो केवल बिजली के 125 यूनिट फ्री दिए हैं लेकिन कांग्रेस की सरकार बना दो तो दिसम्बर माह से हिमाचल प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने उन 300 यूनिट्स का क्या किया? आपने कितने उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली फ्री दे दी? आपने आज बिजली बोर्ड की हालत क्या कर दी है? बिजली बोर्ड के कर्मचारियों का लगभग 250 करोड़ रुपये तो ऐरियर बकाया है। प्राइवेट सैक्टर में जिन्होंने बिजली का उत्पादन किया और उनके उपदान का लगभग 800 करोड़ रुपये बकाया पड़ा है और सरकार ने उन्हें पेड नहीं किया। वे उस पैसे की मांग कर रहे हैं।

श्रीमती के.एस. द्वारा जारी.....

19.02.2024/1645/केएस/एजी/1

श्री सुख राम चौधरी जारी ----

कि हमने बिजली का उत्पादन किया, हमने आगे पेमेंट करनी है, हमारे लोन हैं, सरकार वह देने में असमर्थ है। आप 12-13 महीने में बिजली बोर्ड में रैगुलर एम.डी. नहीं लगा सके।

बिजली के पोल आपके पास नहीं हैं। ट्रांसफार्मर आपके पास नहीं हैं, बिजली के मीटर नहीं हैं। एक प्रश्न के उत्तर में यहां पर कहा गया कि 41 हजार बिजली के मीटरों के आवेदन पैंडिंग पड़े हैं। आप उनको नहीं लगा पा रहे हैं। बिजली के पोल आपके पास नहीं हैं। जब ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है तो उसकी रिप्लेसमेंट के लिए आपके पास ट्रांसफार्मर नहीं है। बिजली का मीटर डैमेज हो जाए तो उसको रिप्लेस करने के लिए आपके पास बिजली के मीटर्ज़ नहीं हैं। मुख्य मंत्री जी ने आर.डी.एस.एस. योजना की चर्चा की। वह तो केंद्र की स्कीम है। उसका नवम्बर, 2022 में टैंडर हो गया था। वह 3701 करोड़ रुपये की स्कीम है। 33/11 के.वी. के सब स्टेशन लगने थे, 20 का संवर्द्धन होना था, 5 हजार डिस्ट्रिब्यूशन ट्रांसफार्मर लगने थे और कम से कम हजारों/लाखों की संख्या में बिजली के मीटर परचेज होने थे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने वह टैंडर क्यों रद्द किया? अभी आपने नया टैंडर लगाया वह डेढ़ सौ प्रतिशत ज्यादा पर जा रहा है। वह नुकसान किसका हो रहा है? हिमाचल प्रदेश में यह पहली बार हुआ कि बिजली बोर्ड में 41 हजार लोगों के आवेदन पैंडिंग पड़े हैं। एक-एक साल से वे घूम रहे हैं। प्राइवेट ले रहे हैं। सरकारी सैक्टर में ना आपके पास पोल हैं, ना ट्रांसफार्मर है। और केंद्र की स्कीम का इसमें वर्णन कर दिया। वह तो केंद्र की स्कीम है, केंद्र ने उसमें आपको शत-प्रतिशत पैसा दे रखा है। आप 14 महीने में उसको इम्पलीमेंट नहीं कर सके, आप टैंडर नहीं लगा सके, काम अवार्ड नहीं कर सके। मैं जानना चाहता हूं कि इसका क्या कारण है?

उपाध्यक्ष जी, आज लारजी प्रोजैक्ट को बंद हुए 8 महीने हो गए हैं। प्लानिंग की बैठक में मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि उसका एक युनिट चल पड़ा है लेकिन वह भी इनको अधिकारियों ने झूठी सूचना दी। अभी भी लारजी के तीनों युनिट्स बंद पड़े हैं। 42-42 मैगावाट के वे 126 मैगावार के तीन प्रोजैक्ट्स हैं। प्लानिंग की बैठक हुए लगभग 15 दिन हो गए लेकिन आज तक एक भी युनिट नहीं चल पाया। अगर चला है तो उससे प्रतिदिन कितनी जनरेशन हो रही है, इस विधान सभा में उसका जवाब आना चाहिए।

19.02.2024/1645/केएस/एजी/2

झूठी बातें करके सरकार चलने वाली नहीं है। आपने कहा था कि जो हमारा ऊहल-iii स्टेज का प्रोजैक्ट है, जिसका पैनस्टोक डैमेज हो गया था, बंद हो गया था, आपने कहा था कि

उसको एक साल के अंदर-अंदर चला देंगे लेकिन सरकार को बने 14 महीने हो गए, आप बताएं कि आपने उसके ऊपर कितना काम किया? ऊहल-iii स्टेज पर आज तक कितना काम हुआ है? आपकी सारी घोषणाएं झूठी हैं और आपने हिमाचल प्रदेश के लोगों को मुंगेरी लाल के सपने दिखाए हैं। हिमाचल प्रदेश में विकास बिल्कुल बंद पड़ा है। विकास फील्ड में नहीं दिखाई दे रहा है। 6 महीने तक आप पैसों का रोना रोते रहे उसके बाद अब त्रासदी आ गई, अब आप उसकी बात कर रहे हैं। आपने मेंटिनेंस के लिए कितनी सड़कों को पैसा दिया? बरसात में हमारी सैंकड़ों सड़कें डैमेज हुईं। उनमें गड्ढे पड़े हैं उनकी आज तक रिपेयर नहीं हुई। पीने के पानी की स्कीमें, सिंचाई की स्कीमें डैमेज हुईं, टैम्परेरी रूप से चलीं, पर्मानेंट स्कीमें चलाने का प्रबन्ध नहीं हुआ। आपने हमारे विधान सभा क्षेत्र के 24 संस्थान बंद कर दिए। आपने उसमें गुण-दोष कुछ नहीं देखा। मेरा आपने वी.एण्ड आर. का सब डिविजन बंद कर दिया । डी लिमिटेशन के बाद हमें दिक्कत आ रही थी। शिलाई विधान सभा क्षेत्र की 11 पंचायतें पांवटा विधान सभा क्षेत्र में आईं। उनको डिविजन का काम करने के लिए भी 80 किलोमीटर दूर शिलाई जाना पड़ता है। सब-डिविजन में भी उनको 35 किलोमीटर दूर सतौन जाना पड़ता है। बिना सोचे-समझे आपने सब-डिविजन भी बंद कर दिया। हमारी दो सब-तहसीलें आपने बंद कर दीं। पटवार सर्कल, कानूनगो सर्कल बंद कर दिए। इलैक्ट्रिकल का एक सब-डिविज़न आपने बंद कर दिया।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

19.02.2024/1650/एवी/एएस/1

श्री सुख राम चौधरी------ जारी

आपका एक साल का इतिहास कहता है कि आप संस्थानों को बंद करने वाली सरकार है। आप हिमाचल प्रदेश के विकास को विराम लगाने वाली सरकार सिद्ध हुई है। आपके एक साल के कार्यकाल में कोई नया काम नहीं हुआ। मेरे विधान सभा क्षेत्र में किसी स्कूल की बिल्डिंग का नया काम शुरू नहीं हुआ। आपका तो यह राग रहा है कि हमारे पास पैसे नहीं है, केंद्र सरकार हमें पैसे नहीं दे रही है और आप हिमाचल प्रदेश की जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं ताकि उनका ध्यान गारंटियों की ओर न जाए क्योंकि आपकी सरकार

झूठी गारंटियों के आधार पर बनी है। आपने जो बजट पेश किया है इसमें 80 प्रतिशत स्कीमें केंद्र सरकार की हैं। आप किसी भी स्कीम को उठाकर देख लो, केंद्र का सारा पैसा है और उन्हीं के अंतर्गत पूरे प्रदेश में स्कीमों का काम चला हुआ है। मैं आपको यह बात जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं कि आप अपने 14 महीने के कार्यकाल में पांवटा साहिब विधान सभा क्षेत्र में शुरू की गई किसी एक भी नई स्कीम का नाम गिना दो। आपने वहां पर अपने कार्यकाल में कोई भी नया काम शुरू नहीं किया है। नया काम तो क्या शुरू करना परंतु जो पहले पैसा दिया था उसको भी आपने वापिस ले लिया। आपने उन स्कीमों का काम भी अधूरा कर दिया है। यहां पर ठीक कहा जा रहा है कि ठेकेदारों की पेमेंट भी चुन-चुनकर हो रही है। उसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है और मैं अभी उस पर ज्यादा नहीं बोलना चाहता। मैं आपको लिखकर दूंगा क्योंकि आपका आइना बदल गया है। आप अपने चहेते ठेकेदारों की पेमेंट निकाल रहे हैं। काम के ऑफलाइन टेण्डर हो रहे हैं, ऑनलाइन टेण्डर बंद कर दिए हैं और अपने चहेतों को एडजस्ट किया जा रहा है। प्रदेश में वर्तमान में यह प्रक्रिया चली है।

इस बजट भाषण के माध्यम से आपने अपनी गारंटियों के लिए कुछ नहीं किया है। आपने केवल औपचारिकताएं पूरी की हैं। आपने किसानों व बेरोज़गारों को ठगा है। आपने प्रदेश में रोज़गार देने की बात कही, मैंने आपको राजीव गांधी स्टार्टअप योजना का वर्णन करके बता दिया है। बेरोज़गार देख रहे थे कि शायद इसी में इनको रोज़गार मिल जाए। कोई छोटा उद्योग लगा लेगा या अपना बिजनेस कर लेगा या कोई दुकान खोल लेगा। उसमें भी आपने कहा कि टैक्सी ड्राइवर बनो, बसें ले लो। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने जो बजट प्रस्तुत किया है इसमें कुछ नहीं है। यह एक

19.02.2024/1650/एवी/एएस/2

निराशाजनक बजट है। हिमाचल प्रदेश के लोगों को जो आपने गारंटियां दी थीं उन गारंटियों की औपचारिकताओं को पूरी करने वाला बजट है। इसलिए मैं इस बजट का समर्थन करने में असमर्थ हूं।

(अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

अभी मई-जून माह में होने वाले लोक सभा चुनाव में आपकी परीक्षा हो जाएगी। प्रदेश का हर वर्ग आपसे परेशान है। इसलिए आप चिंता मत कीजिए क्योंकि आपने कोई भी काम नहीं किए हैं। आपने संस्थानों को बंद करते हुए यह भी ध्यान नहीं रखा कि कौन-सा जेनुइन था या कौन-सा बंद करना था। इसलिए अब प्रदेश की जनता लोक सभा के चुनाव का इंतजार कर रही है। आपको प्रदेश की जनता चुनाव के दिनों में असली आइना दिखाएगी। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि यह बजट निराशाजनक बजट है और इसमें किसानों के लिए कुछ नहीं है। इसमें केवल झूठी घोषणाएं हैं तथा मुंगेरी लाल के सपने दिखाए गए हैं। इसलिए मैं इसका समर्थन करने में असमर्थ हूं।

आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय हिमाचल।

समाप्त

19.02.2024/1650/एवी/एएस/3

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्री राम कुमार जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री राम कुमार, मुख्य संसदीय सचिवः अध्यक्ष महोदय, दिनांक 17 फरवरी, 2024 को प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी ने इस सदन में वित्तीय वर्ष 2024-25 का अनुमानित बजट पेश किया। मैं भी उस पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष महोदय, यह अपनी तरह का पहला बजट है जिसमें माननीय मुख्य मंत्री जी ने पूरे प्रदेश की जनता को लगने वाले टैक्सों से राहत दी है। मैं तो यह कहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक टैक्स फ्री बजट पेश किया है जिसके लिए मैं पूरे प्रदेश की जनता की तरफ से इनका आभार प्रकट करता हूं। हिमाचल प्रदेश के सम्माननीय मुख्य मंत्री श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी का सरकार बनने के बाद जब मेरे विधान सभा क्षेत्र में पहला प्रवास था

टी सी द्वारा जारी

19.02.2024/1655/टी0सी0वी0/ए0एस0-1

श्री राम कुमार, मुख्य संसदीय सचिव... जारी

तो 3 बड़ी घोषणाएं मुख्य मंत्री जी ने उस प्रवास के दौरान की थी। जिसमें सबसे पहली घोषणा दून विधान सभा क्षेत्र की डवलपमेंट ब्लॉक की मांग थी। दूसरी, एस0डी0एम0 कार्यालय की मांग थी। तीसरी, बी0एम0ओ0 कार्यालय की मांग थी। इसके अलावा हमने पटवार सर्कल की मांग भी की थी। मुख्य मंत्री जी ने बी0एम0ओ0 की मांग तो थोड़े दिनों के अंदर ही पूरी कर दी थी और उसकी नोटिफिकेशन भी हो गई थी। यह फंक्शनल भी हो चुका है। इसके लिए मैं सरकार और मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। दिनांक 9 फरवरी को जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें एस0डी0एम0 कार्यालय, विकास खंड, पट्टा और पटवारखाना झाड़माजरी तीन बड़ी मांगें दून विधान सभा क्षेत्र की स्वीकृत की गई। इसके लिए मैं दून क्षेत्र की जनता और अपनी तरफ से मुख्य मंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाले एरिया दून में इनकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। मुख्य मंत्री जी 7 तारीख को दून क्षेत्र के दौरे पर थे। मेरे क्षेत्र में जो आगजनी की घटना हुई वे उसको देखने के लिए स्वयं गए। उस दिन मैंने उनके साथ चर्चा की और उन्होंने मुझे कहा कि परसों आपकी तीनों मांगें कैबिनेट में स्वीकृत कर देंगे। विकास खंड की नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है और सिर्फ एस0डी0एम0 कार्यालय की नोटिफिकेशन होना बाकी है। मैं चाहता हूं कि इस एस0डी0एम0 की नोटिफिकेशन भी शीघ्र ही हो जाए ताकि दून क्षेत्र की जनता को इसके कारण आ रही समस्या से निजात मिले। शीतलपुर-जगातखाना रोड जो मेडिकल डिवाइस पार्क को जोड़ेगा उसकी भी मुख्य मंत्री जी ने इस बजट में घोषणा की है। मेरे पूज्य पिता जी स्वर्गीय श्री लज्जा राम जी ने इस रोड को 14 किलोमीटर तक निकाला था लेकिन अब इसकी डी0पी0आर0 114 करोड़ रुपये की बनी है। यह रोड बद्दी-चण्डीगढ़ से नवांनगर से इसको जोड़ेगा। बद्दी-नालागढ़ रोड पर जो ट्रैफिक का रश है उसको भी इससे राहत मिलेगी। यह बद्दी औद्योगिक क्षेत्र और डिवाइस पार्क ढेरवाल को जोड़ने के लिए सेतु का

काम करेगा। इसके लिए भी मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। जब बरसात की त्रासदी आई तो परवाणू में कालका-शिमला कोटी के पास गिर गया और सारा ट्रैफिक सबाटू-

19.02.2024/1655/टी0सी0वी0/ए0एस0-2

वाया बरोटीवाला से हो कई चण्डीगढ़ के लिए डायवर्ट किया गया। एक तरह से यह पैरलल रोड सिद्ध हुआ। मैंने इसकी भी मुख्य मंत्री जी चर्चा की जिस पर इन्होंने कहा कि इसको इस साल 10 किलोमीटर तक बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसकी डी0पी0आर0 भी तैयार होकर आ चुकी है। मुख्य मंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इसकी प्रशासनिकी अप्रूवल तुरंत की जाए। इसके लिए भी मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। इससे जहां एक ओर हमारा इलाका जिला मुख्यालय से जुड़ेगा। दूसरा,

एन0एस0 द्वारा जारी ।

19-02-2024/1700/एन0एस-डी0सी0/1

श्री राम कुमार (मुख्य संसदीय सचिव) ------जारी

बनालगी के औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग विभाग के नाम है जो पिछले काफी समय से डंप पड़ी थी उसको बसाने के लिए इस रोड का महत्वपूर्ण योगदान होगा। इसमें अभी दो बड़े उद्योग लगे हैं। एक उद्योग टमाटर का और दूसरा सेब का लगा है। इससे काफी लोकल लोगों को रोजगार मिला है। इसी रोड के ऊपर जाड़ला के पास शराब की फैक्टरी भी लगी है। जो कसौली विधान सभा क्षेत्र को कवर करती है। इससे भी हमारे लोगों को रोजगार की संभावनाएं खुलेंगी। इस बजट में माननीय पूर्व मुख्य मंत्री जी व अन्य साथियों ने काफी बातें की हैं। जिस पर मैं कहना चाहूंगा कि यह अपने आपमें पहला बजट है जिसमें गरीब लोगों का ध्यान रखा गया है, जो मनरेगा में काम करते हैं। उसमें ज्यादातर विधवा महिलाएं होती हैं। मनरेगा स्कीम केंद्रीय कांग्रेस सरकार की यू0पी0ए0-॥ ने शुरू की थी। इसमें पहली बार ऐसा हुआ कि मजदूरों की दिहाड़ी 240 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये प्रतिदिन की गई है। इसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन लोगों का इन्होंने बहुत ध्यान रखा। पंचायती राज संस्थाओं से मैं भी जुड़ा रहा हूं। इस सिस्टम में वार्ड पंच से लेकर

जिला परिषद तक उन सभी लोगों का मानदेय बड़ी मात्रा में बढ़ाया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि वर्ष 2006 में जब मैं चेयरमैन बना तो 13वीं जिला परिषद का मानदेय केवल 3500 रुपये होता था और अपना कार्यकाल पूरा करने तक 6000 रुपये मानदेय पहुंचा। आज 24,000 रुपये मानदेय इस सरकार ने किया है और निचले स्तर पर वार्ड पंच का मानदेय 750 रुपये प्रतिमाह किया है। इस सरकार ने यह बहुत बड़ी बढ़ौतरी की है।

सरकार ने सबसे ज्वलंत मुद्दे नशे के ऊपर जो कदम उठाया है इसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी की सराहना करना चाहूंगा। प्रदेश में पहला नशा मुक्ति केंद्र कंडाघाट में बनाने की घोषणा की है। वैसे तो प्रदेश में कई प्राइवेट केंद्र चल रहे हैं। कई केंद्र अच्छा काम कर रहे हैं और कई केंद्र अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। इसके साथ-साथ ओलंपिक खेलों, एशियन गेम्ज, कॉमन वैल्थ गेम्ज व अन्य राज्यों में होने वाली खेलों के खिलाड़ियों की प्रोत्साहन राशि हेतु करोड़ों रुपये की घोषणा की गई है। यहां पर माननीय भवानी सिंह पठानिया जी ने भी कहा कि पहले हम पंजाब व हरियाणा के बारे में सुनते थे कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि दी जाती थी और उसके साथ-साथ सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण दिया जाता था। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान

19-02-2024/1700/एन0एस-डी0सी0/2

में लाना चाहूंगा कि सब-डिवीजन नालागढ़ के रहने वाले श्री अजय ठाकुर जिनको पूर्व वीरभद्र सरकार में डी0एस0पी0 के पद पर नवाजा गया। मैं मुख्य मंत्री जी से चाहता हूं कि आने वाले समय में नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ियों के लिए आरक्षण किया जाए। उन्हें नौकरियों में कुछ आरक्षण दिया जाए ताकि नौजवान साथी खेलों की तरफ प्रोत्साहित हों। उनको उच्च प्रोत्साहन राशि के साथ-साथ सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण मिले। श्री अजय ठाकुर की नौकरी को रोकने के लिए कुछ अधिकारियों ने कोशिश की कि हिमाचल प्रदेश में कभी भी ए0एस0आई0 के ऊपर के रैंक की नौकरी किसी भी खिलाड़ी को नहीं दी गई। मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी से जब मेरी चर्चा हुई तो मैंने उनसे पूछा कि जब हिमाचल प्रदेश में रेवेन्यू मैन्युअल पंजाब का लागू होता है और अन्य सारे सिविल सर्विसिज रूल पंजाब के लागू होते हैं तथा पंजाब व हरियाणा में काफी सारे खिलाड़ियों को ऐसे पदों पर तैनात किया गया है।

आर0के0एस0 द्वारा ------जारी

19.02.2024/1705/RKS/डीसी-1

श्री राम कुमार (मुख्य संसदीय सचिव)...जारी

जब वह नोटिफिकेशन मैंन उन्हें लाकर दी तो फिर उसके आधार पर श्री अजय ठाकुर जी को नौकरी मिली जिसके लिए मैं पूर्व सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा। इस नशे के जाल में हमारे नौजवान काफी फंसते जा रहे हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 25 नौजवान ऐसे थे जो 18 से 30 वर्ष की आयु में नशे के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। चिट्टे का बाजार हर क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। इसके लिए हम सभी लोग चिंतित है। सदन में भी इस बारे में काफी चर्चा हुई है। अगर हमारे नौजवान साथियों को काम मिलेगा और जैसे माननीय मुख्य मंत्री जी ने खेलों में प्रोत्साहन राशि बढ़ाई है तो इससे नशे में जरूर लगाम लगेगी। हिमाचल प्रदेश मक्की, गेहूं, दूध या अन्य उत्पादों में एम.एस.पी. लागू करने वाला पहला राज्य बना है। यह अपने आप में एक पहल है और मैं इसकी काफी सराहना करता हूं। प्रदेश को कैसे आत्म-निर्भर बनाया जाए, प्रदेश की आय को कैसे बढ़ाया जाए और प्रदेश के संसाधनों का दोहन कैसे किया जाए इसके लिए मुख्य मंत्री जी दिन-रात चिंता और चिंतन करते हैं। वे हमसे और अधिकारियों के साथ यही बात करते हैं कि इस प्रदेश को आगे कैसे बढ़ाया जाए। मुख्य मंत्री जी ने 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्टार्ट-अप योजना चलाई है। श्री सुख राम जी आप मांग कर रहे थे लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप सिंगल विंडो सिस्टम में जाइए वहां पर ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो दुकानदारों और बेरोजगार युवाओं के लिए चलाई गई हैं और आप इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। आप उन योजनाओं का ज्ञान प्राप्त कीजिए। वहां पर उन योजनाओं का पूरा ब्रोशर है। इन योजनाओं के तहत 50 प्रतिशत उपदान पर टैक्सी देने की बात कही गई है। इन योजनाओं में सब चीजें कवर की गई हैं इसलिए आप इसे ध्यान से देख लें। ग्रीन हिमाचल, सोलर पावर और अन्य ऐसी बहुत-सी प्रयोजनाएं हैं जिससे हमारे बेरोजगारों को स्वयंभू रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। जो ठेके काफी समय से निलाम नहीं हो रहे थे उसके लिए एक्साइज में मुख्य

मंत्री जी ने बहुत बड़ी पोलिसी लाई है। पूर्व मुख्य मंत्री जी कह रहे थे कि अभी वहां से कोटा नहीं उठाया गया है। जब निलामी हो गई है तो वे कोटा उठाएं या न उठाएं यह ठेकेदारों की जिम्मेवारी है। उन्हें ठेके के पैसे देने ही पड़ेंगे। टोल-टैक्स बैरियर्ज की निलामी से टैक्स की चोरी में लगाम लगी है। हमारा एक्साइज का रेवेन्यू काफी मात्रा में बढ़ा है। पिछली सरकार ने उद्योग स्थापित करने के लिए प्रयास किए

19.02.2024/1705/RKS/डीसी-2

और उसमें कुछ निर्णय गलत भी लिए गए। मैं बल्क ड्रग्स पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क का जिक्र करना चाहूंगा। निःसंदेह इन पार्कों के स्थापित होने से हमारे बहुत से बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा। ये केंद्र सरकार के उपक्रम है इसलिए ये पार्क स्थापित करने ही थे। इसमें जो एक रुपये लीज में जमीन दी है उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो प्राइवेट लोगों को कुछ जमीनें एक रुपये लीज में दी है उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा। एक प्राइवेट आदमी को दो जगह 30-30 हैक्टेयर जमीन जो लगभग 150-150 बीघा बनती है, दी गई है। उसकी एक जमीन मेरे विधान सभा क्षेत्र में है और दूसरी कृपालपुर में है। 30 हैक्टेयर का 1,21,405 वर्ग मीटर क्षेत्र बनता है। अगर हम इसके सी.एल.यू. की बात करें तो हमने यह जमीन एक रुपये में दी और पांच साल तक हम उनको इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी और जमीन भी फ्री दे रहे हैं। उनका एक ट्रैक्टर उद्योग पहले से बद्दी में स्थापित है।

श्री बी.एस.द्वारा... जारी

19.02.2024/1710/बी.एस./एच के/-1

श्री राम कुमार जारी...

मुझे नहीं लगता कि इसमें पांच हिमाचलियों को नौकरी दी गई है। जो उद्योग हमें नौकरी नहीं दे रहा है और हमारी जमीन भी फ्री ले रहा है और हमें सी.एल.यू. नही दे रहा है तो ऐसे उद्योगों को मैं समझता हूं कि उससे अच्छा होगा कि ये लगने ही नहीं चाहिए। मैं इस सदन के माध्य से मुख्य मंत्री जी को ये आंकड़े बताना चाहूंगा कि हम 30 हैक्टेयर की बात

करें उसमें जो इस्तेमाल करने वाली जगह बनेगी वह 90 हजार वर्ग क्युविक मीटर जगह बनेगी और कम-से-कम रेट उस ऐरिया में यदि मैं कहूं तो वह 3000 से 5000 पर वर्ग मीटर है। आज सैंकड़ों उद्योगपति जो छोटे-छोटे उद्योग वहां पर लगाना चाहते हैं वे जमीन की मांग कर रहे हैं। लेकिन जमीन नहीं मिल रही है यह जमीन पहले अन्नपूर्णा के पास थी, मौझामल अक्का वाली में ये गोल्फ कोर्स के नाम थी। पहले ये लीज आउट भी और लगभग 10 मीटर का रोड उस जगह पर है। इस जमीन को पिछली सरकार ने एक रुपये में दे दिया है। इसके लिए क्या सैटिंग थी और क्यों यह हुआ यह तो ये ही लोग जान सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि इसका मैं आकलन करूं और 3000 वर्ग मीटर के हिसाब से इसकी कीमत लगाई जाए तो 27 करोड़ रुपये एक टूकड़े के बनते हैं परंतु इन्हें तो दो टुकड़े दिए गए हैं। इनके लगभग 54 करोड़ रुपये बनते हैं और 50-50 लाख इसका सी.एल.यू. बनता है। इसके बावजूद दो वर्षों में इन्होंने काम तक शुरू नहीं किया है। मेरी मांग है कि इस तरह के उद्योगों को तुरंत प्रभाव से रद्द करके जो उद्योगपति जल्दी उद्योग लगाना चाहते हैं उन्हें ऐसी भूमि को दिया जाए ताकि जल्दी से उद्योग लग सके। जिससे प्रदेश का रेवेन्यू बढ़ सके। जमीन कौड़ियों के भाव में उद्योगापतियों को दी गई है इसमें लगभग 100 करोड़ रुपये का गोल माल हुआ है। मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि अपने जवाब में इन उद्योगों को जिन्होंने इनमें कोई भी काम शुरू नहीं किया उन्हें रद्द करके जो लोग उद्योग लगाना चाहते हैं उनको इस जमीन को आबंटित करने की कृपा रकें।

मेरा क्षेत्र बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, बहुत सारे काम पूज्य पिता जी ने किए और हमने किए, परंतु अभी भी बहुत सुधार की जरूरत है। मेरी मांग रहेगी कि मेरे इस एरिया में एक अथॉरिटी का गटन किया गया है और बी.बी.एन.डी.ए. का बजट बुक में बजट नहीं झपता था। पिछली बार हमने पूर्व मुख्य

19.02.2024/1710/बी.एस./एच के/-2

मंत्री आदरणीय वीरभद्र सिंह जी से मांग की और 35 करोड़ रुपये बजट बुक में और विभाग से रिमेनिंग बजट मुझे मिला। इस ऑथोरिटी को 75 करोड़ रुपये मिलते थे। परंतु इस बजट में इसका उल्लेख नहीं है। मेरा मुख्य मंत्री जी से आग्रह रहेगा कि बी.बी.एन.डी.ए. के लिए

कम-से-कम 100 करोड़ रुपये की राशि इस आगामी बजट में प्रदान करने की कृपा करें, ताकि जो हमारी वहां की मूलभूत सुविधाएं हैं उन्हें पूरा किया जा सके।

यहां पर एक छोटा सा बस स्डैंड है और इसकी बहुत आवश्यकता है, हमारा मेन बस अड्डा था वह एन.एच. में आ गया है इसलिए वहां पर अब कोई बस अड्डा नहीं है। इसे हक बालक नदी के पास ले करके आए हैं, यदि इसका निर्माण पी.पी.पी. मोड पर भी किया जाता है तो भी कोई भी आदमी इसे बना लेगा। क्योंकि वहां पर कॉमर्शियल की बहुत ज्यादा डिमांड है।

जब मैं वर्ष 2012-17 में विधायक था उस समय मैंने कुछ संस्थान शुरू करवाये थे जैसे सिविल अस्पताल बद्दी है वह 50 बिस्तरों का है उसका भवन बन करके तैयार है और पांच करोड़ रुपये की देनदारी केवल लोक निर्माण विभाग की है और वह उद्घाटन के लिए तैयार है। इसमें मैंने 22 लाख रुपये की मीशन किसी उद्योगपति को कह करके लगवाई है और 50 बिस्तरों की जगह मैंने इसे 100 बिस्तरों का करवा दिया है। इन्हें भी मैंने किसी उद्योगपति को कह करके किया है। इसके लिए सरकार का कोई भी पैसा खर्च नहीं हुआ है और वहां पर हर बिस्तर के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था भी कर ली है। मैं चाहता हूं कि इसकी देनदारी का पैसा एक्सीयन, लोक निर्माण विभाग, नालागढ़ को दे दिया जाए ताकि स्वास्थ्य विभाग इसे अपने अधीन ले सके और इसे चालू कर सके। तीसरा जो दो आई.टी भवन, पट्टा और कृष्णगढ़ हैं ये भी लगभग तैयार है इनका थोड़ा सा काम बचता है। मैं चाहता हूं कि विभाग से इनके लिए कुछ शनराशि मिल जाए तो इनके निर्माण कार्य भी पूरे हो जाएंगे।

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

19.02.2024/1715/डी0टी0/एच0के0/1

श्री राम कुमार, मुख्य संसदीय सचिव जारी...

तीसरा मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सी0एच0सी0 चंडी है जिसमें लगभग 13 करोड़ रूपये की राशि पूर्व में मेरे द्वारा ही स्वीकृत करवाई गई थी लेकिन पिछली सरकार की

मेहरबानियों से वह पैसे वापिस आ गये थे। यहां पर बी0एम0ओ0 ऑफिस के साथ-साथ अस्पताल भी लगभग तैयार है लेकिन इस काम की भी काफी देनदारियां शेष है। इसमें मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इस अस्पताल संबंधित देनदारियों को चुकाने और शेष बचे काम को पूर्ण करने के लिए विभागीय बजट से धनराशि उपलब्ध करवाई जाए ताकि लोगों को अपना उपचार बाहर जाकर न करवाना पड़े। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पी0एच0सी0 पट्टा में दो डॉक्टर थे लेकिन पिछली सरकार ने इसको सी0एच0सी0 किया और एक डॉक्टर का पद वापिस ले लिया। ऐसे कार्य पूर्व की सरकार ने भी किए हैं। जब इनके द्वारा बिना किसी भी प्रावधान के खोले गए संस्थान हमारी सरकार द्वारा बंद किए गए तो ये उन संस्थानों को खोलने की बात कहते हैं। मैं अपने विपक्ष के साथियों को बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी आवश्यकता के अनुसार यानी नीड बेस पर संस्थान खोल रहे हैं। मैं देख रहा था पिछले वर्ष जब प्लानिंग की मिटिंग थी तो उसमें माननीय मुख्य मंत्री जी ने विपक्ष के हमारे माननीय सदस्यों के कहने पर बहुत सारे संस्थान रिस्टोर कर दिये थे और अभी भी माननीय मुख्य मंत्री जहां जाते है वहा जरूरत के अनुसार संस्थान को रिस्टोर कर रहे हैं। मेरे दून विधान सभा क्षेत्र में पी0डब्ल्यू0डी0 का अपना कोई भी डिविज़न नहीं है। इस विषय पर मेरी माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय लोक निर्माण मंत्री जी से वार्ता हुई है। इसलिए मैं इस सदन में भी पुनः मांग कर रहा हूं कि आने वाले समय में पी0डब्ल्यू0डी0 का डिविज़न मेरे विधान सभा क्षेत्र में खोला जाए ताकि वहां की सड़कों की हालत ठीक हो सके। बद्दी औद्योगिक क्षेत्र पूरे राज्य में सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, इसलिए इस क्षेत्र का ध्यान रखना हमारी प्राथमिकता है। इस क्षेत्र में जो नए उद्योग लग रहे हैं या जो नई नई इंडस्ट्रीज प्रदेश में आना चाहती है उसके लिए मैं चाहता हूं कि 118 की जो मंजुरी है वह सिस्टम थोड़ा स्लो है इसको भी थोड़ा सा स्पीड-अप करने की जरूरत है। ये माननीय मुख्य मंत्री जी की भी चिंता कि प्रदेश में नए उद्योग आएं इसलिए मेरा सुझाप है कि टेनेंसी एक्ट में 118 के अंतर्गत दी जाने वाली मंजुरी के प्रोसैस को स्पीड-अप करने की जरूरत

19.02.2024/1715/डी0टी0/एच0के0/2

है। इस एक्ट के कारण मंजुरी मिलने में काफी डिले हो रहा है लेकिन प्रदेश में कई उद्योग आना चाह रहे हैं। एक और चीज मैं इस सदन में कहना चाहूंगा कि जब बद्दी क्षेत्र में उद्योग स्थापित किए जा रहे थे उस समय बद्दी के लिए एक औ़द्योगिक पैकेज था क्योंकि यहां भी टेक्स होली-डे था और उस समय वहां पर उद्योग आ रहे थे। आज 20-25 वर्ष हो गए हैं उस छोटे उद्योग जो हाफ भी रहे हैं और उन्य राज्यों में टैक्स होली डे हैं, और ये उद्योग वहां जाने के फिराक में हैं। मेरा निवेदन रहेगा कि जो एडीशनल गुडज टैक्स में जो बढ़ोतरी की गई है, उसको वापिस लिया जाए। उसको वापिस लेने से हमारे जो उद्योग लगे हुए हैं, वह चलते रहेंगे। जिससे लोगों का रोजगार भी चल रहा है। लगभग बद्दी ओद्यौगिक क्षेत्र से जहां पर 100 करोड़ रुपए का जीएसटी हर रोज का सरकार को आता है। जिसमें 50 करोड़ रुपए प्रदेश सरकार को और 50 करोड़ रुपए केन्द्र सरकार को जाता है। इस ओद्यौगिक क्षेत्र को और विकसित करने के लिए वहां पर बहुत सी ऐसी जमीनें हैं जिनको आइडंटीफाई करके उनको उद्योग विभाग के नाम किया जा सकता है और उद्योग विभाग उस भूमि को उन लोागें को दे सकता है जो हिमाचल में उद्योग लगाना चाहते हैं। मेरे ध्यान में आज भी लगभग 40-50 उद्योगपति ऐसे हैं जो बद्दी में उद्योग लगाना चाहते हैं लेकिन उनको जमीन नहीं मिल रही है। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह रहेगा की बद्दी क्षेत्र ऐसे में लोगों की जिन्हें पिछले दो वर्षों में एक रूपए लीज पर जमीनें आंबटित की गई हैं, ऐसे मामलो को तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए और उद्योग विभाग उनको दोबारा अपने रेट से आबंटित करे।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया। आपका धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

अध्यक्षः अब माननीय सदस्य श्री विनोद कुमार जी चर्चा में भाग लेंगे।

19.02.2024/1715/डी0टी0/एच0के0/3

श्री विनोद कुमारः माननीय अध्यक्ष महोदय, 17 फरवरी, 2024 को हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री सुक्खविन्दर सिंह सुक्खू जी ने इस माननीय सदन में वर्ष 2024-25 के बजट

अनुमान प्रस्तुत किए थे। मैं भी इस बजट अनुमानों में बोलने हेतु खड़ा हुआ हूं। आपने समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता के अन्दर और विशेषकर युवा साथियों और किसानों के अंदर इस बजट को लेकर खासा उत्साह था।

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

19-02-2024/1720/वाई.के.-एन.जी/1

श्री विनोद कुमार .....जारी

उस उत्साह का कारण यह था कि एक साल से सरकार की ओर से एक ही बात की जा रही थी कि पैसा नहीं है और पैसे की व्यवस्था की जा रही है। जब हिमाचल प्रदेश की जनता को पता चला कि सरकार ने इन 14 माह में हिमाचल प्रदेश पर 14000 करोड़ रुपये के ऋण का अतिरिक्त बोझ डाल दिया है तब जनता को लगता था कि इस बजट के माध्यम से सरकार कुछ राहत जरूर देगी। लेकिन जब बजट प्रस्तुत हुआ तो वही बात हो गई कि 'खोदा पहाड़ और निकली चुहिया'।

मैं बताना चाहता हूं कि पिछले वर्ष दिनांक 17 मार्च, 2023 को इस माननीय सदन में वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट प्रस्तुत किया गया था और उसमें कुल 66 पन्ने थे। इस बार दिनांक 17 फरवरी, 2024 को इस माननीय सदन में वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट प्रस्तुत किया गया है और इसमें कुल 88 पन्ने हैं। अब पन्ने तो बढ़ा दिए गए लेकिन हिमाचल प्रदेश में रहने वाले जनमानस के लिए इस बजट में जो सुविधाएं होनी चाहिए थीं वे कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही हैं। प्रदेश के अन्नदाता, जिन्हें हम किसान कहते हैं, के संदर्भ में बात करूं तो पूर्व मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी ने अपनी सरकार के समय में एक 'प्राकृतिक खेती खुशहाल योजना' चलाई गई थी। इस बार सरकार ने उसमें नया कुछ भी नहीं किया और सरकार ने इस बजट में उस योजना का नाम बदल कर 'राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्ट'अप योजना' रख दिया। क्या नाम बदलने से काम हो जाएगा? नाम बदलने से हम

किसानों की आय को नहीं बढ़ा सकते। जब हम सरकार की ओर से किसानों को अच्छी योजनाएं व अच्छे लाभ देंगे तभी हम किसानों की मदद कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे किसानों की आय डबल या चार गुणा कैसे हो उसके लिए श्री जय राम ठाकुर जी की पूर्व सरकार ने 'मुख्य मंत्री नूतन पॉली हाऊस योजना' शुरू की थी। उस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से पॉली हाऊस को लगाने के लिए 85 प्रतिशत अनुदान दिया जाता था। लेकिन इस बजट में उस योजना का कोई जिक्र नहीं है।

श्रीमती के.एस. द्वारा जारी.....

19.02.2024/1725/केएस/वाईके/1

श्री विनोद कुमार जारी---

अब वह योजना खत्म हो गई क्योंकि लोगों ने प्लॉट बनाए हैं। जय राम ठाकुर जी की सरकार के समय हजारों की संख्या में हमारे युवा किसानों ने पोली हाउस लगाकर अपनी इन्कम को चार गुना करने का काम किया था। आज इस बजट के अंदर उस योजना का ज़िक्र नहीं किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री पोली हाउस रेनोवेशन के नाम से एक योजना हमारी सरकार के समय में शुरू की गई थी। जिन किसानों ने लम्बे समय से पोली हाउस लगाए थे, भारी बरसात के कारण, बर्फ पड़ने के कारण, ओलावृष्टि के कारण जो पोली हाउस नष्ट हो गई थे, उनकी रेनोवेशन के लिए हमारी सरकार ने70 परसेंट सब्सिडी का फिर से प्रावधान किया था ताकि किसानों को राहत मिल सके। लेकिन इस बजट में इस योजना का भी कोई ज़िक्र नहीं किया गया। इसके साथ-साथ एक योजना मुख्य मंत्री उत्तम फल सुरक्षा योजना के तहत एंटी हेलनैट दी जाती थी, मंत्री जी यहां पर बैठे हैं। एंटी हेल नैट की जो बात है, जितने हमारे सेब के क्षेत्र हैं जहां पर सेब अधिक संख्या में होता है वहां पर इस नैट के माध्यम से सेबों की सुरक्षा की जाती थी लेकिन आपनेदे खा होगा कि इस बजट में इस योजना के बारे में भी चर्चा नहीं की गई है।

अध्यक्ष महोदय, कृषि विभाग की ओर से लघु सिंचाई योजनाएं बनाई जाती हैं। छोटी-छोटी योजनाएं कृषि विभाग बनाता था। इस बजट में उसका भी ज़िक्र नहीं किया गया है। मेरा निवेदन रहेगा, हम तो किसान की इन्कम को दो गुना, चार गुना करने की बात करते हैं

लेकिन जब आप इतनी बेहत्तर योजनाएं बंद कर देंगे तो हमारा किसान किस तरह से आगे बढ़ेगा, इस बारे में हम सभी को चिंता करने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं युवाओं की तरफ इस सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हम जब घर से शिमला की तरफ आते हैं या हिमाचल के किसी भी कोने में जाते हैं, पहली केबिनैट और पहली केबिनैट में पांच लाख युवाओं को रोज़गार दिया जाएगा, यह आज भी बड़े-बड़े अक्षरों में जगह-जगह लिखा हुआ है। वह आपने ही लिखा है इसलिए या तो उसको मिटा दो या उन युवाओं को रोज़गार दो। मैं कहना चाहता हूं कि जो इस बार के बजट अनुमान प्रस्तुत किए गए, इनके अंदर युवाओं के

19.02.2024/1725/केएस/वाईके/2

साथ इस सरकार ने बहुत बड़ा छल किया है। आई.टी. के हजारों की संख्या में जो युवा इतने दिनों तक इस ठिठुरती ठंड में, इस बारिश में हिमाचल प्रदेश सचिवालय में, चौड़ा मैदान में बैठे रहे, आप आश्वासन पर आश्वासन देते रहे लेकिन इस बजट में उनके बारे में कोई चर्चा नहीं है। क्या हुआ उन पी.ई.टी. टीचर्ज़ का? शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं, हिमाचल प्रदेश के स्कूलों के अंदर शारीरिक शिक्षक के बहुत सारे पद खाली हैं। पता नहीं कितनी बार वे सरकार, मंत्री व मुख्य मंत्री के पास आ कर, चक्र लगाकर थक गए, उनको आश्वासन दिया गया लेकिन उनकी भी चर्चा इस बजट के अंदर नहीं की गई है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी----

19.02.2024/1730/एवी/एजी/1

श्री विनोद कुमार------ जारी

यहां पर जैसे माननीय सदस्य श्री दलीप ठाकुर जी हमारे कला अध्यापक साथियों के बारे में कह रहे थे। हमारे कुछ कला अध्यापक साथी 54-55 साल के हो चुके हैं। वे हमें पूछते हैं कि क्या हमें 58 वर्ष की आयु के बाद लगाएंगे? उनकी नौकरी का इंतजार करते हुए इतनी ज्यादा उम्र हो चुकी है। शिमला के चक्कर काटते-काटते अब उनका मन भर गया है।

उनको लेकर के इस बजट में कोई चर्चा नहीं की गई है। यहां पर शास्त्रियों का भी जिक्र आया था। प्रदेश के स्कूलों में शास्त्रियों की भी बहुत सारी पोस्ट्स खाली हैं परंतु उनके लिए भी बजट में कुछ नहीं कहा गया है।

स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत चाहे डॉक्टर की बात की जाए या स्टाफ नर्सिज व फार्मासिस्ट्स की बात करें, प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में इनके अनेकों पद खाली पड़े हैं। परंतु वर्तमान सरकार का ध्यान लोगों का स्वास्थ्य ठीक करने के बारे में नहीं है क्योंकि इनका खुद का ही हाज़मा खराब हो चुका है। इनका अपना ही स्वास्थ्य ठीक नहीं है।

हिमाचल प्रदेश में ऊर्जा विभाग के अंतर्गत भी बहुत सारे पद खाली हैं जिसके कारण काम में बहुत दिक्कतें रहती हैं। हमारे वहां चार-चार दिन तक बिजली नहीं आती। मैं माननीय सदस्य श्री सुख राम चौधरी जी की बात से सहमत हूं। मैंने एक दिन भी कहा था कि गोहर डिवीजन से 60 ट्रांसफॉर्मर्ज के लिए प्रपोज़ल भेजी जाती है और वर्तमान सरकार द्वारा केवल 4 ट्रांसफॉर्मर्ज दिए जाते हैं। अगर आप 60 की जगह 40 या 30 ट्रांसफॉर्मर्ज भी देते तब भी बात समझ आती परंतु 60 की जगह केवल 4 ट्रांसफॉर्मर्ज दिए गए। इसके अतिरिक्त मीटर तो आ ही नहीं रहे। आपने एक हफ्ते का टाइम दिया था और चार दिन बीत चुके हैं। सर्विस वायर और पोल इत्यादि कुछ भी नहीं मिल रहा। मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह कैसी व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार है? विद्युत विभाग के अंतर्गत भी बहुत सारी पोस्टें खाली हैं और उनको भरने बारे भी इस बजट में कोई जिक्र नहीं किया गया है।

(उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

19.02.2024/1730/एवी/एजी/2

कृषि विभाग और उद्यान विभाग के अंतर्गत अगर पूरे प्रदेश की जानकारी ली जाए तो इनमें भी लगभग 40 प्रतिशत पोस्टें खाली हैं। उनको भरने को लेकर भी यहां पर कोई बात नहीं की गई है। माननीय श्री संजय अवस्थी जी, इसके अतिरिक्त आउटसोर्स कर्मचारी जिन्होंने शायद कोरोनाकाल में आपके, यहां सदन में बैठे हुए सभी माननीय सदस्यों, अधिकारियों और विधान सभा के अधिकारियों/कर्मचारियों के परिवार के किसी-

न-किसी सदस्य की मदद की होगी। आपने उनको भी बाहर निकाल दिया। उनको एक आस थी कि इस बजट के अंदर निकाले गए आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर सरकार कोई बात करेगी परंतु इसमें उनके बारे में भी कुछ नहीं कहा गया। इसके अतिरिक्त एस0एम0सी0 के अध्यापकों ने यह कहा कि हमें सैलरी ज्यादा नहीं चाहिए, हमें पॉलिसी चाहिए। लेकिन इस सरकार ने इस बजट में उनको दोबारा से ठगने का काम किया और कोई पॉलिसी नहीं बनी। इसके अतिरिक्त मल्टी टास्क वर्कर्ज, वे चाहे आपके लोक निर्माण विभाग में लगे हैं या जल शक्ति विभाग या शिक्षा विभाग में लगे हैं, वे कितनी बार प्रस्ताव देने आए होंगे। उनको 4000 रुपये या 4500 रुपये सैलरी मिलती है। मुझे याद है जब धर्मशाला में हमारा शीतकालीन सत्र चला हुआ था तो उस दौरान वे सारे-के-सारे साथी हजारों की संख्या में आपसे इंसाफ की भीख मांगने आए थे। उनका कहना था कि हमें पैसा नहीं चाहिए लेकिन हमारी पॉलिसी में सुधार किया जाए। आपने कहा था कि सुधार करेंगे परंतु आपने उनकी बात को भी नहीं सुना। यहां पर बहुत-सी बातें की जाती हैं, आप जब विपक्ष में थे तो करुणामूलक आधार पर नौकरी देने के लिए बड़ी-बड़ी बातें करते थे। परंतु भाषणों से काम नहीं चलता अपितु निर्णय लेने से काम होता है।

टी सी द्वारा जारी

19.02.2024/1735/टी0सी0वी0/ए0जी0-1

श्री विनोद कुमार .... जारी ।

जो करुणामूल आधार पर नौकरी मिलनी है उनके बारे में भी सरकार की ओर से कोई बात नहीं की गई। हिमाचल प्रदेश में हमारे होमगार्ड के कर्मचारियों के बारे में भी सरकार की ओर से कोई बात नहीं की गई। उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने प्रदेश के युवाओं के साथ जिस तरह से छल किया है, आने वाले समय में ये युवा इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। युवा साथियों ने मुझे व्हाट्सऐप मैसिज भेजा है कि आप हमारी ओर से एक संदेश सरकार को दे देना। आदरणीय परमार साहब मैं उन दो लाइनों को यहां पर कहना चाहता हूं जो इस प्रकार से है :-

"वह वक्त गुजर गया, जब तेरी हसरत भी थी हमें,
अब तू खुदा भी बन जाए तो भी हम सजदा नहीं करेंगे।"

अब उन्होंने कह दिया है कि एक साल से सरकार ने हमारे जूते घिसा दिए है। सरकार ने 14 महीनों के अंदर बहुत जूते घिसा लिए लेकिन आने वाले लोक सभा के चुनाव में इसका जवाब आपको देने के लिए जनता निश्चित तौर पर तैयार बैठी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं किसानों की बात करना चाहता हू कि भैंस का दूध 55 रुपये लीटर लिया जाएगा और गाय के दूध के लिए 45 रुपये का रेट दिया जाएगा। मंत्री महोदय, शायद आपने आज तक अपने घर में नहीं पूछा होगा कि हम अपने घर में दूध किस तरह से लेते हैं। यहां सदन में जितने माननीय विधायक साथी बैठे हैं, गाय का दूध हम और आप 50 या 55 रुपये लीटर लेते हैं। किसानों दिमाग खराब है जो वे आपके 45 रुपये प्रति लीटर दूध के रेट पर आएंगे। आप लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हैं। अगर आज भैंस का दूध मार्केट में लेना है तो 60 या 65 रुपये प्रति लीटर मिलता है। वे आपके पास 55 रुपये में क्यों आएंगे? मेरा आपसे निवदेन रहेगा कि अगर आप जनता का भला नहीं कर सकते, उनके काम नहीं कर सकते तो कम-से-कम उस जनता को ठगने का काम भी मत करें।

19.02.2024/1735/टी0सी0वी0/ए0जी0-2

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर बात की गई कि मनरेगा के तहत 60 रुपये दिहाड़ी बढ़ा दी गई । मेरे मनरेगा के साथियों ने भी सरकार के लिए कुछ भेजा है। उन मनरेगा के मजदूर और मेरी बहनों ने लिखा है कि "बड़ा हसीन है आपकी जुबान का जादू, लगाकर आज बहारों की बात करते हैं।" जिसने मनरेगा के गरीब दिहाढ़ीदारों के 16 रुपये नहीं दिए वे लाखों की बात करते हैं। एक साल में आपसे 16 रूपय तो दिए नहीं गए और अब आप 60 रुपये देने की बात कर रहे हैं। माननीय अवस्थी जी पता कर लेना अगर मैं गलत हूं तो अभी विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा। आपकी सरकार ने अभी तक एक भी मजदूर

के 16 रुपये नहीं दिए हैं। आप 60 रुपये देने की बात कर रहे हैं। आपने गरीब मजदूर के पैसे नहीं दिए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि उनमें से भी 65 परसेंट हमारी बहनें हैं, जिनके पैसे आपकी सरकार ने नहीं दिए और मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रहे हैं।

एन0एस0 द्वारा जारी ।

19-02-2024/1740/एन0एस-ए0एस0/1

श्री विनोद कुमार ------जारी

उपाध्यक्ष महोदय, अब हद हो गई और अति हो गई। मैं आपकी पिछली बार की बजट बुक देख रहा था। यहां पर मुख्य संसदीय सचिव, श्री राम कुमार जी कह रहे थे कि हिमाचल प्रदेश दिनांक 31 मार्च, 2026 तक ग्रीन एनर्जी स्टेट बन जाएगी। इसका काम कहां शुरू हुआ? आप बता दो कि इसका काम कहां शुरू हुआ? इसके साथ-साथ वर्ष 2023-24 में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। मैं जानना चाहता हूं कि यह कहां शुरू हुआ? प्रदेश के युवाओं को उनको अपनी तथा लीज पर ली गई भूमि पर 250 किलोवाट के 2 मेगावाट तक सौर ऊर्जा परियोजना 40 प्रतिशत अनुदान पर स्थापित की जाएगी। आप बताएं, क्या ये शुरू हो गई है? इसके साथ-साथ प्राइवेट बस ऑपरेटर को ई-बस दी जाएगी। प्राइवेट ट्रक आपरेटरों को ई-ट्रक दिए जाएंगे। इस साल के अंदर अगर एक भी दिया होगा तो माननीय सुन्दर सिंह ठाकुर जी मैं कहना चाहता हूं कि या तो मैं रिजाईन दे दूंगा या आप रिजाईन दे दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले साल कहा गया था कि 1500 डीजल बसों को ई-बसों में चरणबद्ध तरीके से बदलने के लिए 1000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। आपने तो 1500 बसों की बात की थी, आप एक बस बता दो। इस 14 महीने के कार्यकाल में आपसे एक भी बस नहीं बदली गई। आप आगे की तो बात छोड़ो। आपने कहा था कि 20,000 मेधावी छात्रों को इलैक्ट्रिक स्कूटी पर 25,000 रुपये उपदान दिया जाएगा। आपने कितने छात्रों को दिया? आप सपने तो बड़े-बड़े दिखाते हैं। आपने यह योजना अभी शुरू भी नहीं की। आपने 20,000 तो क्या 20 छात्रों को अभी तक इस योजना का लाभ नहीं दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर बात हुई। मण्डी के एयरपोर्ट को लेकर कोई बात नहीं हुई। इसके साथ-साथ ए0डी0बी0 प्रोजैक्ट के तहत 1311 करोड़ रुपये आपको मिले हैं। उसमें आपने कुल्लू, शिमला, कांगड़ा, हमीरपुर और मण्डी का जिक्र किया है लेकिन मण्डी के शिवधाम का अभी तक काम शुरू नहीं हो पाया है। आपने कहा कि सभी मेडिकल कॉलेजिज में चरणबद्ध तरीके से रोबोटिक सर्जरी करवाई जाएगी। मैं जानना चाहता हूं कि यह सर्जरी कितने

19-02-2024/1740/एन0एस-ए0एस0/2

मेडिकल कॉलेजिज में शुरू हुई? यह सर्जरी एक भी कॉलेजिज में आज तक शुरू नहीं हो पाई। आपने कहा था कि सभी में हो जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय, दस्तावेज में कहा गया कि प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खोले जाएंगे। मैं जानना चाहता हूं कि इन आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों का क्या हुआ? सभी मेडिकल कॉलेजिज में पैट स्कैन सुविधा दी जाएगी। परमार जी, आपके पास यह विभाग रहा है तो कहीं गलती से शुरू तो नहीं हो गई। अगर शुरू हो गई है तो हमें भी पता लगना चाहिए। कैंसर के मरीज की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि उसको टैस्ट करवाने के लिए चण्डीगढ़ या दिल्ली जाना पड़ता है। यह बहुत महंगा टैस्ट है और गरीब व्यक्ति इस टैस्ट को नहीं करवा सकते।

आर0के0एस0 द्वारा ------जारी

19.02.2024/1745/RKS/AS-1

श्री विनोद कुमार...जारी

इसके साथ-साथ राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल का क्या हुआ? आप मुझे एक जगह का नाम बताएं जहां राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल खुल गया हो। बजट में कहा गया है कि - 'महाविद्यालयों में वर्ष में दो बार रोजगार मेले लगेंगे'। आप मुझे यह बताएं कि यह मेले कहां

लगे हैं? ...(व्यवधान) बजट बुक में कहा गया है कि - '7000 विधवाओं को घर बनाने के लिए मुख्य मंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना शुरू की जाएगी'। मैं पूछना चाहूंगा कि क्या ये घर किन्हीं सात बहनों को भी मिले हैं? बातें करने और काम करने में काफी अंतर होता है। लोक निर्माण मंत्री जी अभी यहीं बैठे थे लेकिन अब वे यहां से उठकर चले गए हैं। मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र की ग्राम पंचायत छपराहन और नांडी में एक पुल का निर्माण हुआ है। ग्राम पंचायत सयांज में पंगलूर के पास भी एक पुल का निर्माण हुआ है। सयांज और नांडी को जोड़ने के लिए भी एक पुल का निर्माण हुआ है। ग्राम पंचायत धरोहट के खारसी और ग्राम पंचायत भलाणा में भी एक पुल का निर्माण हुआ है। लेकिन इन पुलों में साइड की अप्रोचिज अभी तक नहीं लगी हैं। जब तक अप्रोचिज नहीं लगेगी तो स्वाभाविक रूप से लोगों को इन पुलों की पूरी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि आप विभाग को आदेश दें ताकि इन पुलों पर अप्रोचिज लगाई जा सके। मैं आपकी जानकारी के लिए यह भी कहना चाहूंगा कि सयांज पुल से एक 20 साल का नौजवान गिर कर मर गया था। अगर वहां पर समय रहते ये सारी चीजें कर दी होती तो वह दुर्घटना नहीं होती। हिमाचल प्रदेश के ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसे आपने ठगने का काम न किया हो। आपने किसानों-बागवानों और नौजवानों को ठगने का काम किया है। भाई सुन्दर सिंह ठाकुर जी आपने हमारी बहनों और माताओं को ठगने का भी काम किया है। आपने इन बहनों को 1500 रुपये देने की बात कही थी। आपने कहा था-'एक होला तो 1500, दूई होला ता 3000, तीन होला ता 4500 और 4 होला ता छः हजार'। जो छल-कपट यह सरकार कर रही है वह ठीक नहीं है। जनता इसका जवाब आने वाले लोक सभा चुनाव में देगी। उपाध्यक्ष महोदय, जो बजट यहां पर प्रस्तुत किया गया है मैं इसका समर्थन करने में असमर्थ हूं। इस बजट में हिमाचल प्रदेश के किसी भी वर्ग का ध्यान नहीं रखा गया है। मैं निश्चित तौर पर इस बजट का विरोध करता हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद।

19.02.2024/1745/RKS/AS-1

उपाध्यक्ष : अब इस चर्चा में श्री किशोरी लाल जी भाग लेंगे।

श्री किशोरी लाल (मुख्य संसदीय सचिव) : उपाध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री श्री सुक्खविन्द्र सिंह सुक्खू जी ने हिमाचल प्रदेश विधान सभा में वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान प्रस्तुत किए हैं।

श्री बी.एस.द्वारा... जारी

19.02.2024/1750/बी.एस./डी सी/-1

श्री किशोरी लाल जारी...

मैं यहां पर बजट की चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इस बजट का सर्मथन करता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने के लिए समय दिया, आपका दिल से आभार प्रकट करता हूं। यह सभी जानते हैं कि पिछली सरकार के समय में 75 हजार करोड़ रुपये का कर्ज और 12 हजार करोड़ रूपये की देनदारियां और प्रदेश में हुई भारी बारिश की वजह से 12 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। इसके बावजूद मुख्य मंत्री जी ने जो बजट यहां पर पेश किया है वह सराहनीय है। यह बजट विकासोन्मुखी, संतुलित और हर वर्ग को राहत देने वाला बजट इस विधान सभा में प्रस्तुत किया है। जिसकी हर वर्ग और प्रदेश के लोग सराहना कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष के लोगों को यह बजट हजम नहीं हो रहा है लगता कि इनका थोड़ा हाजमा खराब है। ये सभी जानते हैं कि पुरानी पैंशन बहाल हुई और कर्मचारी उसे अब प्राप्त कर रहे हैं परंतु विपक्ष के लोग उसके लिए भी इंकार कर रहे हैं उसे तो विपक्ष को स्वीकार करना चाहिए। इसी तहर से इस पैंशन योजना के तहत अब तक एक लाख 15 हजार कर्मचारियों ने ओ.पी.एस. को चुना है और ओ.पी.एस. में आए सभी कमचारियों ने जी.पी.एफ. प्राप्त कर चुके हैं तथा ओ.पी.एस. में आए लगभग पांच हजार कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पैंशन ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। क्या यह सत्य नहीं है? युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपये का स्टार्ट-अप योजना आरंभ की गई है, राजीव गांधी स्टार्ट-अप योजना के अन्तर्गत 50 प्रतिशत उपदान पर ई-टैक्सी और राजीव गांधी स्टार्ट-अप योजना के अन्तर्गत ही निजी भूमि पर 50 प्रतिशत उपदान पर 50 किलोवाट के सोलर पैनल लगाने का प्रावधान किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, 2.37 लाख महिलाएं जो प्रति माह 1100 रुपये पैंशन लेती थीं उन्हें 1500 रुपये तक पैंशन की गई है तथा लाहौल-स्पिति में महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह देने शुरू कर दिए हैं और जल्दी

ही इस योजना को अन्य जिलों में शुरू कर दिया जाएगा। प्रदेश में आपदा प्रभावित लोंगों को 4500 करोड़ रुपये का पैकेज दिया गया है तथा फौरी राहत समय पर मुहैया करवाई गई है। बरसात के दिनों में जब त्रासदी आई तो बैजनाथ विधान सभा चुनाव क्षेत्र में जहां-जहां भी घर गिरे थे मैं स्वयं वहां गया और फौरी राहत मौके पर उन लोगों को दी। यह भी सरकार का सराहनीय कार्य था। आज तक इससे पहले

19.02.2024/1750/बी.एस./डी सी/-2

इतनी राहत राशि कभी नहीं दी गई। जिन लोगों को पहले 1.30 लाख रुपये सरकार देती थी इसे बढ़ाकर सरकार ने सात लाख रुपये कर दिया है। जिन लोंगो का नुकसान आंशिक रूप का था उन्हें 6000 से बढ़ाकर एक लाख रुपया दिया गया है। इसी तरह से पहले यदि कहीं गौशाला गिर जाती थी तो उसे पैसा नहीं दिया जाता था परंतु अब सरकार ने 50 हजार रुपया दिया है। यह सरकारी का सराहनीय कार्य है। उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री सुख आश्रय योजाना के अन्तर्गत प्रदेश में 4000 से अधिक बच्चों को Children of the State के रूप में अपनाया है तथा उन्हें प्रति माह सरकार 11000 रुपये दे रही है। यह भी सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है। क्योंकि ऐसे बच्चों को कोई भी नहीं पूछता था। हमारे बच्चे ऐसी स्थिति में थे और जगह-जगह ठोकरें खाते थे। परंतु मेरे मित्रों को ऐसे बच्चों के लिए बातें बच्छी नहीं लगती हैं। प्रदेश में राजस्व अदालतें लगा करके 99,091 इंतकाल और 6000 तकसीमें एक साल में की है। परंतु इन्हें कुछ नजर नहीं आता। यह भी सरकार का एक सराहनीय कार्य है और ये बहुत सालों से लंबित कार्य पड़ा हुआ था। मेरे मित्र गला फाड़-फाड़ के कसानों के हितैषी बनते हैं परंतु जब मुजारा कानून बना तो उसका विपरोध किसने किया?

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

19.02.2024/1755/DC/DT/-1

श्री किशोरी लाल, मुख्य संसदीय सचिव जारी...

भारतीय जनता पार्टी ने किया और बैजनाथ में उस वक्त चौधरी हरदयाल जी मंत्री थे, उनकी कार जला दी गई थी। कौन लोग थे? वह भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। वह चीज आपको नजर नहीं आती मैं उसका चश्मदीद गवाह हूं। मैं उस समय वहां पर था । किसानों की मलकीयत को कांग्रेस पार्टी ने मालकना हक दिया। आज किसान खुशहाल हैं, क्योंकि वह भूमि के मालिक बनें हैं और वह भूमि उन्हें कांग्रेस पार्टी ने दी है। सारी व्यवस्था किसानों के लिए कांग्रेस पार्टी ने की है। आप लोग तो सिर्फ उस समय विरोध ही करते थे । उसी तरह से किसानों की आय बढ़ाने के लिए गाय और भैंस के दूध के मूल्यों में बढ़ोतरी की है। समय आने पर दूध के रेट को और भी बढ़ाएंगे। गाय का दूध 80 रुपए और भैंस का दूध 100 रुपए ऐसा हमारे मैनिफेस्टों में कहा लिखा है? जो किसान यूरिया और बारा-बत्ती-सोलह खाद के बिना फसल तैयार करेंगे ऐसे किसानों को गेंहूं का दाम 40 रुपए प्रतिकिलो और मक्की का दाम 30 रुपए प्रतिकिलो दिया जाएगा और यह पहली बार हुआ है। यह भी कांग्रेस पार्टी की बढ़ी उपलब्धि है। यहां पर पूर्व में मंत्री रहे श्री सुख राम चौधरी जी कहते थे कि मीटर नहीं है। अब 85 हजार मीटर आ गए हैं। वह कहते थे कि खंभे नहीं है अब खंभे भी आ गए हैं। पिछली सरकार के समय जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था थी उसको दुरूस्त करने में समय तो लगेगा ही। अब व्यवस्था परिवर्तन का समय है। अब व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है और आगे भी होगा। किसानों की आय बढ़ाने के लिए जाईका में फेज-2 प्रोजैक्ट, जिसके अतंर्गत सब्जी उत्पादन पर 50 हजार हैक्टर भूमि पर सब्जी उगाई जाएगी, यह भी प्रदेश सरकार द्वारा बहुत बढ़िया काम किया गया है। आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने इसके लिए भी पूरी योजना बनाई है और राज्य कृषि विपरण बोर्ड की कार्य प्रणाली को सुधारने के लिए भी प्रदेश सरकार काम कर रही है। यह भी सरकार का सराहनीय काम है। किसान अधिक दूध पैदा करे इसके लिए 500 करोड। रूपए की हिम गंगा योजना शुरू की गई है। माननीय सदस्य परमार जी तो जानते होंगे कि जिला कांगड़ा के ढगवार में एक बहुत बड़ा प्लांट विकसित किया जा रहा है। प्लांट के लिए जमीन ली गई है, काम शुरू हो गया है। जब प्लांट विकसित होगा तो उसमें पाउडर बनेगा और कई प्रकार के अन्य दूध के उत्पाद बनेंगे और उससे किसान खुशहाल होगा। इसी तरह से आप कांगड़ा को देखिए, इसे पर्यटक राजधानी घोषित किया है उसका आप

तालियां बजाकर स्वागत कीजिए। ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ। इसके विस्तारीकरण के लिए गगग्ल का जो हवाई अड्डा है उसका भी

19.02.2024/1755/DC/DT/-2

काम शुरू हो गया है। प्रदेश सरकार हर क्षेत्र में काम कर रही है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि प्रदेश में हमारे जो पशु पालक हैं उनके लिए 44 मोबाईल वेन चलाईं गई हैं। इसके द्वारा पशुओं का घरद्वार पर ही इलाज होगा। यह भी सरकार का एक सराहनीय काम है। किसानों और बागवानों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की है। इससे किसानों और बागवानों को लाभ होगा। पूर्व की यू0पी0ए0 सरकार द्वारा आरंभ की गई मनरेगा योजना में भी कामगारेां की देहाड़ी बढ़ाई गई है यह भी पहली बार हुआ है। एक मजदूर की दिहाड़ी 76 रूपये बढ़ी है, आप कहते हैं कि 16 रूपये भी नहीं बढ़ें हैं। अब 300 रूपए मजदूर को प्रतिदिन मजदूरी मिलेगी यह भी हम करके दिखाएंगे यह कोई बड़ी बात नहीं है। इसी तरह से पंचायती राज संस्थओं में सभी के मानदेय बढ़ाये गये हैं यह भी एक सराहनीय काम है। इससे उनकी हौंसला अफजाही होगी और वह अपना कार्य अच्छे ढंग से करे सकेंगे। जितने भी हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उन सभी का मानदेय बढ़ाया गया है। एक सबसे बढ़िया काम जिन्होंने रामायण लिखी, महार्षि वाल्मिकी जी, उनके जो अनुयायी हैं उनके लिए आवास योजना के लिए सरकार 3 लाख रूपये देगी।

श्री एज0जी0 द्वारा जारी.....

19-02-2024/1800/एच.के.-एन.जी/1

श्री किशोरी लाल.....जारी

आज तक उन्हें कोई भी नहीं पूछता था। वे बेचारे सारा साल काम करके ऐसे ही रह जाते थे और ऐसे लोगों को भी सरकार ने इस बजट के माध्यम से लाभ देने का काम किया है। इसी

प्रकार एकल नारियां व विधवाओं, जिनकी आय 2.5 लाख रुपये से कम है, को भी मकान बनाने के लिए 3 लाख रुपये दिए जाएंगे। सरकार द्वारा 'प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना-III' के अंतर्गत 500 किलोमीटर लंबी सड़कों की अपग्रेडेशन का काम शुरू किया जाएगा। 325 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण होगा। 8 पुलों का निर्माण का निर्माण होगा। 15 बस्तियों को सड़कों से जोड़ा जाएगा। इस प्रकार 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' के अंतर्गत 825 किलोमीटर लंबी सड़कों व 8 पुलों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश सरकार ने हर वर्ग को राहत देने वाला बजट इस माननीय सदन में पेश किया है। इस बजट की हर तरफ सराहना हो रही है। मैं बजट का पूर्ण समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय हिमाचल, जय बाबा बैजनाथ।

समाप्त/-

19-02-2024/1800/एच.के.-एन.जी/2

उपाध्यक्ष : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य, श्री के0 एल0 ठाकुर जी भाग लेंगे।

श्री के0 एल0 ठाकुर (नालागढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी द्वारा दिनांक 17 फरवरी, 2024 को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट प्रस्तुत किया गया है और मैं इसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश की वर्तमान आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए जो बेस्ट पोसिबल बजट बनाया जा सकता है, उसी प्रकार इस बजट को बनाया गया है। इस बजट में काफी इनोवेशन्ज़ दिखाई दे रहे हैं। यह बजट हर वर्ग के लिए है। कृषि क्षेत्र के लिए काफी कुछ किया गया है। युवा वर्ग के लिए भी इस बजट में बहुत कुछ है। खिलाड़ियों की डाइट मनी बहुत कम हुआ करती थी और उसे इस बजट के माध्यम से 4 से 5 गुणा तक बढ़ाया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के लिए पुरुस्कार राशि को भी कई गुणा बढ़ाया गया है। हमारे खिलाड़ी आमतौर पर कहते थे कि हरियाणा व पंजाब में हिमाचल से ज्यादा पुरुस्कार राशि मिलती है। जिस कारण हमारे प्रदेश के

खिलाड़ी अन्य प्रदेशों से खेलते थे और हमारे लिए बहुत अजीब परिस्थितियां बन जाती थीं। उनकी समस्या को ध्यान में रखते हुए पुरुस्कार राशि में सिगनिफिकेंट इंक्रीज़ किया गया है। इस कारण मैं इस बजट की सराहना करता हूं।

इस बजट के माध्यम से कृषि क्षेत्र में ऑर्गेनिक फर्मिंग के लिए बहुत प्रोत्साहन दिया गया है। यदि कोई किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग करता था तो उसे एश्योर्ड मार्किटिंग की समस्या रहती थी। उसके लिए इस बजट में एम.एस.पी. को बढ़ाया गया है और गेंहूं के लिए 40 रुपये प्रति किलो और मक्की के लिए 30 रुपये प्रति किलो का प्रावधान किया गया है। यह बहुत अच्छी शुरूआत है। मुझे लगता है कि यह अगले साल और बढ़ाई जा सकती है। यदि हम ग्रीन हिमाचल की बात करें तो इसके लिए प्रदेश सरकार ने काफी अच्छा काम किया है। इसमें डीज़ल वाहनों को इलैक्ट्रिकल वाहनों में बदलने के बारे में सरकार काम कर रही है। सबसे पहले प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में सभी डीज़ल वाहनों को इलैक्ट्रिकल वाहन में बदलने का प्रावधान इस बजट में किया गया है। इसके बाद धीरे-धीरे युवाओं के लिए इलैक्ट्रिकल वाहनों पर सब्सिडी फेज़ड मैनर में ऑन द बेसिस ऑफ बजट

श्रीमती के.एस. द्वारा जारी.....

19.02.2024/1805/केएस/एचके/1

श्री के0 एल0 ठाकुर (नालागढ़) जारी---

के आधार पर फेज्ड मैनर में सभी गाड़ियों के लिए जो 50 परसेंट सब्सिडी देने का प्रावधान है, यह बहुत अच्छा कदम है और इसमें युवाओं को आगे आने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही निजी भूमि पर जो सोलर पावर प्लांट लगाएंगे या पंचायतों में भी लीज़ पर सरकार देगी, उसके लिए 50 परसेंट सब्सिडी सरकार देगी। यह भी हमारे युवाओं को एश्योर्ड इन्कम होगी। इसी तरह से 32 मैगावाट क्षमता वाला सोलर प्लांट जो ऊना के पेखुबेला में स्थित है, उसको भी बहुत जल्दी ही कमिशन किया जाएगा। यह बहुत अच्छा योजना है क्योंकि जो हमारी कोल और हाईडल एनर्जी है यह लिमिटिड है और इसका कहीं ना कहीं एंड हो रहा है तो इसलिए नॉन कन्वेंशनल की तरफ बढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए सोलर एनर्जी की तरफ सरकार बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। आने वाले समय में इसका हमें बहुत लाभ होगा क्योंकि यह स्टैप समय पर उठाया गया है। जैसे मुख्य मंत्री जी

ने कहा कि आने वाले 10 साल में हिमाचल आत्मनिर्भर बन जाएगा। मुझे लगता है कि यह निश्चित तौर पर होगा। जैसे आय बढ़ाने के लिए एक्साइज़ में पिछले साल को देखें जो एक्साइज़ में लगभग 30-35 परसेंट की इन्क्रीज़ हुई है। यह बहुत अच्छी बात है। वाटर सैस लगाया है यह भी बहुत अच्छी बात है। हमारे पड़ोसी प्रदेशों को इससे थोड़ी समस्या आई परन्तु मुझे लगता है कि अंततः हम उसमें कामयाब होंगे।

उपाध्यक्ष जी, हम कहां से रेवन्यू बढ़ा सकते हैं, सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अच्छे-अच्छे इनिशियेटिव्ज़ लिए गए हैं। बहुत सी स्कीमें हैं लेकिन पीछे जो आपदा हिमाचल में आई, मुझे लगता है कि हमने अपने जीवन में वर्षा से इतना नुकसान पहले कभी नहीं देखा था। सरकार ने उसको जिस प्रशंसनीय ढंग से डील किया, उसके तो हम वैसे ही कायल है। रिलीफ मैनुअल को अमैंड करना और पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त घरों के पुनर्निर्माण के लिए दी जाने वाली राशि को 1 लाख 30 हजार से 7 लाख करना बहुत अच्छा कदम है और उसको प्रैक्टिकली इम्पलीमेंट भी किया तथा 3 लाख रुपए पहली इन्स्टॉल्मैंट थी। यह बहुत अच्छी बात है।

इसी तरह से हैल्थ के क्षेत्र में कहना चाहूंगा। हमारे यहां बहुत कम स्पैशलिस्ट डॉक्टर होते थे। जो हमारे सी.एच.सी. हैं या सिविल हॉस्पिटल्ज़ हैं, मैं नालागढ़ की

19.02.2024/1805/केएस/एचके/2

बात बताऊं तो हमारे यहां पांच स्पैशलिस्ट डॉक्टर्ज़ की पोस्टिंग हो चुकी है। यह बहुत बढ़िया स्टैप है। आदर्श स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना भी एक बहुत अच्छा कदम है। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल कुछ चुनाव क्षेत्रों में शुरू हो गए हैं और हमें भी उसमें स्थान मिलेगा। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार आगे बढ़ रही है।

उपाध्यक्ष जी, मैं उद्योगों के बारे में कहना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में जितना कार्य होना चाहिए, उतना नहीं हुआ है। क्योंकि बजट में इंडस्ट्री फ्रेंडली कहा गया है परन्तु इंडस्ट्री फ्रेंडली में कुछ इंसेंटिव्ज़ देने होंगे क्योंकि हिमाचल में इंडस्ट्री तभी आएगी जब हम कुछ अलग से करेंगे। ए.जी.टी.जो बढ़ाया है, उसको भी विद्ड्रॉ करना पड़ेगा। साथ में और क्या-क्या

इंसेंटिव्ज़ हम दे सकते हैं, वह भी देखना है और इलैक्ट्रिसिटी बिल्ज़ पर एक्साइज़ डियूटी कम कर दी है यह बहुत अच्छी बात है। जो बढ़ाई थी उसको वापिस ले लिया है।

सीमेंट इंडस्ट्रीज़ के बारे में भी बताना चाहूंगा क्योंकि हमारे नालागढ़ में भी सीमेंट के दो युनिट्स हैं। एक बघेरी में अल्ट्राटैक का है और दूसरा नवांग्राम में अम्बुजा का है। वे लोग मुझसे मिलने भी आए थे और मुझे वाकई उनकी प्रॉब्लम प्रैक्टिकल लगी। हम उसमें डबल ले रहे हैं। एक बार क्लींकर पर 60 रुपये पट्टा ले रहे हैं।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी----

19.02.2024/1810/एवी/वाईके/1

श्री के0 एल ठाकुर ------ **जारी**

उसका फिनिश्ड जब सीमेंट बन जाता है तो वह शायद 220 रुपये प्रति टन है। मेरे हिसाब से डबल करना तो कोई लॉजिक नहीं बनता। छोटे से गेन के लिए यानी 60 रुपये प्रति टन के चक्कर में अब यह हो रहा है कि उन दोनों प्लांट्स ने राजपुरा और पंजाब में अपने प्लांट्स लगा दिए हैं। वे बता रहे थे कि पहले डेढ़ लाख टन का था, अब 75 लाख टन कर दिया है और फिर 50 लाख टन का सोच रहे हैं यानी हिमाचल में प्रोडक्शन 50 लाख टन करेंगे। इससे बड़ा भारी नुकसान हो रहा है इसलिए मैंने उनसे कहा कि क्लिंकर कहां से लाएंगे। उन्होंने बताया कि क्लिंकर तो हम राजस्थान से ट्रेन द्वारा लाएंगे क्योंकि ट्रेन का किराया भी बहुत कम है। हमारी जब प्रोडक्शन ही कम हो जाएगी तो जी0एस0टी0 जो हमें 220 रुपये प्रति टन मिलता था, इसलिए छोटे से गेन के लिए ऐसा करना अच्छा नहीं रहेगा। मैंने इस बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी से बात भी की थी। इसको हम बीच में भी विड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि अभी तो बजट पास होना है। इसलिए मेरा इस बारे में सुझाव रहेगा कि आप इसको करें क्योंकि अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य युवाओं को रोज़गार देने के साथ-साथ स्टेट की इन्कम बढ़ाना भी है। मुझे लगता है कि डबल वसूल करने से हमारा वह टारगेट अचीव नहीं हो पाएगा बल्कि उलटे हमें घाटा होगा। इसलिए इस इश्यू को देखें। उद्योग क्षेत्र में हमारे प्रदेश को अभी काफी कुछ करना है। देश के दूसरे राज्य जैसे उत्तर प्रदेश में भी

हमारी बहुत सारी इंडस्ट्रीज जा रही हैं। जम्मू-कश्मीर में तो केंद्र सरकार ने थ्री हंडर्ड टाइम इनपुट पर जी0एस0टी0 कर दिया है। इसलिए इण्डस्ट्रीज वहां को भी भाग रही हैं। इसलिए दूसरे राज्यों से कंपीट करने के लिए उद्योगों को लाभ देने की बात करनी चाहिए। इस बारे में सरकार को सीरियसली विचार करना चाहिए ताकि हमें कोई नुकसान न हो जाए।

इसके अतिरिक्त ग्रीन स्टेट की बात की गई है और उस बारे में एक अच्छी पहल की गई है। मैं उसके लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की प्रशंसा करता हूं। इसके अतिरिक्त खेल के बारे में भी बात की गई है।

मैं अब लोकल नालागढ़-दून की बात करना चाहूंगा। हमारे बी0बी0एन0डी0ए0 में यह प्रोब्लम आ रही है क्योंकि जब मैं पहली बार एम0एल0ए0 बना था तो हमारा बजट लगभग 60 करोड़ रुपये तक था और ग्रांट-इन-एड होती थी। माननीय उद्योग

19.02.2024/1810/एवी/वाईके/2

मंत्री जी भी आ गए हैं। बी0बी0एन0डी0ए0 उद्योग विभाग के अंतर्गत ही आता है। उस समय हम 60 करोड़ रुपये तक पहुंच गए थे जो ग्रांट-इन-एड दी जाती थी। हमारी सरकार को बी0बी0एन0डी0ए0 से बहुत ज्यादा राजस्व प्राप्त होता है। वह आंकड़ा टोटल राजस्व का 40 प्रतिशत या 45 प्रतिशत भी हो सकता है, अभी मेरे पास आंकड़े नहीं है। परंतु बी0बी0एन0डी0ए0 का प्रदेश सरकार के राजस्व में काफी योगदान है इसलिए प्रदेश सरकार को इनके लिए दिल खोलकर काम करने चाहिए। पहले जो 50-60 करोड़ रुपये तक पहुंचा था तो इस साल वह जीरो है। अगले साल के लिए ग्रांट-इन-एड का कोई प्रोविजन नहीं किया गया है। यहां पर माननीय सदस्य श्री राम कुमार जी ने तो कहा कि ग्रांट-इन-एड सौ करोड़ रुपये होनी चाहिए। परंतु वह तो मुझे हाइपोथैटिकल बात लग रही है क्योंकि हमें प्रदेश की वित्तीय स्थिति का भी पता है। इसलिए हमें इस ढंग से करना चाहिए जो पॉसिबल/फीजिबल भी हो। इसलिए मेरा सुझाव रहेगा कि बजट पास करने से पहले इसको देखना बहुत जरूरी है। अगर 50 करोड़ रुपये ग्रांट-इन-एड हो क्योंकि इण्डस्ट्रीज की वजह से हमारे वर्कर्ज का लोड, उसमें चाहे पीने की पानी की बात हो,

गलियों या सड़कों की बात हो या पार्क की जरूरत है, इन सबके कारण हमारे ऊपर एडिशनल बर्डन है। वहां उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डवलप करने के लिए या एडिशनल फेसिलिटीज देने के लिए ग्रांट-इन-एड देना बहुत जरूरी है। यह लगभग 50 करोड़ रुपये होनी चाहिए परंतु इसका बजट में कोई जिक्र नहीं किया गया है। उसमें केवल टोकन रखा गया है परंतु टोकन को तो बढ़ाया भी जा सकता है। इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पिछले कुछ वर्षों से विकास कार्यों पर खर्च केवल दून निर्वाचन क्षेत्र में ही हो रहा है। मेरा अनुरोध है कि एरिया और जनसंख्या के आधार पर फंड्ज की डिस्ट्रीब्यूश्न होनी चाहिए क्योंकि बद्दी ओवर इण्डस्ट्रीयलाइज हो चुका है। वहां पर बहुत ज्यादा कंजेशन हो चुकी है और नालागढ़ में चाहे सरकारी जमीन की बात की जाए या प्राइवेट लैंड की बात करें, वहां पर अब पोटेंशियल ज्यादा है। उस तरफ अब इंडस्ट्रीज जा भी रही हैं। हमारी अच्छी-अच्छी इण्डस्ट्रीज हैं।

टी सी द्वारा जारी

19.02.2024/1815/टी0सी0वी0/वाई0के0-1

श्री के0ए0 ठाकुर..... जारी ।

वहां पर अच्छी-अच्छी इंडस्ट्रीज जा रही है जैसे मेडिकल डिवाइज पार्क, ए0पी0आई0, तिरमन के नाम से 400 करोड़ रुपये का प्रोजैक्ट है। ...(घंटी) उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो मैंने शुरू ही किया है। मैंने आज बोलना ही नहीं था लेकिन अध्यक्ष महोदय ने कहा कि आज आप डिटेल में बोल सकते हैं। मैं सिर्फ अपने विधान सभा क्षेत्र की ही बात कर रहा हूं, कोई पूरे स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं। मैं 10-15 मिनट और बोलूंगा। बी0बी0एन0 एरिया की कुल पंचायतें, उसका कुल क्षेत्र में नालागढ़ विधान सभा चुनाव क्षेत्र का 65 प्रतिशत कवर करता है और 35 प्रतिशत दून क्षेत्र में आता है। मेरी मांग है कि वहां पर जो भी पैसा खर्च हो रहा है वह एरिया और जनसंख्या के आधार पर खर्च होना चाहिए यानी 2/3 नालागढ़ विधान सभा चुनाव क्षेत्र में और 1/3 दून क्षेत्र में खर्च होना चाहिए ताकि नालागढ़ की ओर

भी इडंस्टियलिस्ट आकर्षित हों। वहां पर प्राइवेट सेक्टर में काफी उद्योग लग रहे हैं लेकिन वहां केन्द्र या राज्य के उद्योग भी स्थापित होने चाहिए। नालागढ़ में स्वास्थ्य संस्थान, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलीटेक्निकल कॉलेज इत्यादि हो ताकि नालगढ़ का जो एक ऐतिहासक वैभव है उसको मेंटेन करने के लिए कार्य किए जा जाए। ऐसी वहां के लोगों की डिमांड है। माइनिंग के बारे में यहां माननीय सदन में काफी चर्चा होती है। माइनिंग अब एक कंसैप्ट बन चुका है। पहले माइनिंग को नेगटिव माना जाता था लेकिन ऐसा नहीं है माइनिंग होनी चाहिए scientific mining and legal mining सरकार को माइनिंग लीजिज के लिए एनक्रेज करना चाहिए और माइनिंग लीजिज जल्दी देनी चाहिए। ग्रीन ट्रिब्यूनल की जो क्वायरीज होती है उनको शीघ्रतिशीघ्र अटेंड करना चाहिए। माइनिंग के लिए अप्लाई करने से इलीगल माइनिंग रुकती है। इससे सरकार के एक्सचैकर में भी वृद्धि होती है जोकि बहुत जरूरी है। राज्य की आर्थिक स्थिति को देखते हुए ज्यादा-से-ज्यादा माइनिंग लीज अलॉट हो। इससे लोगों को काम मिलेगा। रेत और बजरी का रेट कम होगा और इलीगल माइनिंग रुकेगी। मैं इलीगल माइनिंग के बहुत अंगेस्ट हूं और सरकार भी इसके अंगेस्ट है। हम सरकार की मंशा पर कोई शक नहीं कर सकते हैं लेकिन फिर भी इलीगल माइनिंग का सिलसिला थम नहीं रहा है। यह मैंने पिछली बार

19.02.2024/1815/टी0सी0वी0/वाई0के0-2

प्लानिंग की मिटिंग में भी कहा था। माइनिंग डिर्पाटमेंट और पुलिस की जितनी मेन पावर होनी चाहिए थी उतनी नहीं है। इस बजट में मुख्य मंत्री जी पुलिस के कर्मचारियों की डाइट मनी बढ़ाई है, उसको 200 रुपये से 1000 रुपये किया है। इसकी बड़े लम्बे समय से मांग थी। यह बहुत ही बढ़िया कार्य किया है। मैं इसके लिए बजट की सराहना करता हूं। जो इलीगल माइनिंग हो रही है वह पंजाब को जा रही है। हमारे घर के पास से भी हैवी टिपर रातभर चलते रहते हैं। अगर लैसी भी है तो वह भी रात को टिपर या ट्रक नहीं चल सकता है। इसके बारे में मैं कई बार अधिकारियों को कह चुका हूं परंतु पता नहीं उनकी क्या

मजबूरियां है कि वह रुक नहीं रही है। वे लोगों के खेत तक उखाड़ देते हैं। हो सकता है कि ऐसा पूरे प्रदेश में होता होगा लेकिन बी0बी0एन0 में तो हो रहा है और हमारे सामने हो रहा है। इसके स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। मुझे लगता है कि जो ट्रिब्यूनल की गाइडलाइन्स हैं उसके मुताबिक 1/3 ऑफ दि वैल्यू ऑफ व्हीकल का फाइन है। अगर ऐसे 2-4 चालान हो जाएंगे तो इलीगल माइनिंग अपने आप ही बंद हो जाएगी।

एन0एस0 द्वारा जारी ।

19-02-2024/1820/एन0एस-ए0जी0/1

श्री के0एल0 ठाकुर ------जारी

अगर बंद नहीं तो काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। शत-प्रतिशत तो नहीं लेकिन कम हो जाएगी। इसके लिए एफ0आई0आर0 का होना बहुत जरूरी है। केस हो, व्हीकल जब्त हो, यह तभी हो पाएगा। इसको करना जरूरी है। दूसरा, नशे की बात है। विशेषकर सिंथैटिक ड्रग की बात है। पहले हम पंजाब के लिए कहते हैं लेकिन अब नशे का प्रचलन हिमाचल में भी कम नहीं है। प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में तो है ही लेकिन अब दूरदराज के क्षेत्रों में भी नशा पहुंच गया है। इसके लिए एक स्पैशल टास्क फोर्स बनाने की काफी आवश्यकता है। नशा मुक्ति केंद्र अभी कंडाघाट में नया प्रपोज किया गया है, इसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। इसके लिए अलग से टास्क फोर्स स्ट्रैंथन करें। हर विभाग के ऑफिसर/ऑफिशियल इसमें शामिल हों जो मिशनरी मोड पर काम करें। ये कागजों में कहने के लिए नहीं होने चाहिए बल्कि प्रेक्टिकली उसका रिजल्ट आना चाहिए। आप जितनी मर्जी डवल्पमेंट कर लें या जितना मर्जी बोल लें, अगर हमारा यूथ नशे की तरफ बढ़ेगा तो हम यह नहीं कह सकते कि हमने कुछ किया है। हमारी डवल्पमेंट कोई मायने नहीं रखेगी अगर हम यूथ को नशे से नहीं रोक पाएंगे। माइनिंग और नशे का कारोबार आपस में जुड़ा हुआ है। जब नौजवान नशे में पड़ते हैं विशेषकर सिंथैटिक ड्रग जिसको चिट्टा बोला जाता है तो वह उसके लिए इतना महंगा है कि वह उसके लिए कुछ भी करने

को तैयार रहता है। उसके लिए वे चोरी और अवैध कामों को भी करते हैं। इन दोनों को इंटर लिंक करके इस पर चैक रखना समय की आवश्यकता है। उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने बहुत अच्छा बजट दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं संस्थानों की बात करना चाहूंगा। अभी मुख्य मंत्री जी यहां पर नहीं बैठे हैं। मेरे क्षेत्र नालागढ़ में काफी संस्थान डिनोटिफाई हुए हैं और वे बहुत जरूरी हैं। डवल्पमेंट ब्लॉक, राम शहर में है और इसको दोबारा से खोला जाए। एक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, बरूआं चंगर क्षेत्र में डेंसली पॉपुलेटिड है। न केवल हिमाचल बल्कि पंजाब के छात्र भी वहां पढ़ने आते हैं। यह कॉलेज बहुत अच्छा चल रहा था लेकिन बंद कर दिया गया। मैं निवेदन करता हूं कि इसको दोबारा खोला जाए। इसके अतिरिक्त दो पी0एच0सीज0 दियोली और पंजेरा में हैं इनको भी डिनोटिफाई किया गया है। नालागढ़ में 200 बिस्तरों के अस्पताल को सरकार आदर्श स्वास्थ्य

19-02-2024/1820/एन0एस-ए0जी0/2

संस्थान में कवर करने जा रही है। उसमें 5 विशेषज्ञ तैनात करना एक अच्छे स्वास्थ्य की तरफ कदम है। राम शहर में 50 बिस्तरों वाले अस्पताल की मांग थी। इसके अतिरिक्त दो फायर सब-स्टेशन खोलने की मांग है। एक राम शहर में खोलने की मांग है क्योंकि वहां पर काफी जंगल है और जब आग लगती है तो बहुत नुकसान होता है और नालागढ़ से फायर ब्रिगेड आने में काफी समय लगता है। अगर यहां पर एक फायर स्टेशन और गाड़ी दे दी जाए तो काफी लाभ होगा। दूसरा चंगर क्षेत्र में बघेरी में फायर स्टेशन की मांग है। वर्तमान सरकार अच्छा कार्य कर रही है और इसके अच्छे परिणाम आएंगे। हमारा प्रदेश सैल्फ रिलायंट स्टेट बनेगी।

मैंने गरीब किसानों की बात पहले कर ली है। यहां पर इन्वैस्टर फ्रेंडली की भी बात हो गई है। मेरी अनस्किल्ड युवाओं के बारे में भी बात हो गई है। पूरे प्रदेश में ट्रांसफार्मर्ज की समस्या है। नालागढ़ में भी कम-से-कम 4 ट्रांसफार्मरों की आवश्यकता है। यह सप्लाई ऑफ पॉवर टू इरिगेशन जो नये ट्यूब वैल्ज लगने हैं और इसके लिए हम डेढ़ साल से इंतजार कर रहे हैं।

मनरेगा की दिहाड़ी बढ़ाने के लिए मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया वाइंडअप कीजिए।

श्री के0 एल0 ठाकुर : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में स्टांप वैंडर्ज की भी समस्या है और यह अन्य स्थानों से भी डिमांड आ रही है। इसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। ठेकेदार काम करेंगे। मेरे क्षेत्र में बड़ी मांग आ रही है। स्टांप वैंडर्ज में जो कंटीन्यू सिस्टम चला हुआ है तो कृपया उसी को कंटीन्यू करें। फिलहाल उसका टेंडर न किया जाए तो अच्छी बात है। उनका रोजगार नहीं छीना जाना चाहिए अन्यथा बहुत मुश्किल होगा। यहां पर उद्योग मंत्री जी बैठे हैं। मेरे क्षेत्र में एक ब्रिज है और यह ब्रिज दो औद्योगिक क्षेत्रों को मिलाता है। यह कृपालपुर

आर0के0एस0 द्वारा ------जारी

19.02.2024/1825/RKS/Aजी-1

श्री के0एल0 ठाकुर...जारी

और जो मंझोली का एरिया है वहां मेडिकल डिवाइस पार्क और एक्सलूसिव कारखाने स्थापित हो रहे हैं। वहां मंडयारपुर के लिए सिंगल लेन ब्रिज का टेंडर अवार्ड हो चुका है। पहले उद्योग विभाग ने इस पुल का निर्माण रूकवा दिया था। इस पुल के निर्माण के लिए 6 करोड़ रुपये का टेंडर अवार्ड हुआ था लेकिन इसे डबल लेन बनाने के लिए यह काम रूकवा दिया था। मैंने इस संबंध में मंत्री जी से भी बात की थी और इसके निर्माण कार्य के लिए 12-13 करोड़ रुपये का एस्टीमेट बना दिया गया था। हमारे पास 6 करोड़ रुपये पहले के पड़े हैं और इसके लिए टेंडर भी हो गया है। लेकिन डबल लेने बनाने की वजह से यह काम 6 महीनों से रूका हुआ है। मेरा आग्रह है कि इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसके लिए I will feel obliged and the public of Nalagarh will also feel obliged.

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री के. एल. ठाकुर : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी काफी विषयों में बात हो गई है। Let me wind it up. मैं सब्जी मंडी रामशहर की बात करना चाहूंगा। हमारे कृषि मंत्री जी सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं। सब्जी मंडी रामशहर में टोकन सिस्टम है। मैं मानता हूं कि सब्जी मंडी के लिए लम-सम बजट का प्रावधान होता है। इस सब्जी मंडी के बनने से नालागढ़, दून और अर्की विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को काफी फायदा होगा। हमारे पहाड़ी क्षेत्र में लोगों को ऑफ सीजन सब्जियां और फलों से काफी अच्छी इनकम होती है। अगर इस क्षेत्र में एक वेजिटेबल एंड फ्रूट प्रोसैसिंग प्लांट स्थापित हो जाए तो इससे लोगों को काफी फायदा होगा। पंचायती राज संस्थानों में जो एनहांसमेंट हुई है इसके लिए भी मैं सरकार का बहुत धन्यवादी हूं। हमारे पंचायत प्रतिनिधियों, प्रधान, जिला परिषद् या शहरी निकायों के जो पदाधिकारी हैं उन्हें बहुत काम करना पड़ता है। अन्य वर्गों को भी बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की गई हैं इसके लिए भी मैं मुख्य मंत्री जी का बहुत आभारी हूं। हमारे उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए मुख्य मंत्री जी की गाइडलाइंस में जो वित्त विभाग के अधिकारियों ने बजट तैयार किया है, वह बहुत सराहनीय है। साल के अंत तक इस बजट के अच्छे रिजल्ट हमारे सामने आएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस बजट में आउट ऑफ टर्न बोलने का मौका दिया क्योंकि मुझे कल बोलना था और आपने आज ही बोलने का मौका दिया, इसलिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

19.02.2024/1825/RKS/Aजी-2

उपाध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र शौरी इस चर्चा में भाग लेंगे।

श्री सुरेन्द्र शौरी : उपाध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री जी ने 17 फरवरी, 2024 को वर्ष 2024-25 के लिए जो बजट अनुमान इस सदन में प्रस्तुत किए हैं, आपने इन पर मुझे बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद। मैं वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान भी पढ़ रहा था। मैं इन दोनों बजटों की तुलना कर रहा था। जो बजट पिछले वर्ष 17 मार्च, 2023 को इस सदन में रखा गया था उस बजट के अंदर 183 बिंदू और 52 पन्ने थे लेकिन इस बजट में 194 बिन्दू और 72 पन्ने हैं।

श्री बी.एस.द्वारा... जारी

19.02.2024/1830/बी.एस./ए एस/-1

श्री सुरेन्द्र शौरी जारी...

मैं देख रहा हूं कि इस बार के बजट में बिंदु भी बढ़ गए और पन्ने भी बढ़ गए। लेकिन जो पिछली बार के बजट में योजनाएं थीं उसमें अधिकांश योजनाएं सरकार धरातल में उतार नहीं पाई। यदि हम इसमें तुलना करें तो पिछली बार के बजट में ऐसी योजनाएं थीं जिनका इस प्रदेश की जनता को किसी तरह का कोई लाभ नहीं हुआ। यह सरकार इन्हें धरातल में उतारने के लिए गंभीर नहीं दिखी और न ही अधिकारी गंभीर दिखे।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर मैं अपनी बात पर्यटन से शुरू करूं तो पर्यटन हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए रिसोर्स को मोबिलाइजेशन करने के लिए, जिस प्रर्यटन के कारण हर घर को लाभ होता है, हजारों, लाखों युवाओं को लाभ मिलता है। इस बार के बजट पर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। इस बजट में हम देख रहे हैं कि पिछली बार भी बजट में कांगड़ा एयरपोर्ट की विस्तारीकरण की बात की गई थी और इस बार भी की है परंतु एक साल में हम कहीं भी आगे नहीं बढ़ पाए हैं। भूतंर एयरपोर्ट की बात करें तो अभी कुछ दिन पहले अखबारों के अदंर खबर छपि की भूंतर एयरपोर्ट का एफ.सी.ए. हो गया लेकिन इस बार के बजट में देख रहे हैं कि इस ऐयरपोर्ट को विस्तरीकरण के लिए कोई भी बजट का प्रावधान नहीं है। मैं अपनी विधानसभा में देखता हूं कि जब इस प्रदेश के मुख्य मंत्री जय राम ठाकुर जी थे उन्होंने पर्यटन के लिए विशेष बजट का प्रावधन किया था "नई राहें नई मंजिले" योजना ला करके ऐसे अनछुये प्रर्यटक स्थलो को विकसित किया था। लेकिन उसमें हमारा एक पर्यटन स्थल लारजी का था। परंतु इस आपदा के कारण आठ करोड़ रुपये से वहां बनाई गई सड़क भी डैम में चली गई और उस सड़का का छह महीनों से कोई जिर्णोद्धार नहीं किया गया है। हमारे ओट का पुल चला गया, इसके लिए भी कोई बजट का प्रावधान नहीं किया गया है और न ही सरकार उस पुल को लगाने के लिए गंभीर है। वहां पर कैफेटेरिया एरिया पांच करोड़ की लागत से बना है, कैटि प्वांइट बना है और बहुत सारे पर्यटको के लिए जल क्रीड़ा के लिए संयत्र मौजूद हैं। लेकिन उसे आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है और उसे कैसे रिस्टोर किया जा सकता है तथा उसे कैसे अच्छे से चलाया जा सकता है। उस दृष्टि से इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। उसके साथ उपाध्यक्ष महोदय मैं देख रहा था कि इस बजट में जिला कुल्लू

के अन्दर 272 करोड़ की लागत से नेचर पार्क महोल से बिजली के बीच हाईब्रीड एन्युटी मोडल पर एक 3.2

19.02.2024/1830/बी.एस./ए एस/-2

किलोमीटर लंबे रोपवे का कार्य आरंभ किया जाएगा जिसमें 50 प्रतिशत अंश राज्य सरकार देगी। मैं आज ही देख रहा था कि यदि सरकार इस प्रोजैक्ट को लगाने के लिए गंभीर होती तो वहां पर जो वहां घाटी के लोग हैं वे सब आंदोलित हैं कहीं-न-कहीं कोई दिक्कत है। मैं सरकार से चाहूंगा कि इस पर पहल करें और जो लोग हैं उनको वार्ता के लिए बुलाएं ताकि वहां पर अच्छा रोपवे सौहार्दपूर्ण वातावरण में लग सके और लोगों का विरोध इस पर न हो। पिछले बजट में तो लिख दिया गया था कि इसे 172 करोड़ रुपये से आरंभ किया जाएगा परंतु धरातल में आज भी कुल्लू के अन्दर इसे लेकर आंदोलन हो रहा है। मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इस मामले में स्वयं हस्क्षेप करें और इसके लिए साकारात्मक सोच रखें। ताकि देव समाज को भी इसमें कोई दिक्कत न आए।

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

19.02.2024/1835/डी0टी0/ए0एस0/1

श्री सुरेन्द्र शौरी जारी...

यह रोपवे वहां पर सफल हो और इसका काम अच्छे से चले।। उपाध्यक्ष महोदय, मैं पिछले वर्ष 2023-24 के सरकार के द्वारा प्रस्तुत बजट के व कांग्रेस पार्टी के द्वारा चुनाव के दौरान कांग्रेस प्रतिज्ञा पत्र को पोलिसी दस्वावेज के रूप में अपनाने हेतु उस बजट में कहा गया था कि उसका अनुसरण करते हुए हम कृत संकल्प हैं कि जो गारंटियां हमने दी थीं, उन्हें हम पूरा करेंगे। लेकिन हम क्या देख रहें हैं? हम देख रहे हैं कि जो बजट वर्ष 2024-25 का के लिए सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है इस बजट में उन गारटिंयों का कहीं भी उल्लेख नहीं हैं। शायद सरकार को यह लग रहा होगा कि प्रदेश की जनता इन गारंटियों को भूल गई है। लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि यह प्रदेश की जनता

के साथ धोखा है, क्योंकि इस बार भी उन गारटियों का कहीं-न-कहीं इस बजट में जिक्र जरूर होना चाहिएद था। कहा तो यह गया था कि पहली कैबिनेट में इन गारंटियों को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। चुनाव के दौरान जब एक कांग्रेस नेता से पत्रकारों ने पूछा कि कांग्रेस पार्टी जो गारटिंयां दे रही है इन गारंटियों के लिए बजट कहां से आएगा, उसका लाइव वीडियो हमारे पास हैं, उन्होंने कहा कि यह चिंता आप छोड़िए, जैसे ही हम सत्ता में आएंगे दस दिन के अन्दर हम बजट भी लाएंगे और इन गारंटियों को धरातल पर भी उतारेंगे। लेकिन आज क्या हुआ, आज हम क्या देख रहें हैं? इसलिए इस प्रतिज्ञा पत्र को पिछली बार सरकार के द्वारा जब बजट के अन्दर रखा गया था तो मुझे लगता था कि सरकार इनको अवश्य पूरा करेगी और सरकार को करने भी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश के युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया है। आज हम देख रहे हैं कि पूरे हिमाचल प्रदेश का कोई ऐसा वर्ग नहीं हैं जो निराश न हो और जो अपने आप को असहज महसूस नहीं कर रहा। हम देख रहे हैं कि हर वर्ग कहीं-न-कहीं रोष व आंदोलन में हैं। शिमला की सड़कों में इस विधान सभा के सत्र के दौरान भी हमने देखा बहुत सारे आंदोलनकारी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। जिसका जिक्र यहां हमारे कई पूर्व वक्ताओं ने भी किया परन्तु सरकार उसमें गंभीर नहीं हैं। सरकार को उन्हें वार्ता के लिए बुलाना चाहिए और उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए।

19.02.2024/1835/डी0टी0/ए0एस0/2

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप अपनी गारंटियों को, जनता से किये गये वायदों को पूरा करें और इस बजट के अंदर जो आपने कहा है उनको भी निश्चित समय में पूरा करें। यहां मैं कुछ पंक्तियां शेर के माध्यम से कहना चाहूंगा कि:

चुनावों में झुठे वायदे करके आप मुकर कर चले गये।
इस बार भी बजट में आप अपने गुण गा कर चले गये,
कैसे सोच लिया जनता अब माफ करेगी।

इस बार लोक सभा चुनावों में यह प्रदेश की जनता आपको जड़ से साफ करेगी।

अगर आपने इन गारंटियों को जल्द ही पूरा नहीं किया। लोगों के साथ किये गये वायदों के लिए कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई तो जनता निश्चित रूप से आपको जड़ से साफ करेगी। आज इस प्रदेश का गौ-पालक, किसान अपने आपको ठगा हुआ महसूस कर रहा है। चुनावों के दौरान आपने कहा कि गाय का दूध हम 80 रूपये प्रति लीटर खरीदेंगे और भैंस का दूध 100 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से लेंगे। लेकिन अभी आपने बजट में कहा कि गाय का दूध 38 रुपए से 45 रुपए और भैंस का दूध 47 रुपए से 55 रुपए कहां गया वह 80 और 100 रुपए झूठ क्यों बोला था। किसानों से कहा था कि गोबर खरीदेंगें। इस बजट में गोबर का तो इसमें कोई जिक्र ही नहीं हैं। मैं कहना चाहूंगा कि आप इसमें गंभीर नहीं हो। इस प्रदेश के अंदर पिछले 5-6 सालों से एक नई क्रांति आई है कि बहुत सारे किसान प्राकृतिक खेती के साथ अपनी खेती कर रहे हैं। आपने इस बार के बजट में देश भर में जो सुभाष पालेकर जी के नाम से खुशाहल खेती, खुशाहल किसान योजना चल रही थी और वह योजना

19-02-2024/1840/डी.सी.-एन.जी/1

श्री सुरेन्द्र शौरी.....जारी

पूरे प्रदेश के अंदर लोगों के बीच में लोकप्रिय हो रही थी, उस योजना का नाम बदल कर 'राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्ट-अप योजना' रख दिया। मैं कहना चाहता हूं कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी इस देश के प्रधान मंत्री रहे हैं और उनके नाम से देश व प्रदेश में बहुत सारे संस्थान चल रहे हैं। हम सभी उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन इस प्रकार की छोटी राजनीति, तुष्टिकरण व सस्ती लोकप्रियता के लिए एक कृषि वैज्ञानिक के साथ नाइंसाफी करना ठीक नहीं है। जिस कृषि वैज्ञानिक ने अपना

पूरा जीवन कृषि व प्राकृतिक खेती के लिए लगाया और ऐसे व्यक्ति के नाम से चलाई गई योजना का नाम बदल कर सरकार ने प्रदेश की जनता, किसानों व कृषि वैज्ञानिकों के साथ अन्याय किया है। आपको इस योजना का नाम बदलने की क्या जरूरत आन पड़ी? यह सरेआम लोगों के साथ धोखा है। मैं कहना चाहता हूं कि स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी के नाम से और बहुत सी चीजें हो सकती हैं। श्री सुभाष पालेकर जी भारतीय जनता पार्टी के नेता या कार्यकर्ता नहीं हैं। वे इस प्रदेश व देश के किसानों के हित में काम करने वाले एक महान कृषि वैज्ञानिक हैं। जिस प्रकार की योजनाएं पूर्व मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार ने चलाई थीं उस प्रकार की योजनाएं हमें इस बजट में देखने को नहीं मिल रही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाने के लिए फिर से कहा गया है कि हम कृत संकल्प हैं। बंजार अस्पातल के लिए सरकार ने कहा था कि इसे आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाया जाएगा और आदर्श स्वास्थ्य संस्थान के नाम पर सरकार ने वहां केवल एनेस्थीसिया डॉक्टर को भेज दिया। वहां पर न तो ओ.टी. है और न ही उसका भवन बना है। मैं स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी और पूरी सरकार को कहना चाहता हूं कि ऐसी नीति बनानी चाहिए कि किस डॉक्टर की आवश्यकता किस अस्पताल में है और उसी के अनुसार डॉक्टर्स की तैनाती की जाए।

19-02-2024/1840/डी.सी.-एन.जी/2

कुल्लू अस्पताल एक जोनल अस्पताल है और वहां पर एनेस्थीसिया का डॉक्टर चाहिए तथा वहां पर डॉक्टर नहीं है। लेकिन बंजार अस्पताल की बिल्डिंग भी अभी कम्पलीट नहीं हुई है और उसका काम एक साल से ठप्प पड़ा हुआ है तथा वहां पर न तो कोई ओ.टी. है और न ही कोई अन्य स्टाफ है। मैं पूछना चाहता हूं कि वहां पर एनेस्थीसिया का डॉक्टर क्या करेगा? वहां पर मेडिकल ऑफिसर चाहिए और सरकार उसे उपलब्ध करवाए। आपकी सरकार ने 14 माह के कार्यकाल में मेरे विधान सभा क्षेत्र में 14 स्वास्थ्य संस्थानों को

बंद कर दिया। हम बार-बार चिल्ला-चिल्ला कर कह रहे हैं कि इन संस्थानों को वापिस खोल दीजिए और इसके लिए हमने बहुत सारे धरने-प्रदर्शन भी किए। लेकिन प्रदेश सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। हमने कईं बार मुख्य मंत्री जी से मिलकर भी कहा और मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि नीड बेस्ड पर खोलेंगे। हम उनसे कह रहे हैं कि आवश्यकता है लेकिन संस्थान अभी भी बंद ही पड़े हैं। जलोड़ी पास एक पर्यटन स्थल है और वहां पर बहुत सारे हादसे होते रहते हैं। हमारी सरकार के समय में वहां पर एक पी.एच.सी. खोली गई थी क्योंकि वहां पर डॉक्टर का होना बहुत जरूरी है नहीं तो आपातकाल में मरीज को बंजार जाना पड़ता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में ही इस प्रकार के पांच अन्य स्वास्थ्य संस्थान प्रदेश सरकार ने बंद कर दिए हैं। बंजार अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट होना चाहिए क्योंकि वहां पर मशीनें बंद पड़ी हुई हैं। पिछले बजट में कहा गया था कि सभी मेडिकल कॉलेजिज़ में पैट स्कैन होगा। कुछ समय पहले मेरे रिलेटिव को पैट स्कैन की आवश्यकता पड़ी तो मैंने आई.जी.एम.सी. में पता किया और उन्होंने मुझ से कहा कि हमारे पास पैट स्कैन नहीं है आपको पी.जी.आई. जाना पड़ेगा। वहां पर किसी भाई ने मेरे रिलेटिव को कहा कि शिमला में लिफ्ट के पास एक निजी संस्थान है और वहां पर पैट स्कैन हो जाएगा। मैं हैरान हुआ कि हिमाचल प्रदेश के 7 मेडिकल कॉलेजिज़ में पैट स्कैन नहीं है लेकिन शिमला के एक निजी संस्थान में पैट स्कैन होता है। मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार अपने 14 माह के कार्यकाल में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर गम्भीर नज़र नहीं आ रही है।

19-02-2024/1840/डी.सी.-एन.जी/3

पिछली बार बजट में कहा था कि हर मेडिकल कॉलेज में पैट स्कैन उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन आई.जी.एम.सी. या टांडा मेडिकल कॉलेज में ही पैट स्कैन उपलब्ध करवा देते तो हमें लगता कि प्रदेश सरकार लोगों के स्वास्थ्य को लेकर गम्भीर है लेकिन ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है।

(अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

अध्यक्ष महोदय, एक वर्ष में प्रदेश में कहीं पर भी राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल शुरू नहीं हो पाए हैं। हमने कहा कि इसके क्राइटेरिया को चेंज करना चाहिए क्योंकि मेरे विधान सभा में सारी भूमि फोरेस्ट की है और इसके लिए कहीं पर भी भूमि उपलब्ध नहीं हो पाएगी। पूरे विधान सभा क्षेत्र में कहीं पर भी जमीन मिलती है तो इस स्कूल को वहां पर खोलना जाना चाहिए

श्रीमती के.एस. द्वारा जारी.....

19.02.2024/1845/केएस/डीसी/1

श्री सुरेन्द्र शौरी जारी---

क्योंकि हर जगह सब-डिविज़न हैड क्वार्टर्ज़ या कंसीच्युएंसीज़ हैं, हैड क्वार्टर्ज़ से 5-10 किलोमीटर के अंदर भूमि उपलब्ध नहीं हो पाएगी।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर आत्मनिर्भरता की बात की गई कि हिमाचल आत्मनिर्भर होगा। इस प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि जब इस सरकार ने 14 हजार करोड़ रुपया ऋण लिया है उसके बावजूद भी कैसे कहा जा रहा है कि हम आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। चंद ठेकेदार और कुछ मित्र लोग ही आत्मनिर्भर हो रहे हैं। आम जनता के हित में इस बजट के अंदर कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

अध्यक्ष जी, हमारे यहां कुल्लू-मनाली के अंदर बहुत ज्यादा सब्जियां होती हैं। सेब होता है और अनार भी होता है। लाहौल-स्पिति का आलू वहीं आता है लेकिन कुल्लू में कोई कोल्ड स्टोर नहीं है और ना ही इसमें उसका कोई ज़िक्र किया गया है। हम चाहेंगे और हमने

प्लानिंग की बैठक में भी यह बात रखी थी कि कुल्लू के अंदर बंजार या बजौरा के आसपास कोल्ड स्टोर होना चाहिए। उसके लिए भूमि हम उपलब्ध करवाएंगे। वहां पर हमारी बहुत सारी फसलें, सब्जियां और अनार होता है इसलिए वहां पर इसकी ज़रूरत है।

अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने पिछले बजट में कहा था कि हम 25 हजार लोगों की भर्तियां करेंगे लेकिन बदले में कितने लोगों को नौकरी दी? 10 हजार से ज्यादा लोग आउटसोर्स से निकाले गए। वे बेरोज़गार निकाले गए जिनको नौकरी की बहुत ज्यादा ज़रूरत है। आखिर आउटसोर्स के लोगों को मिलता कितना वेतन है? उन्होंने भी अपना परिवार पालना है। मुझे लगता है कि यह सरकार बेरोज़गारों का बहुत ज्यादा शोषण कर रही है। उन निकाले गए कर्मचारियों को दोबारा से नौकरी में रखा जाना चाहिए। हमें उम्मीद थी कि आउटसोर्स वालों के लिए इस बजट में ज़रूर कोई नीति होगी लेकिन सभी ओउटसोर्स कर्मचारियों को इस बजट से निराशा ही हुई है। ना ही इसमें निकाले गए कर्मचारियों के बारे में कुछ कहा गया है कि उनको दोबारा से कैसे रख सकते हैं और ना ही जो आजकल आउटसोर्स में लगे हुए हैं, उनके लिए इसमें कोई नीति बनाने की बात की गई है।

19.02.2024/1845/केएस/डीसी/2

अध्यक्ष महोदय, सौर ऊर्जा के लिए पिछले बजट में कहा गया था 2 मैगावाट तक के लिए 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा? मैं पूछना चाहता हूं कि एक साल के अंदर ऐसे कितने लोगों को आपने यह अनुदान दिया और इसमें कितने लोग आए? मुझे लगता है कि जो नीतियां बने वे प्रॉपर एक सर्वे के तहत बने कि लोगों की क्या ज़रूरत है और उनको कैसे लाभ दिया जा सकता है, लोग उसमें कैसे ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कर सके, उस नाते नीति बनानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें एक योजना के बारे में पढ़ रहा था जो कि मेरी समझ से परे है। पेज नम्बर-37 के 101 नम्बर पैरा में लिखा है कि मुख्य मंत्री सुख आरोग्य योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी ऐसे कृषकों एवं वृद्धों

जो कि आयकर न दे रहे हो अथवा कोई पेंशन न ले रहे हों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा दी जाएगी। मैं कहना चाहता हूं कि 70 वर्ष से ऊपर सभी बुजुर्गों को सरकार द्वारा पैंशन दी जाती है। वे इस क्राइटेरिया में नहीं आएंगे तो आप आखिर किस वर्ग को लाभ देना चाह रहे हैं? सामाजिक सुरक्षा पैंशन तो सभी को मिलती है। इसलिए इस बात को थोड़ा क्लीयर किया जाए कि इस योजना का लाभ आखिर किसको मिलेगा? इसका स्पष्टीकरण दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय, मैं देख रहा हूं कि बजट में सीवरेज योजना के बारे में कहा गया कि इसको वर्ष 2024-25 में पूरा करेंगे।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी----

19.02.2024/1850/एवी/एचके/1

श्री सुरेन्द्र शौरी ------ जारी

मेरे बंजार की भी एक सिवरेज योजना है जिसकी ए0ए0 एण्ड ई0एस0 पूर्व मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी के कार्यकाल में मिल गई थी। परंतु उसके बाद वर्तमान सरकार उसका टेण्डर तक नहीं कर पाई और न ही उसके बारे में कोई प्लान बना पाई कि कहां-कहां से जाएगी। परंतु इसमें लिख दिया है कि उसको पूरा कर दिया जाएगा। मैं यह कहना चाहूंगा कि अधिकारियों को फील्ड से पूरी जानकारी लेनी चाहिए कि आखिर किस योजना में क्या समस्या है और उसको कैसे दूर किया जा सकता है, उसके बारे में तब जाकर बजट में मेंशन करना चाहिए।

इस बजट के माध्यम से प्रदेश के हर वर्ग को ठगा गया है। इस बजट से किसान-बागवान, बेरोज़गार, पत्रकार इत्यादि कोई भी खुश नहीं है। इनको तो छोड़िए आपके मंत्री और विधायक भी खुश नहीं हैं और ये लोग मजबूरी में इस बजट का समर्थन कर रहे हैं। इसलिए मैं इस बजट का समर्थन करने में असमर्थ हूं क्योंकि यह बजट निराशाजनक है। इस बजट के अंदर प्रदेश को आगे बढ़ाने हेतु कोई महत्वपूर्ण योजना नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

समाप्त

19.02.2024/1850/एवी/एचके/2

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्री सुरेश कुमार जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री सुरेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट अनुमानों पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री और व्यवस्था परिवर्तन के सूत्रधार श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने अपने कार्यकाल का यह दूसरा बजट पेश किया है। पिछले बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने व्यवस्था परिवर्तन के स्लोगन के साथ बजट पेश किया था और उस व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से इस प्रदेश के अंदर पिछले एक वर्ष में ऐसे अनेकों व्यवस्था परिवर्तन हुए जिनका सीधा लाभ प्रदेश की जनता को पहुंचा है। हमारे प्रदेश की जनता इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी और सरकार का धन्यवाद कर रही है। अगर हम बदलाव की बात करें तो इस प्रदेश में पिछले दिनों बहुत बड़ी त्रासदी आई थी और पूरा प्रदेश उस त्रासदी की चपेट में आया था। माननीय मुख्य मंत्री जी ने बड़ी सूझबूझ के साथ इस प्रदेश को उस आपदा से उभारा जिसके लिए देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारी सरकार और माननीय मुख्य मंत्री जी की प्रशंसा हुई है। हमारे मुख्य मंत्री जी और सरकार उसके लिए बधाई की पात्र है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने सुख आश्रय योजना का आगाज़ किया जिसका लाभ प्रदेश के उन बेसहारा बच्चों को मिल रहा है जिनके मां-बाप नहीं है और जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। सरकार ने ऐलान किया कि जिनके मां-बाप नहीं हैं उनके माता-पिता प्रदेश की सरकार है। आज हजारों बच्चें इस सुख आश्रय योजना का लाभ उठा रहे हैं।हमारी सरकार ने राजस्व अधिनियम, 1953 में संशोधन करके प्रदेश की जनता को एक बहुत बड़ी राहत दी है। यहां पर वर्षों से लोगों की जमीनों के मामले पटवारियों या तहसीलदारों के पास लंबित पड़े थे, आज 95,000 लोगों ने इसका लाभ प्राप्त किया है। उसमें चाहे तकसीम के मामले थे या इंतकाल के केस थे, आज प्रदेश की जनता इसके लिए भी माननीय मुख्य मंत्री जी और सरकार का धन्यवाद कर रही है। हमारी सरकार ने फॉरैस्ट क्लीयरेंस का सरलीकरण करते हुए इस प्रदेश में ऐसी व्यवस्था परिवर्तित की है कि जो मामले वर्षों से लंबित पड़े हुए

थे और जिनकी वजह से हमारी कई योजनाएं साकार नहीं हो पा रही थी तथा धरातल पर नहीं उतर पा रही थी, उसके लिए फॉरैस्ट क्लीयरेंस एक्ट में बदलाव किए जिसका प्रदेश की जनता व सरकार को लाभ प्राप्त हो रहा है। हमारी सरकार ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मद्देनज़र रखते हुए आबकारी नीति बनाई **टी सी द्वारा जारी**

19.02.2024/1855/टी0सी0वी0/एच0के0-1

श्री सुरेश कुमार .... जारी ।

जिसका लाभ प्रदेश को हुआ। हमारी सरकार ने वॉटर सैस लगाकर प्रदेश के आर्थिक संसाधनों को जुटाने का कार्य किया। जिसके साकारात्मक नतीजे देखने को मिल रहे हैं। इस वर्ष जो बजट मुख्य मंत्री जी ने पेश किया है, वह आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश का बजट है। इस बजट से गांव का आम परिवार का किसान और मजदूर उम्मीद रखता है कि इस बजट से उनकी आशाएं पूरी होंगी। मैं अभी सुन रहा था, हमारे विपक्ष के साथी विरोध कर रहे थे। विपक्ष का काम है विरोध करे लेकिन साकारात्मक विरोध हो। वह होना भी चाहिए लेकिन मात्र विरोध के लिए विरोध हो नहीं होना चाहिए। आज ऐसा सुनने को मिल रहा है कि हमारी सरकार ने कुछ नहीं किया और यहां पर जो कुछ हुआ वह इनकी सरकार ने किया और हम जो योजनाएं लेकर आ रहे हैं उनके बारे में कहते हैं कि ये योजनाएं तो केन्द्र से आई हैं। अगर केन्द्र सरकार की ऐसी योजनाएं होती और सारे अच्छे कार्य आपने किए होते तो आप उस तरफ नहीं बैठे होते, आप इस तरफ होते। यह साबित हो चुका है कि आपकी चाहे केन्द्र सरकार की योजनाएं थी या प्रदेश की योजनाएं थी जिनका डंका आप यहां जोर-जोर से पीट रहे हैं, आपकी योजनाओं को प्रदेश की जनता ने नकारा है। जो कार्य पिछले एक साल में हमारी सरकार ने किए हैं उसकी सराहना प्रदेश में हुई है। आज आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश की जो गाथा इस बजट के माध्यम से लिखी गई है उसमें ग्रामीण व्यवस्था को सुधारने का कार्य किया गया है। 'राजीव गांधी स्टार्टअप योजना', 'राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना' जिसमें 36 हजार किसानों को जोड़ने का लक्ष्य है। 'राजीव गांधी सोलर पावर स्टार्टअप योजना', राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना' ये सारी योजनाएं ऐसी हैं जिनका सीधा प्रभाव ग्रामीण अर्थव्यवस्था के ऊपर पड़ता

है और इनका सीधा लाभ प्रदेश की जनता को होने वाला है। यह हमारे बजट की खूबसूरती है जोकि मुख्य मंत्री जी ने पेश किया है। अभी हमारे विपक्ष के साथी कह रहे थे कि किसी को भी इस बजट का लाभ नहीं हुआ है। हम इनकी सारी चर्चा सुन रहे हैं तो हमारे विपक्ष के साथी मात्र गारंटियों की बात कर रहे हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि प्रदेश की जनता को गारंटियां हमने दी है और प्रदेश की जनता को हमारे ऊपर कोई शक नहीं है। हम प्रदेश की जनता के सामने वचनबद्ध है लेकिन राग हमारे विपक्ष के साथी अलाप रहे

19.02.2024/1855/टी0सी0वी0/एच0के0-2

हैं। हमने गारंटियां दी हैं और हम इन गारंटियों को पूरा करने का मादा रखते हैं। हमारे बजट के अंदर इन गारंटियों की झलक दिख रही है। आप कह रहे हैं कि हम लोक सभा के चुनाव में देखेंगे। लोक सभा के चुनाव में हम देखेंगे कि लोग हमारी गारंटियों को किस तरीके से लेते हैं। इस बजट के माध्यम से इन गारंटियों का आधार रख दिया गया है। आप सारी गारंटियों की बात कह रहे हैं। हमने पहली गारंटी जो प्रदेश के कर्मचारियों को दी थी उसको कर्मचारियों के लिए ओ0पी0एस0 देकर पूरा किया है और लगभग 1.50 लाख कर्मचारियों के जीवन को सुरक्षित किया है। आप उस गारंटी को भूल रहे हैं। उस पर भी आप प्रश्नचिन्ह लगा रहे हैं। आप लोग प्रदेश के कर्मचारियों की चिंता कर रहे हैं। प्रदेश के कर्मचारियों के बारे में बोलने का अधिकार आप खो चुके हैं। आज हमारे विपक्ष के साथी कह रहे हैं कि कर्मचारी गेट पर बैठे हुए हैं। ये बैठकर सुन तो रहे हैं आपकी सरकार में तो आपने इनको बैठने भी नहीं दिया था। आप लोगों ने इनके ऊपर पानी की बौछारें यही मारी थी। ये ठंड में बैठे थे और आपने इनके ऊपर पानी की बौछारें मारी थीं जब ये लोग ओ0पी0एस0 के लिए आए थे। जब बेरोजगार संघ आया था तो उसको भी आपने खदेड़ा था और उसमें एक व्यक्ति की टांग भी टूट गई थी। इसलिए कर्मचारियों के बारे में बोलने का अधिकार आप लोगों का नहीं है। आप लोग आज कर्मचारियों के हितैषी हो गए। प्रदेश का कर्मचारी जानता है कि कौन प्रदेश के कर्मचारियों का हितैषी है और कौन कर्मचारियों के लिए काम कर रहा है। आपको इसके ऊपर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।

एन0एस0 द्वारा जारी ।

19-02-2024/1900/एन0एस-वाई0के0/1

श्री सुरेश कुमार ------जारी

10,000 करोड़ रुपये की देनदारियां आप कर्मचारियों की छोड़ कर गए।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया एक मिनट बैठें। 7.00 बजे सायं सत्र का समय प्राप्त हो रहा है और अभी माननीय श्री सुरेश कुमार जी बोलेंगे और उसके बाद श्री डी0एस0 ठाकुर जी बोलेंगे।

(माननीय सदन की बैठक 7.30 बजे सांय तक बढ़ाई गई)

श्री सुरेश कुमार : मैं मुख्य मंत्री जी का इस बजट के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में एक नई पहले करते हुए कैंसर पीड़ित मरीजों को राहत देते हुए कीमो थैरेपी और कैंसर से संबंधित दवाओं को ग्रामीण स्तर के औषधालयों में उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया है। इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है? इन औषधालयों में कैंसर के डे-केयर सेंटर्ज खोलने का प्रावधान किया गया है। हमारी सरकार ने सभी वर्गों को इस बजट में राहत दी है। यहां पर ओ0पी0एस0 और 1500 रुपये की बात विपक्ष के साथी कर रहे थे। हमारी सरकार ने 1500 रुपये चरणबद्ध तरीके से देने का कार्य आरंभ किया है। विपक्ष वाले इन 1500 रुपये की चिंता कर रहे हैं लेकिन आप उन गारंटियों को भी याद कीजिए जो आपने 9 वर्ष पूर्व दी थीं। आपने 15 लाख रुपये देने, 2 करोड़ नौकरियां देने और बुलेट ट्रेन चलाने की बात की थी, आपने 100 स्मार्ट सिटीज बनाने की बात भी की थी। आपने कौन-सी गारंटियां पूरी की हैं? आप जरा जनता को जवाब दीजिए। आप हमारी गारंटियों पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। हमारी सरकार का अभी एक ही साल का समय हुआ है और हम गारंटियों को पूरा कर रहे हैं। आप गारंटियों के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाने के योग्य नहीं हैं। आप हमारे ऊपर ऐसा कोई इल्जाम नहीं लगा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, 680 करोड़ रुपये की स्टार्ट-अप योजना रोजगार से जुड़ी हुई है। यह ग्रामीण रोजगार से जुड़ी योजना है। 'हिम गंगा योजना' के ऊपर काम आरंभ हो चुका है। सरकार का नेशनल डेयरी डवल्पमेंट के साथ एम0ओ0यू0 हो चुका है। हम किसानों से दूध खरीदने की प्रक्रिया में आगे बढ़ चुके हैं और आप कह रहे हैं कि हमने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। आप आज यहां पर किसानों के हितैषी बनने

19-02-2024/1900/एन0एस-वाई0के0/2

की बात कर रहे हैं तो अध्यक्ष महोदय, हमें हंसी आती है। आज किसानों की बात विपक्ष के सभी साथियों ने की। ये भूल रहे हैं कि किसान आंदोलन पर दिल्ली में बैठे हुए हैं और आप किसानों के ऊपर अश्रु गैस के गोले फैंक रहे हैं। आज 3 किसान इस आंदोलन में अपनी जान गंवा चुके हैं और आप किसानों के हितैषी बनने की बात कर रहे हैं। किसानों की असली हितैषी कांग्रेस पार्टी है और बजट में इसकी झलक आपको दिखी होगी। आने वाले समय में किसानों के लिए दूध की योजना भी हम लेकर आ रहे हैं और दूध के ऊपर हमारी सरकार ने एम0एस0पी0 दी है। अभी कहा जा रहा था कि दूध 60 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। हमारी सरकार ने एम0एस0पी0 दी है। इससे ज्यादा रेट पर अगर किसी किसान का दूध बिकता है तो वह मार्केट में बेच सकता है लेकिन नहीं बिकता है तो उससे सरकार लेगी। एम0एस0पी0 का मतलब यही है। हमारा दूध 100 रुपये प्रति लीटर खरीदने का वायदा था वह जनता व किसानों के साथ है। इसके लिए मिल्क सोसायटीज़ गठित की जा रही हैं। आपको इसके ऊपर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, इस बजट में हर वर्ग को राहत देने का कार्य हुआ है। मैं खिलाड़ियों की बात करना चाहता हूं। जब हमारे खिलाड़ी बाहर खेलने के लिए जाते थे तो वे बसों में जाते थे। आज मुख्य मंत्री जी ने ए0 सी0 गाड़ियों के माध्यम से बाहर खेलने जाने की व्यवस्था की है। बच्चों की डाइट मनी को 500 रुपये किया गया है जो 200 से 250 रुपये हुआ करती थी। हर वर्ग को राहत पहुंचाने का कार्य इस बजट के माध्यम से किया गया है। यहां तक कि आप सब लोग जो बातें कर रहे हैं, आपका ख्याल भी मुख्य मंत्री जी ने रखा है। विधायक क्षेत्र विकास निधि को 2.20 करोड़ रुपये कर दी गई है। 'विधायक एच्छिक निधि' को 13 लाख रुपये से बढ़ाकर 14 लाख रुपये कर दिया गया है। विधायक प्राथमिकताओं के

वित्तीय पोषण की वर्तमान सीमा को 175 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 195 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

आर0के0एस0 द्वारा ------जारी

19.02.2024/1905/RKS/वाई के-1

श्री सुरेश कुमार...जारी

अब कौन-सा ऐसा वर्ग बचा है जिसे इस बजट में राहत न दी गई हो। पंचायती राज की सभी संस्थाओं को राहत दी गई हैं। आप इस बजट पर शंका जाहिर कर रहे हैं लेकिन मैं कहना चाहूंगा का कि यह बजट किसानों-बागवानों, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं का हितैषी है। मुख्य मंत्री जी ने हर वर्ग को राहत देने का कार्य किया है। मैं मानता हूं कि अभी कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन पर कुछ और ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। यहां पर राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल खोलने पर काफी चर्चा की गई। मेरे विधान सभा क्षेत्र भोरंज में डे-बोर्डिंग स्कूल का कार्य आरंभ हो चुका है। मुख्य मंत्री जी ने उस स्कूल के भवन का शिलान्यास कर दिया है और अब इसका निर्माण कार्य शुरू हो गया है। पांच राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूलों का निर्माण कार्य पूर्ण होने की प्रक्रिया में है जिनमें लाहड़ू, नगरोटा-बगवां, अमलैहड़, भोरंज और संगवाई के स्कूल हैं। 11 राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूलों की टेंडर प्रकिया जारी है। जहां पर जमीन उपलब्ध नहीं है वहां पर इन स्कूलों को स्थापित करने के लिए जमीन उपलब्ध करवाई जा रही है। आप अपने समय के अटल आदर्श विद्यालयों के बारे में बताएं कि आपने पिछले पांच सालों में ये स्कूल कहां खोले? इन संस्थानों को विकसित करने में समय लगता है। हमारी सरकार राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल खोलने की प्रक्रिया में आगे बढ़ी है और इन स्कूलों के माध्यम से हमारी सरकार ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों, गरीब परिवारों के बच्चों और आम परिवार के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने का कार्य करने जा रही है। मेरे साथी विनोद जी पोलीहाउस का जिक्र कर रहे थे। यह अच्छी बात है कि आप किसानों के लिए पोलीहाउस की स्कीम लेकर आए। आप कह रहे हैं कि पोलीहाउस स्कीम के लिए आपने कोई प्रावधान नहीं रखा है। जब

हमने यह स्कीम ही बंद नहीं की है तो जो प्रावधान आपकी सरकार ने किए थे वे वैसे ही चल रहे हैं। इसमें प्रश्न उठाने की कोई बात नहीं है। हमने यह स्कीम बंद नहीं की है। यह स्कीम जैसे थी वैसे ही चल रही है। हमने इस स्कीम में कोई फेरबदल नहीं किया है। आप शिक्षकों की भर्ती की बात कर रहे हैं। आप भी पांच साल सरकार में रहे आपने अपने कार्यकाल में कितने शारीरिक शिक्षक और शास्त्री भर्ती किए हैं? हमारी सरकार ने पी.जी.टी., शास्त्री और जे.बी.टी. के पद भरने की प्रक्रिया जारी की है लेकिन आप उन बातों को उठा रहे हैं जो आप पिछले पांच वर्षों में नहीं कर पाए।

19.02.2024/1905/RKS/वाई के-2

आपने अपने समय में तो कुछ नहीं किया लेकिन आप हमारे से हाथ में जौ जमाने वाली बात कर रहे हैं। हम एक वर्ष में ही सब कुछ कर दें ऐसा संभव नहीं है। इन सारे कामों को करने में वक्त लगता है और सरकार बड़ी संजीदगी के साथ हर कार्य कर रही है। हम पांच वर्षों के भीतर अपनी सभी गारंटियों को पूरा करेंगे। हम जनता की आशा के अनुरूप कार्य कर रहे हैं और इसका नतीजा आप आने वाले लोक सभा चुनाव में देख सकेंगे। आप ओ.पी.एस. की बात कर रहे हैं। हम प्रदेश के कर्मचारियों को आगाह करना चाहते हैं कि जो हमने ओ.पी.एस. लागू की है उस पर आज भी खतरा मंडरा रहा है। जब से छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, वहां ओ.पी.एस. बंद कर दी गई है। हम कर्मचारियों को आगाह करना चाहेंगे कि आप इनकी कुनीतियों से सचेत रहें ताकि जो कांग्रेस सरकार ने ओ.पी.एस. ने दी है ये इस पर डाका न डाल सकें। हम इसके लिए कर्मचारियों को जागरूक करना चाहते हैं। आप कर्मचारियों के हित की बात करने वाले लोग नहीं हैं। मैं मुख्य मंत्री जी के लिए एक शेर पढ़ना चाहूंगाः-

काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए,
कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए,
यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है,
आगाज इस कदर करो कि मिसाल बन जाए।

श्री बी.एस.द्वारा... जारी

19.02.2024/1910/बी.एस./ए जी/-1

श्री सुरेश कुमार जारी...

मुख्य मंत्री जी ने ऐसा कार्य किया है, जो बजट मुख्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है यह आम जनता की आशाओं का बजट है और इस बजट में समाज के हर वर्ग का ख्याल रखा गया है तथा इस बजट के आने वाले समय में दूरगामी परिणाम सामने आएंगे। मैं इस बजट का समर्थ करता हूं और इस बजट के लिए मैं सरकार का और मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री विनोद कुमार जी कुछ बोलना चाह रहे हैं।

श्री विनोद कुमार : अध्यक्ष महोदय, मेरे साथी, भाई सुरेश जी ने मेरा नाम ले करके कहा है कि यह जो पॉलीहाउस योजना हिमाचल प्रदेश में चली है, किसानों के हित में चली है। मैं कहना चाहूंगा कि भाई सुरेश जी पता कर लेना कि इस वित्तीय वर्ष में कितने पॉलीहाउस आपकी सरकार के दौरान लगाए। दूसरा, यह बजट बुक मेरे पास भी है और आपके पास भी है। किस स्कीम के तहत कितने बजट का प्रावधान किया गया है, बाकायदा उसमें लिखा होता है।

श्री सुरेश कुमार : माननीय सदस्य, आप भी वर्ष 2020-21 के बजट में क्या प्रावधान था उसे दिखा देना।

श्री विनोद कुमार : मैं भी दिखा दूंगा। बजट में लिखा होता है कि किस स्कीम के अंगेस्ट कितने बजट का प्रावधान है। आपको पता लग जाएगा कि आप कितने किसानों के हितैषी हैं! आपने रोजगार देने की बात कही । अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जल शक्ति विभाग के अंदर हमारी सरकार के समय 5000 मल्टीटास्क वर्कर्ज की भर्ती होनी थी और उसकी इन्टरव्यू भी हो गई थी परंतु आपसे एक वर्ष में उनका रिजल्ट तक नहीं निकला है जबकि आप नई भर्तियां देने की बात करते हैं।

19.02.2024/1910/बी.एस./ए जी/-2

अध्यक्ष : आदरणीय विनोद जी कृपया बैठ जाइए।

श्री विनोद कुमार : अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं कहना चाहता हूं कि आप कर्मचारियों के हितैषी होने की बात करते हैं। ...(व्यवधान)...आपके द्वारा एक साल के अन्दर उन्हीं कर्मचारियों को न टी.ए. दिया गया और वे किस्ते भी पैंडिंग पड़ी हैं तथा आप कर्मचारियों के हितैषी होने की बात करते हैं।...(व्यवधान)... उसके साथ ही अध्यक्ष महोदय, बिजली कर्मचारी हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों को सैलरी समय पर नहीं दी जा रही है और आप कर्मचारियों के हितैषी होने की बात कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर इन्हें जानकारी है तो उसके हिसाब से बात करें। जो भी मैंने कहा है वह तथ्य के आधार पर कहा है और डंके की चोट पर कहा है और उसमें एक भी बात गलत होगी तो विनोद कुमार विधान सभा सदस्यता से इस्तीफा दे देगा। यह मैं बताना चाहता हूं। आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपका आदर करता हूं, सम्मान करता हूं।

अध्यक्ष : आदरणीय विनोद जी बैठ जाइए।

श्री विनोद कुमार : हम जनता के हित के लिए लड़ेंगे। उसके लिए हमें चाहे जो भी करना पड़ेगा, विधान सभा के अन्दर लड़ाई लड़ने की बात होगी या विधान सभा के बाहर लड़ने की बात होगी तो हिमाचल प्रदेश की जनता के हितों के लिए लड़ा जाएगा।

Speaker: Nothing will go on record. Shri Vinod Kumar wanted to intervene only with regard to the polyhouse reference which was made by Mr. Sureshji. So that part of the statement is okay, rest will not be a part of the record.

Now the last Speaker, Hon'ble Member Shri D.S. Thakurji.

आदरणीय जय राम ठाकुर जी आप क्या कहना चाहते हैं।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में माननीय सदस्य को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, यदि सामने की तरफ से कोई प्रश्न खड़ा होता है तो इन्हें स्पष्टीकरण

देने का अधिकार है और इन्होंने कर्मचारियों के संदर्भ में जो बात कही उसमें हमें भी आपत्ति है।

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

19.02.2024/1915/डीटी/Aजी-1

श्री जय राम ठाकुर...जारी

मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि यहां से कौन कर्मचारियों के खिलाफ बोला गया? विपक्ष के किसी भी सदस्य ने कर्मचारियों के विरोध में नहीं बोला है। लेकिन आप बार-बार कह रहे हैं कि हम कर्मचारी विरोधी हैं। जो श्री विनोद कुमार जी ने अपनी बात कही है then that should be part of the record. I think it should not be expunged. इस पर आपको रिव्यू करना चाहिए, यह आपका अधिकार है लेकिन जो बात है ही नहीं उस पर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सत्तापक्ष और विपक्ष के लोग अपनी-अपनी बात रखेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि यह कार्यवाही का हिस्सा रहना चाहिए। इन्होंने ऐसा कोई शब्द इस्तेमाल नहीं किया है जो सदन की गरिमा के खिलाफ है।

Speaker: I will look into whatever has been said by Thakur Sahib. If it will be required, it will be a part of the record, and if not, then certainly it will not be a part of the record. I have already given my Ruling. Now I will request the Hon'ble Member Shri D.S. Thakurji.

श्री डी.एस. ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो वर्ष 2024-25 के लिए 17 फरवरी, 2024 को बजट प्रस्तुत किया है आपने मुझे इस पर बोलने के लिए समय दिया, आपका धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, बजट की चर्चा पर सत्तापक्ष और विपक्ष के लोग अपने-अपने सुझाव देते हैं और जो चीजें गलत हों उनको रोकने के लिए सरकार को आगाह भी करते हैं। जब मैंने इस बजट बुक को देखा तो मुझे लगा कि कुछ विषयों पर जनता को गुमराह किया जा रहा है। आप व्यवस्था परिवर्तन की बात तो कर रहे हैं लेकिन इस बजट को देखकर ऐसा लगता है कि यह सरकार इन 14 महीनों में व्यवस्था परिवर्तन करने में

पूरी तरह नाकाम रही है। कांग्रेस सरकार ने जो 10 गारंटियों दी थीं उन गारंटियों को पूरा करने के लिए इस बटज में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। इसमें न तो महिलाओं को 1500 रुपये देने का जिक्र किया है और न ही युवाओं को हर वर्ष एक लाख नौकरी देने की बात की है। किसान-बागवान और गरीबों के लिए कोई भी बड़ी घोषणा इस बजट बुक में नहीं की गई है। जो बजट बुक में लिखा गया है ये केवल लोगों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। इसमें

19.02.2024/1915/डीटी/Aजी-2

वही गारंटियां हैं जो मोदी सरकार ने हमारे गरीब, युवाओं और महिलाओं के उत्थान के लिए दी हैं। प्रदेश सरकार की ओर से इस बजट बुक में कुछ खास नहीं दर्शाया है। हमारे कर्मचारी भाइयों को सरकार ने ओ.पी.एस. तो दी पर यह बात भी कागजों तक ही सीमित है। कमचारियों को कोई एरियर नहीं मिला। हमारे पेंशनर्ज का पेंशन भत्ता भी एक साल से अधूरा पड़ा है। इससे पेंशनर्ज भी नाराज हैं। इस बजट से कोई भी वर्ग खुश नहीं है। सरकार शिक्षा संस्थानों को सुदृढ़ करने की बात कर रही है लेकिन प्रदेश के सभी स्कूलों में अध्यापकों की काफी कमी है। यहां पर माननीय मुख्य मंत्री और शिक्षा मंत्री जी भी बैठे हुए हैं।

श्री एन.जी. द्वारा... जारी

19-02-2024/1920/ए.एस.-एन.जी/1

श्री डी0 एस0 ठाकुर.....जारी

यहां पर मुख्य मंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी बैठे हुए हैं और मैं इनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि प्रदेश के सभी स्कूलों में अध्यापकों की काफी कमी है। कई स्कूलों में तो एक ही अध्यापक सभी कक्षाओं के बच्चों को पढ़ा रहा है। अगर आप अध्यापकों के पदों को नहीं भरेंगे तो हमारे बच्चों का भविष्य बहुत पिछड़ जाएगा। गरीब मां-बाप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बड़ी मुश्किल से स्कूलों में भेजते हैं लेकिन अध्यापकों की कमी होने के कारण बच्चे

अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। अगर मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत शिक्षा विभाग में कुल 1779 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 1295 पद भरे हुए हैं और 484 पद रिक्त पड़े हैं। मैं इन पदों को भरने के लिए कई बार आपसे आग्रह कर चुका हूं और यह विषय सरकार के ध्यान में भी कई बार ला चुका हूं। हर बच्चे को शिक्षित करना हमारा मूल कर्तव्य है लेकिन सरकार इस ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दे रही है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में स्थापित चार महाविद्यालयों में विभिन्न श्रेणियों के 31 पद रिक्त पड़े हैं। इसी तरह कुल 34 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में विभिन्न श्रेणियों के कुल 249 पद खाली पड़े हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में स्थापित कुल 19 राजकीय उच्च पाठशालाओं में विभिन्न श्रेणियों के 54 और कुल 26 राजकीय माध्यमिक पाठशालाओं में 40 पद रिक्त पड़े हैं तथा कुल 94 राजकीय प्राथमिक पाठशालाओं में 105 पद रिक्त पड़े हैं। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इतनी संख्या में पद रिक्त होंगे तो हम शिक्षा के क्षेत्र में कैसे उन्नती कर सकते हैं। मेरा सरकार से आग्रह रहेगा कि इन पदों को शीघ्रातिशीघ्र भरा जाए।

स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करूं तो पूर्व सरकार के समय हिम केयर योजना का लाभ गरीब मरीजों को मिलता था। लेकिन आज सरकार की यह स्थिति है कि हिम केयर योजना की देनदारियां देने में भी सरकार असफल रह रही है

19-02-2024/1920/ए.एस.-एन.जी/2

जिससे गरीब लोग बहुत परेशान हैं और लोगों को अपना उपचार करवाने में काफी परेशानियां आ रही हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में डॉक्टर्ज और पैरा-मैडिकल स्टाफ के काफी पद खाली पड़े हैं। इन परिस्थितियों में लोगों को अपना उपचार करवाने के लिए प्रदेश से बाहर जाना पड़ रहा है। मेरा आग्रह है कि प्रदेश सरकार जल्द-से-जल्द प्रदेश के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में इन पदों को भरने का काम करे ताकि लोगों को उनके नजदीकी

अस्पतालों में ही अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। मेरे विधान सभा क्षेत्र के नागरिक अस्पताल किहार और सलूणी में भी काफी डॉक्टर्ज़ के पद रिक्त पड़े हैं। मेरा आग्रह है कि इन पदों को शीघ्र भरा जाए ताकि हमारे दूर-दूराज के लोगों को अपना उपचार करवाने के लिए इधर-उधर न भटकना पड़े। मेरे विधान सभा क्षेत्र डलहौजी में स्वास्थ्य संस्थानों में कुल 165 पद रिक्त पड़े हैं जिनमें से एम.ओ. के 17 पद रिक्त पड़े हैं। इसके अलावा नर्सिस, फार्मासिस्ट, टेक्निकल, पैरा मेडिकल स्टाफ आदि श्रेणियों के कुल 148 पद रिक्त पड़े हुए हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से हमारा क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है और जिला चम्बा भी पिछड़े जिलों में आता है इसलिए यहां पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। डलहौजी विधान सभा क्षेत्र काफी दूर-दराज़ का क्षेत्र है और काफी बड़े ऐरिया में फैला हुआ है। मेरे विधान सभा क्षेत्र की पी.एच.सी. तिलका में पिछले 6 माह से कोई भी एम.ओ. नहीं है। इस पी.एच.सी. में 10 पंचायतों के लोग अपना उपचार करवाने के लिए जाते हैं। एक माह पहले स्थानीय निवासी श्री चमारू राम जी तीन दिन तक वहां पर भूख हड़ताल पर बैठे थे। फिर विभाग द्वारा किहार व सलूणी से दो-दो दिन के लिए तिलका पी.एच.सी. में डॉक्टर को भेजा जा रहा है। जबकि किहार में एम.ओ. की आठ पोस्टें हैं जिसके अगेंस्ट दो डॉक्टर नियुक्त हैं। इसी प्रकार सिविल हॉस्पिटल सलूणी में एम.ओ. की आठ पोस्टें हैं

श्रीमती के.एस. द्वारा जारी.....

19.02.2024/1925/केएस/एएस/1

श्री डी0एस0 ठाकुर जारी---

और सलूणी में सिविल हॉस्पिटल में 8 पोस्टें हैं और एम.ओ. दो हैं। इस तरह से स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हमारे यहां आप एम.ओ. नहीं भेजेंगे और लोगों को स्वास्थ्य लाभ नहीं मिलेगा तो हमारी डलहौजी के दूर-दराज के क्षेत्र की जनता को स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए चम्बा जाना पड़ता है। मेरा निवेदन है कि तेलका में तुरंत एक एम.ओ. की नियुक्ति की जाए। सिविल हॉस्पिटल सलूणी में 8 एम.ओ. के पद के विरुद्ध 2 ही एम.ओ. की पोस्टें भरी

गई हैं इसलिए वहां भी 6 एम.ओ. और भेजे जाएं। इसी तरह किहार में भी 8 पोस्टों के अगेंस्ट 2 एम.ओ. हैं अतः वहां भी 6 डॉक्टर भेजे जाए। डलहौजी सिविल हॉस्पिटल में हमें आपने डॉक्टर तो दे दिए। वहां 12 पद सेंक्शंड हैं जबकि डॉक्टर 16 दे दिए लेकिन ऑप्रेशन के लिए हमारे मरीजों को चम्बा या टांडा मैडिकल कॉलेज जाना पड़ता है क्योंकि ना तो वहां टूल किट है जिससे डॉक्टर ऑप्रेशन कर पाएं और ना ही वहां कोई टैक्निकल स्टाफ है। इसलिए मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि डलहौजी विधान सभा क्षेत्र में जितने भी एम.ओ. या नर्सिज़ के पद खाली हैं उन्हें भरा जाए। आपने आउटसोर्स के लिए 12 हजार रुपये तो प्रति महीना कर दिया लेकिन जो लोग कोरोना काल में सेवाएं दे रहे थे, वे आपने घर बैठा दिए और उनके परिवार का गुजारा कैसे होगा वे कैसे अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे या उनकी ट्रेनिंग करवा पाएंगे? आपसे निवेदन रहेगा कि जिन आउटसोर्स कर्मचारियों को आपने घर बिठाया है, तुरंत उनको आप नियुक्ति दें ताकि लोगों को स्वास्थ्य लाभ भी मिले और जिन्होंने कोरोना काल में इतनी मुश्किल में लोगों का साथ दिया है, उनको आप रोज़गार उपलब्ध करवाएं।

पर्यटन की दृष्टि से आपने जिला चम्बा, डलहौजी जो कि पर्यटन नगरी है और जो पूरे देश में पर्यटन के मानचित्र पर है, उसके लिए कोई खास ज़िक्र नहीं किया गया। डलहौजी में रोपवे की बहुत डिमांड है ताकि हमारे जो टूरिस्ट हैं, उनका वहां एक दिन का ठहराव हो सके।

अध्यक्ष जी, सड़कों की हालत बहुत खस्ता है। सड़कों के लिए भी आप बजट का प्रावधान करें ताकि पर्यटक वहां आ सके और सरकार के आय के साधन भी बढ़े और हमारे बेरोजगार युवाओं को रोज़गार के साधन भी मिले।

19.02.2024/1925/केएस/एएस/2

सड़कें किसी भी देश या प्रदेश की जीवन रेखाएं होती हैं। जिस जिला से मैं सम्बन्ध रखता हूं वहां सड़कें ही एक मात्र साधन है जिसने इस दूर-दराज क्षेत्र को प्रदेश से जोड़ रखा है किन्तु वर्ष 2023 में आई आपदा ने इन जीवन रेखाओं को काफी नुकसान पहुंचाया है जिससे हमारी आर्थिकी पर काफी प्रभाव पड़ा है। लोगों को अपना सामान मंडियों तक

पहुंचाने के लिए काफी समस्याएं आ रही हैं। लेकिन सरकार ने अभी तक इन सड़कों को रिस्टोर करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में ऐसी बहुत सी सड़कें व पुल हैं जिन्हें जनहित के लिए रिस्टोर करना अति आवश्यक है। अतः मेरा माननीय मुख्य मंत्री व मंत्री जी से आग्रह है कि इन सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त किया जाए ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े।

(माननीय सदन की बैठक का समय सात मिनट के लिए बढ़ाया गया)

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी----

19.02.2024/1930/एवी/डी सी/1

श्री डी0 एस0 ठाकुर : हमने गत वर्ष जिन-जिन योजनाओं को विधायक प्राथमिकता में स्वीकृति हेतु डाला था वे योजनाएं आज भी अधर में लटकी हुई हैं। इन योजनाओं की न तो कोई डी0पी0आर0 तैयार हुईं और न ही एफ0सी0ए0 व एफ0आर0ए0 केसिज की क्लीयरेंस हुई है। फिर आप कहते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन की सरकार है जबकि इन कार्यों को धरातल पर उतारना बहुत ही जरूरी है। परंतु वर्तमान सरकार भेदभाव के तरीके से कार्य कर रही है और आप कहते हैं कि यह व्यवस्था परिवर्तन है।

अगर डलहौजी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत विद्युत विभाग की बात की जाए तो वहां पर कई नये घर ऐसे हैं जिन्हें एक वर्ष से मीटर उपलब्ध नहीं करवाए जा रहे हैं और लोग इस कारण से काफी परेशान हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो पुराने ट्रांसफॉर्मर्ज स्थापित किए गए हैं वे बार-बार खराब हो रहे हैं जिन्हें ठीक करवाने के लिए विभाग डमटाल ले जाता है। विभाग एक तरफ तो इनको ठीक करवाने पर बार-बार खर्च कर रहा है और बावजूद उसके पुराने ट्रांसफॉर्मर्ज ज्यादा दिन तक नहीं चल पाते। मेरा मुख्य मंत्री जी से अनुरोध रहेगा कि वहां पर नये ट्रांसफॉर्मर्ज भेजे जाएं ताकि बार-बार के खर्चे से बचा जा सके और लोगों को बिजली की समस्या से भी नहीं जूझना पड़ेगा।

डलहौजी विधान सभा क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार की ओर से 28 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त हुई थी। वह 28 करोड़ रुपये की राशि मेरे विधान सभा क्षेत्र में खर्च होनी थी। उसके अंतर्गत बनीखेत और तेलका में दो सब-स्टेशन्ज हेतु स्वीकृति मिल गई है परंतु आज दिन तक उसका टेण्डर नहीं हो पाया है। विभाग पिछले 6 महीनों से उसका टेण्डर नहीं कर पाया। इस व्यवस्था परिवर्तन के चलते लोगों को बिजली की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। अगर वह टेण्डर लग जाता और 33 के0वी0 सब-स्टेशन बन जाते तो हमारी विधान सभा क्षेत्र में बिजली की समस्या कम हो जानी थी। अतः मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह रहेगा कि अधिकारियों को निर्देश देकर इन दोनों 33 के0वी0 सब-स्टेशन्ज का काम जल्दी शुरू करवाया जाए। मेरे विधान सभा के दूरदराज क्षेत्र के गांवों में बिजली के पुराने खम्भे हैं। वहां के लिए नये खम्भे मिलना बहुत ही आवश्यक है। इसके अतिरिक्त सर्विस वायर की रिक्वायरमेंट भी बहुत जरूरी है, विभाग ये सारी चीजें जल्दी-से-जल्दी मुहैया करवाएं ताकि लोगों को बिजली की समस्या का सामना न करना पड़े। मेरा मुख्य मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि इस व्यवस्था को ठीक किया जाए ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। वर्तमान में हमें देश के

19.02.2024/1930/एवी/डी सी/2

दूसरे राज्यों से बिजली की खरीद करनी पड़ रही है। मैं यहां पर अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करना चाहूंगा। मेरे वहां बांधल में विद्युत विभाग की ओर से 5 मेगावाट का प्रोजैक्ट मंजूर हुआ था। उस प्रोजैक्ट का काम वर्ष 2012 में शुरू हुआ था परंतु वर्ष 2015 के बाद उसका आगे कोई काम नहीं हुआ। मैंने इस संदर्भ में पिछले विधान सभा सत्र के दौरान भी प्रश्न लगाया था जिसके उत्तर में विभाग की ओर से कहा गया था कि उसका 50 प्रतिशत काम हो चुका है। उस प्रोजैक्ट के कारण लोगों की जमीनें भी खराब हुईं और वहां जो नौजवानों को रोज़गार मिलना था, वह भी नहीं मिला। उसमें काम करने वाली कंपनी सब्सिडी खाकर वहां से गायब हो गई। मेरा मुख्य मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि बांधल के उस 5 मेगावाट के प्रोजैक्ट को पूरा करवाया जाए ताकि हमारे युवाओं को रोज़गार के साधन मिले और साथ में सरकार को इन्कम हो।

अगर जल शक्ति विभाग की बात की जाए तो हालांकि उस समय मैं विधायक नहीं था। परंतु मेरे विधान सभा क्षेत्र में पानी की किल्लत को देखते हुए मेरे आग्रह पर पूर्व में श्री जय

राम ठाकुर जी के नेतृत्व में रही हमारी भाजपा की सरकार ने वहां के लिए 5-6 बहुत बड़े-बड़े प्रोजैक्ट दिए थे। उसमें एक साल पहले सलूणी-मझींर-सुरगाणी का 56 करोड़ रुपये का प्रोजैक्ट पूरा हो गया है तथा उस प्रोजैक्ट का उद्घाटन भी हो गया है।

टी सी द्वारा जारी

19.02.2024/1935/ टी.सी.वी/डी.सी./-1

श्री डी.एस. ठाकुर जारी...

परंतु इसकी पानी की सप्लाई की व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है। उसमें कंपनी ने जो काम करवाया है उसके रख-रखाव की जिम्मेवारी एग्रीमेंट में पांच वर्ष तक उनकी ही थी। परंतु आज तक उनका आदमी न तो उस स्कीम में काम करता है और न ही पाइपें चेंज हो रही हैं। जब विभाग से बात की जाती है तो कहते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है। (घंटी...)

कैसे सोच लिया कि जनता अब माफ करेगी।
इस बार लोक सभा के चुनाव में जनता आपको जड़ से साफ करेगी।

अध्यक्ष महोदय, इस बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका मैं समर्थन करूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष : ठाकुर साहब, मैंने इसलिए समय नहीं दिया था कि आप ऐसा शेर पढ़ करके सुनाओ। मैंने तो इसलिए मौका दिया था कि आप कोई अच्छा शेर बोलते।

अब माननीय सदन की बैठक मंगलवार, 20 फरवरी, 2024 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171004 **यशपाल शर्मा**
दिनांक 19 फरवरी, 2024 **सचिव।**